



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022020-215872  
CG-DL-E-02022020-215872

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 33]	नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2020/माघ 12, 1941
No. 33]	NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2020/MAGHA 12, 1941

---

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2020

**फा. सं. 2(2)-बी(डी)/2020.**—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

**बजट 2020-2021**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का भाषण

1 फरवरी, 2020

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं, वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

प्रस्तावना

मई 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा सरकार बनाने के लिए बड़ा जनादेश प्राप्त किया। उनके नेतृत्व में, नए जोश के साथ हम विनम्रता और समर्पण की भावना से भारत की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. निःसंदेह भारत की जनता ने न केवल राजनैतिक स्थिरता के लिए अपना जनादेश दिया अपितु हमारी आर्थिक नीति पर भी भरोसा किया। यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। केवल उच्च वृद्धि से ही हम उसे हासिल कर सकते हैं और हमारे युवाओं को लाभप्रद एवं सार्थक रोजगार दे सकते हैं। हम अपना व्यवसाय नवोन्मेषी, स्वस्थ और सम्पन्न बनाएं और यह प्रौद्योगिकी के उपयोग से सही अर्थ में "जीवन सहज" बनाने के लिए हो।

3. शताब्दी के बदलाव के माहौल में जन्मे हुए, आज के युवकों के लिए, बेहतर जीवन की खोज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक महिला जो अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती है और समाज में अपनी पहचान चाहती है, समाज के असुरक्षित क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए-इस बजट का लक्ष्य आपकी महत्वाकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करना है।
4. हम, नई प्रौद्योगिकी के मन्द हवा के झोंकों से मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था का परिदृश्य खोलना चाहते हैं। यह मजबूत भारत एक संरक्षण समाज बने और अपने नागरिकों के बीच कमजोर, वृद्ध एवं असुरक्षित जन की देखभाल करेगा।
5. वर्ष 2014-19 के दौरान, हमारी सरकार ने अभिशासन में मूल-चूल परिवर्तन किया है। दो फोकस इस परिवर्तन की विशेषता है: बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेशी विकास।
6. अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं और इनसे वृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है। मुद्रास्फीति सुनियंत्रित हो गई है। बैंकों को विगत दशक के संचयित ऋणों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है और उनका पुनः पूंजीकरण किया गया। कंपनियों को आईबीसी के जरिए उबरने के लिए सम्मानजनक रास्ता मुहैया कराया गया। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए।
7. संरचनात्मक सुधारों में, माल और सेवा कर हमारे देश में ऐतिहासिक रहा है। इसका मुख्य वास्तुकार आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं दूरदर्शी नेता स्वर्गीय श्री अरूण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। जीएसटी लागू करते समय उन्होंने कहा था उसे मैं दुहराती हूं: "यह भारत ही होगा जहां केन्द्र और राज्य साझी सम्पन्नता के सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए सद्भावनापूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। संवैधानिक संशोधन की मतैक्य और जीएसटी परिषद की सर्वसम्मति यह उजागर करती है कि राष्ट्र के हित के लिए भारत संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठ सकता है। जीएसटी से न तो राज्य और न ही केन्द्र अपनी सम्प्रभुता खोता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष करों के संबंध में निर्णय लेने पर अपनी सम्प्रभुता को पूल करेंगे।"
8. ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार के लिए इस दूरदर्शिता को सही साबित करते हुए माल और सेवा कर धीरे-धीरे कर का रूप ले रहा है जिसने देश को आर्थिक रूप से एकीकृत किया है। इसने अनेक करों और उपकरों को एक कर में मिला दिया है और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को सुविधाजनक बनाया है। इसके परिणामस्वरूप संभार तंत्र और परिवहन सेक्टरों में दक्षता आई है। जीएसटी में चेक पोस्टों को हटाने के कारण ट्रकों के टर्न अराउंड समय में 20% तक गिरावट आई है। भयावह इंस्पेक्टर राज का भी अंत हो गया है।
9. बढ़ी हुई आरंभिक अवस्था और संरचना सीमितताओं के परिणामस्वरूप एमएसएमई को काफी लाभ हुआ है। लगभग प्रत्येक वस्तु पर प्रभावी कर मामलों में काफी कमी आई है। अनेक दर कटौती के जरिए ₹1 लाख करोड़ का वार्षिक लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है। इससे समग्र कर मामलों में 10% की कमी आई है। कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार अब अपने मासिक खर्च में लगभग 4% की बचत करता है।
10. परिपक्व होने के इस चरण में जीएसटी को कतिपय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह स्वाभाविक था क्योंकि परिवर्तन हतोत्साहित हो रहा था। इस परिवर्तन के दौरान जीएसटी परिषद समस्याओं का समाधान सक्रिय रूप से कर रही थी। पिछले दो वर्षों में हमने 60 लाख से अधिक नए करदाताओं को जोड़ा है, कुल लगभग 40 करोड़ विवरणियां फाइल की गईं, 800 करोड़ इनवाइसेज अपलोड किए गए और 105 करोड़ ई-वे बिल दिए गए। हितधारकों के साथ व्यापक रूप से मिलकर काम किया गया। 1 अप्रैल, 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जा रही है। नई प्रणाली के संबंध में हाल ही में आयोजित राष्ट्रव्यापी आपसी बात-चीत को अत्यधिक प्रतिक्रिया मिली थी।
11. पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार चिंता व्यक्त की थी कि कल्याणकारी स्कीमों का लाभ जरूरतमंद नागरिकों तक नहीं पहुंच रहा था-आम और जरूरतमंद नागरिक को भेजा गया प्रत्येक रुपये का केवल 15 पैसे ही उसे मिलता था। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" द्वारा मार्गदर्शित होकर हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी गति कई गुना बढ़ाई और ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को ऊंचाइयों पर ले गए जो निर्धनों और वंचितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मैं उदाहरण के लिए केवल कुछ स्कीमों की सूची देना चाहती हूं: (क) कल्याणकारी स्कीम, जिनमें डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) शामिल है; (ख) स्वच्छता और जल के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं के उपायों और निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान में (ग) आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य देखभाल (घ) उज्ज्वला और सौर विद्युत के जरिए स्वच्छ ऊर्जा; (ङ) असुरक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन क्रेडिट सहायता, बीमा सुरक्षा और पेंशन स्कीम (च) ब्राडबैंड और यूपीआई से डिजिटल प्रवेश; (छ) पीएमएवाई के माध्यम से सस्ता आवास। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं, वैश्विक रूप से इनकी सराहना की गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के लिए बेंचमार्क हैं।
12. पूर्व से चली आ रही ऐसी व्यवस्था में बदलाव आया जिसमें कुछ व्यक्तियों को अधिकांश लाभों से वंचित रखा जा रहा था और इसकी जनता द्वारा बड़ी सराहना की गई है। इसके बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम हुए। हम 1950 के दशक में 4% से थोड़ा ही ऊपर से 1980 और 1990 के दशकों में 6% की वृद्धि दर से आगे बढ़े हैं। फिर भी 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4% हो गई और औसत मुद्रास्फीति 4.5% पर कम थी। यह ध्यान देने लायक है कि पिछली सहस्राब्दी के विगत दो दशकों में मुद्रास्फीति 9% के आस-पास थी और 2009-14 के दौरान यह 10.5% के दायरे में थी।

13. अब हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2009-14 के दौरान आए 190 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2014-19 के दौरान 284 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। जीएसटी ने प्रणाली में बहुत सी बाधाओं को दूर किया और एक बार जब समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, तब यह अधिक आधुनिक, प्रगामी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कराधान प्रणाली होगी। केन्द्रीय सरकार का ऋण जो हमारी अर्थव्यवस्था के अनिष्ट का कारण रहा है, मार्च 2014 में 52.2% के स्तर से घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7% पर आ गया। 2006-16 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में समर्थ था, जिसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए।

14. इस पृष्ठभूमि से हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी ताकि हम स्वास्थ्य, सम्पन्नता और खुशहाली के अगले स्तर पर मेढ़ककूद कर सकें। हम प्रत्येक नागरिक के लिए सहज जीवन हेतु प्रयास करेंगे।

15. मैं, इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूँ:

क) प्रौद्योगिकियों का प्रचुर प्रसरण, विशेषकर विश्लेषणात्मक, मशीन रोबोटिक्स, बायो-इंफोरमेटिक्स और आर्टिफिशल इन्टेलिजेंस

ख) भारत में 15-65 वर्ष, उत्पादक आयु वर्ग में इसकी जनता की संख्या अर्थात् अपने आप में सबसे अधिक है।

16. यह संयोजन समकालीन भारत के लिए विशेष है। विश्व भर में यदि वैश्वीकरण में कमी आ रही है, उसी तरह मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता पर भी वाद-विवाद हो रहा है। पिछले, पांच वर्षों में हमने जो प्रयास किए और हमारे युवकों की ऊर्जा, उत्साह और नवोन्मेष ऐसी चिंगारी है जिन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय उद्यमशीलता की भावना जिसने शताब्दियों से अनेक अवरोधों का सामना किया हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देते हैं। हम इस भावना को समर्थन देने और इसे अधिक बढ़ाने की आवश्यकता को जानते हैं।

17. यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बना है:-

**एक: महत्वाकांक्षी भारत** जिसमें समाज के सभी वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं।

**दो: सबके लिए आर्थिक विकास** जिसे प्रधानमंत्री के प्रबोधन "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" में दर्शाया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के कई कतरों में सुधार लाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इसमें निजी क्षेत्र के लिए अधिक गुंजायश होगी। दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे।

और

**तीन: हमारा संरक्षण समाज होगा** जो मानवीय और दयाभावना से भरा होगा। अन्त्योदय विश्वास का प्रतीक है।

18. भारत में डिजिटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है हमारा लक्ष्य है।

- डिजिटल गर्वनेस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना
- आपदा समुत्थान शक्ति के जरिए जोखिम न्यूनीकरण
- पेंशन और बीमा प्रवेश के जरिए सामाजिक सुरक्षा

इनमें से प्रत्येक पहल और उनके घटक अंतरराष्ट्रीय मानक के लिए बेंचमार्क होंगे और सूचकांकों की घोषणा जल्द की जाएगी।

19. मेरे परिचायक वक्तव्य का सारांश यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है। जैसाकि कुछ देर पहले कहा गया है, तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत ब्यौरा-महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और संरक्षण भारत फूलों के गुच्छ का फूल है, जो जीवन आसान बनाना रूपी फूल हैं। इस फूल के गुच्छे को पकड़ने के लिए दो हाथ हैं-एक, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति से संचालित अच्छा अभिशासन और दो, स्वच्छ और मजबूत वित्तीय सेक्टर।

20. पहले वर्णित तीन थीमें विषय मेरे बाद की प्रस्तुती के आधार हैं। वे उस फूल गुच्छ के फूल हैं जिसमें "जीवन आसान बनाने" की समग्र धारणा अंतर्निहित है और अभिशासन का स्तर उठाने की आवश्यकता जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कहा गया है। वित्त साधन और बाद में भाग ख में करों के संबंध में अध्याय बजट के आवश्यक नए आधार है, जो आगामी वर्ष और उसके बाद के लिए मार्गदर्शन देता है।

इसके पहले कि मैं तीन विषयों पर विस्तृत चर्चा करूँ मैं कश्मीरी में एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ:-

भेन वउन, गुलर मलीभाग ऊयव  
 डल मंर, डेलवन पभेस ऊयव।  
 नवखवन-धन हुन वसुन लभभाग ऊयव  
 धेन वउन, धेन वउन  
 भेन वउन, ननुवेन वउन।  
 - पंडित मीननष कैल

Saun Watan Gulzar Shalamaar Hyur

Dal Manz Pholvun Pamposh Hyuv

Navjavan-an-hund, Vushun Khumaar Hyuv

Myon Watan, Chyon Watan

Saun Watan, Nundbony Watan

(प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, सभी करते हैं, वह इस सुन्दर देश के लिए है।)

यह कविता पंडित दीनानाथ कौल द्वारा लिखी गई है।

#### महत्वाकांक्षी भारत

21. मैं (1) कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास (2) वेलनेस, जल और स्वच्छता तथा (3) शिक्षा और कौशल से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं पर बात करूंगी।

#### कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

22. हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में जिन किसानों ने ई-नाम पर अपना पंजीकरण किया है, ऐसे 1.65 करोड़ किसानों को बाजार कनेक्टिविटी का लाभ मिला है। हमने कुसुम के माध्यम से ऊर्जा प्रभुसत्ता और परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए इनपुट प्रभुसत्ता मुहैया कराई है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले 6.11 करोड़ किसानों के जीवन में उजाला किया है। कृषि सिंचाई योजना के जरिए दालों की फसल और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार पर फोकस करके देश की आत्म-निर्भरता में इजाफा किया है। किसानों को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त आय मुहैया कराने के प्रावधान को सीधे प्रधानमंत्री-किसान योजना के जरिए पूरा किया जाता है।

22(1). कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए कृषि बाजारों को उदार किए जाने की जरूरत है। कृषि और पशुधन बाजारों में पैदा हुई गड़बड़ियों को हटाए जाने की आवश्यकता है। कृषि के उत्पाद, औजार और कृषि संबंधी सेवाओं की खरीद के लिए प्रचुर निवेश की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में समर्थन और पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा मछली पालन जैसी कृषि आधारित गतिविधियों के लिए सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। किसान भंडारण, वित्तपोषण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को शामिल करते हुए एक समग्र समाधान चाहते हैं।

23. फसल उगाने के सुस्थिर पैटर्न को अपनाना और प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल करना हमारी योजना का अभिन्न हिस्सा है। यह सब और इससे अधिक को राज्यों के साथ कार्य करने और उनके सहयोग के माध्यम हासिल किया जा सकता है।

निम्नलिखित 16 कार्य बिंदु हमारे फोकस को दर्शाते हैं :

23(1). हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करते हैं :

- (क) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016
- (ख) मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 और
- (ग) मॉडल कृषि उत्पाद तथा पशुधन संविदा कृषि और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018

**23(2).** पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय हैं। हमारी सरकार पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव कर रही है।

**23(3).** जुलाई, 2019 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि "अन्नदाता" "ऊर्जादाता" भी हो सकता है। पीएम-कुसुम स्कीम से डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई है और उन्होंने अपने पम्प सेट सौर ऊर्जा से जोड़े हैं। अब, मैं स्टैंड अलोन और पम्प स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को यह सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव करती हूँ; इसके अलावा, हम अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पम्प सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए भी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी खाली पड़ी/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करने और उसे ग्रिड को बेचने में समर्थ बनाने की स्कीम आरंभ की जाएगी।

**23(4).** हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

**23(5).** भारत के पास कृषि भंडारण, शीत गृह, माल ढुलाई वैन की सुविधाओं की 162 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है। नाबार्ड इन्हें मापने और जिओ टैग करने की कवायद करेगी। इसके अलावा, हम मालगोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूटीआरए) के मापदंडों की तर्ज पर मालगोदाम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हमारी सरकार ब्लॉक/तालुक स्तर पर ऐसे कार्यक्षम मालगोदाम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुहैया कराएंगे। इसे हासिल किया जा सकता है, जहां राज्य भूमि की सुविधा दे सकते हैं और यह पीपीपी मॉडल पर हो। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) अपनी भूमि पर भी ऐसे भंडारण बनाएंगे।

**23(6).** बैकवर्ड लिंकेज के रूप में, ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे किसानों को एक अच्छी धारिता क्षमता मुहैया होगी और उनकी लाजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। महिला, एसएचजीएस अपनी धन लक्ष्मी की ओहदे को पुनः प्राप्त करेगी।

**23(7).** दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के जरिए "किसान रेल" चलाएगी/एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटरकृत कोच होंगे।

**23(8).** नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में अत्यधिक मदद मिलेगी।

**23(9).** बागबानी क्षेत्र ने 311 मिलियन मीट्रिक टन के अपने वर्तमान उत्पाद के चलते खाद्यान्नों के उत्पाद को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, हम उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं जो क्लस्टर आधार अपनाते हुए "एक उत्पाद एक जिला" पर फोकस करेंगे।

**23(10).** वर्षासिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। गैर-फसल सीजन में बहुस्तरीय पैदावार, मधुमक्खी पालन, सौर पम्प, सौर ऊर्जा निर्माण को शामिल किया जाएगा। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (जिसका जुलाई 2019 के बजट में उल्लेख किया गया था) को भी शामिल किया जाएगा। "जैविक खेती" पर पोर्टल-ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

**23(11).** निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) पर किया जाने वाला वित्तपोषण 6000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसे ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

**23(12).** गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नाबार्ड की पुनःवित्तपोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री-किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

**23(13).** हमारी सरकार वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होनेवाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों को लेने वाले पेस्टे पेटिस रुमिनेंट (पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म करने की मंशा रखती है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, हम 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन करेंगे।

**23(14).** नीली अर्थव्यवस्था : हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। इससे विकास होगा और प्रभावी संरक्षण भी होगा। समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा, सुस्थिरता और उत्तरदायी समुद्र मत्स्य पर फोकस किया जाएगा।

**23(15).** तटीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन के जरिए लाभ मिलता है। वर्ष 2022-23 तक, मैं मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन कराने का प्रस्ताव करती हूँ। शैवाल, समुद्री खरपतवार उगाने तथा केज कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

हमारी सरकार युवाओं 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों के माध्यम से फिशरी एक्सटेंशन को शामिल करेगी। हम आशा करते हैं कि 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएगा।

**23(16).** गरीबी उपशमन को दीन दयाल अन्त्योदय योजना में, 50 लाख परिवारों को 58 लाख स्वसहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा जाता है। हम एसएचजी का विस्तार करेंगे।

**24.** अब, ऊपर उल्लिखित 16 विभिन्न कदमों के लिए निधि के आवंटन हेतु इनका दो भिन्न श्रेणियों के तहत विवरण दिया जा रहा है:

कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों; सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इसे अन्य बातों के साथ-साथ इसे विभाजित किया है।

(क) कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए - 1.60 लाख करोड़ रुपये

(ख) ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए - 1.23 लाख करोड़ रुपये

### अरोग्यता, जल और स्वच्छता

महत्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत अब हम वेलनेस, जल और स्वच्छता के बारे में बात करेंगे।

**25.** हमारा स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक सर्वांगीण दृष्टिकोण है जो सभी नागरिकों की तंदुरुस्ती में परिवर्तित होता है। टिटनेस, प्रौढ़ डिप्थेरिया, पोलियो, मिजल्स-रुबेला तथा रोजावायरस की रोकथाम के लिए 5 नई वैक्सिनों सहित 12 बीमारियों को कवल करने के लिए इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। **फिट इंडिया अभियान** जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली गैर-संचारी बीमारियों का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य विज्ञान के समर्थन में एक अत्यंत केंद्रित सुरक्षित जल (जल जीवन मिशन) और व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम (स्वच्छ भारत मिशन) की शुरुआत की गई है। इससे गरीबों पर बीमारियों का बोझ कम होगा।

**26.** इस समय, पीएमजेएवाई के अंतर्गत 20,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पताल हैं, फिर भी हमें इस स्कीम के अंतर्गत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में गरीबों के लिए अधिक अस्पतालों की आवश्यकता है।

**26(1).** पीपीपी मॉडल के तहत अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण विंडो स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रथम चरण में, उन आकांक्षी जिलों को शामिल किया जाएगा जहां इस समय आयुष्मान से पैनलबद्ध अस्पताल नहीं हैं। मेडिकल उपकरणों पर करों से प्राप्त राशियों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना की सहायता में प्रयुक्त किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

**26(2).** मशीन लर्निंग और आर्टिफियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए आयुष्मान भारत स्कीम में, स्वास्थ्य प्राधिकारी और चिकित्सक समाज उचित डिजाइनकृत निवारक प्रणाली से बीमारियों को लक्षित कर सकते हैं।

**27.** "टी.बी. हारेगा देश जीतेगा" अभियान शुरू किया गया है। मैं 2025 तक टी.बी. समाप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता की पूर्ति के प्रयासों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**28.** मैं 2024 तक सभी जिलों में 1000 केंद्र स्थापित करते हुए 2000 औषधियों तथा 300 सर्जिकल को पेशकश करते हुए जन औषधि केंद्र स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ।

मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लिए 6400 करोड़ रुपये हैं।

**29.** हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्ध है। इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन हुआ है। ओडीएफ व्यवहार बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे छूट न जाए। अब तरल और घूसर जल प्रबंधन की दिशा में कार्य किए जाने की और अधिक जरूरत है। कचरा इकट्ठा करने, इकट्ठा करने की जगह पर ही कचरे को अलग-अलग करने और उसको संसाधित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

**30.** सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करने के लक्ष्य से, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से **जल जीवन मिशन** की घोषणा की थी। हमारी सरकार ने इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया है। यह मिशन स्थानीय जल स्रोतों, मौजूदा स्रोतों को पुनःपोषित पर भी बल देता है और जल संचयन तथा विलवणीकरण को बढ़ावा देगा। वे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उन्हें चालू वर्ष में ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस स्कीम को 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

**शिक्षा और कौशल**

**महत्वाकांक्षी भारत** के अंतर्गत शिक्षा और कौशल तीसरी और अंतिम मद है।

**31.** 2030 तक, भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। उनके लिए न सिर्फ साक्षरता आवश्यक है बल्कि उनको रोजगार व जीवन कौशल की भी जरूरत है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ शिक्षा नीति पर चर्चाएं की गई हैं। 2 लाख से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।

**32.** यह महसूस किया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों, अभिनव परिवर्तन, बेहतर प्रयोगशालाओं की और अधिक आवश्यकता है और इसके लिए जाहिर है अधिक पैसों की आवश्यकता है। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों, कार्मिक और यहां तक कि एफडीआई सोर्सिंग को समर्थकारी बनाने के कदम उठाए जाएंगे ताकि अधिक गुणता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

**33.** सामान्य स्ट्रीम (सेवाओं या प्रौद्योगिकी स्ट्रीम की तुलना में) के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियोजनीयता में सुधार आए। मार्च 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिक्षुता संबद्ध डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ कर देंगे।

**34.** सरकार प्रस्ताव करती है कि एक ऐसा कार्यक्रम आरंभ किया जाए जिसके द्वारा देशभर के शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

**35.** समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों तथा साथ ही जिनके पास उच्चतर शिक्षा की पहुंच नहीं है, उनको गुणता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह शिक्षा कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थानों में उपलब्ध होगा जो राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग रुपरेखा में शीर्ष 100 में आते हैं। शुरुआत में, ऐसे कुछ ही संस्थानों से इन कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी।

**36.** भारत उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गन्तव्य होना चाहिए। इसलिए, अपने "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत, एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्ड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग उन विदेशी अभ्यर्थियों की बेंचमार्किंग के लिए किया जाएगा। जिन्हें भारतीय उच्चतर शिक्षा केन्द्रों अध्ययनरत रहने के लिए छात्रवृत्तियां मिलती हैं।

**37.** पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साइबर-न्यायिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किया जा रहा है।

**38.** योग्य चिकित्सीय डॉक्टरों का अभाव है, चाहे वे सामान्य चिकित्सक हों या फिर विशेषज्ञ। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए;

**38(1).** यह प्रस्ताव किया जाता है कि पीपीपी मोड में विद्यमान जिला हस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ दिया जाए। वे राज्य जो अपने हस्पतालों की सुविधाएं मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराते हैं और जिनकी रियायत देकर भूमि उपलब्ध कराने की मंशा है, वे केन्द्र सरकार से पूंजी लागत के 20 प्रतिशत तक की व्यवहार्यता अंतर निधियन प्राप्त कर सकते हैं।

**38(2).** राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं; डिप्लोमा और राष्ट्रीय बोर्ड (डीएनबी/एफएनबी) की अध्येता प्रदान करता है। अंतः सरकार पर्याप्त क्षमता वाले बड़े हस्पतालों को अपने यहां आवासीय डीएनबी/एफएनबी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित करेगी।

**39.** विदेश में शिक्षकों नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की अत्यधिक मांग है। हालांकि, कई बार उनका कौशल नियोजक के मानकों पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए उनके कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वास्थ्य, मानव संसाधन, कौशल विकास मंत्रालय व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करें और उनको मानकों के अनुरूप दक्ष बनाएं। विभिन्न देशों की भाषायी अपेक्षाओं का भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है। यह सब विशेष प्रशिक्षण पैकेजों के माध्यम से हासिल किया जाना होगा।

हमारी सरकार 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।

## आर्थिक विकास

### उद्योग, वाणिज्य और निवेश

सरस्वती-सिंधु सभ्यता के शिल्प और हड़प्पा की मुहरें विलक्षण हैं। वे 3300 वर्ष ईसा-पूर्व की हैं। सिंधु पांडुलिपि-चित्रलिपियों का गूढ़ अर्थ स्पष्ट कर लिया गया है। वाणिज्य और व्यापार संबंधों शब्दों से पता चलता है कि कैसे भारत सहस्राब्दि से कौशल, धातु-कर्म, व्यापार आदि में लगातार समृद्ध रहा है। "तकारा कोलिमी = थोक व्यापारी, "पोद्दार" = धातु को कोष में बदलने का पारखी ।

**40.** उद्यमशीलता हमेशा से भारत की शक्ति रही है। आज भी, युवक और युवतियों ने कहीं भी क्यों न हों, अपनी अच्छी स्थिति को त्यागकर भारत की वृद्धि में अपना योगदान किया है। उनमें जोखिम उठाने की क्षमता है और वे चुनौतियों से निपटने के लिए आमूलचूल समाधानों के साथ आते हैं। इसी प्रकार, भली-भांति स्थापित पुराने उद्योग बदलती वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में स्वयं को पुनः तैयार कर रहे हैं।

उनके ज्ञान, कौशल और जोखिम उठाने की क्षमताओं का संज्ञान लेते हुए, हम चाहते हैं कि उनके लिए और अधिक अवसर सृजित किए जाएं और अड़चनों को हटाया जाए। मैं निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ जो निवेश-पूर्व सलाह, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना सहित "एंड टू एंड" सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएगा और केन्द्र व राज्य स्तर पर निपटान को सुसाध्य बनाएगा। यह पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा।

**41.** यह तीन अलग-अलग विकासशील आर्थिक गतिविधियों के अधिकतम लाभ का मामला है: (1) आगामी आर्थिक गलियारे; (2) विनिर्माणकारी गतिविधियों का पुनर्नवीकरण और (3) प्रौद्योगिकी और महत्वाकांक्षी वर्गों की मांगें। इन तीनों को एक बिंदु पर लाकर हमें लाभ प्राप्त करना होगा। इसलिए, राज्यों के साथ सहयोग से पीपीपी मोड में **पांच नए स्मार्ट शहरों** को विकसित करने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे ही शहरों को चुना जाएगा जो ऊपर बताए सिद्धान्तों के लिहाज से सर्वोत्कृष्ट विकल्प हों।

**42.** भारत को नेटवर्क वाले उत्पादों का विनिर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा। इसके फलस्वरूप, अधिक निवेश प्राप्त होगा और हमारे युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजन होगा।

**42(1).** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणकारी उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी है और भारत ने अपनी लागत प्रभावी लाभदायक स्थिति का परिचय दिया है। इस उद्योग में रोजगार सृजन की संभावनाएं अपार हैं। भारत को आवश्यक है कि अपने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करे और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश आकर्षित करे। यहां, मैं, मोबाइल फोनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केन्द्रित स्कीम का प्रस्ताव करती हूँ।

**42(2).** समुचित संशोधन करके, यह स्कीम चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए भी अपनाई जा सकती है।

**43.** भारत प्रत्येक अच्छी-खासी मात्रा में 16 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तकनीकी वस्त्रों का आयात करता है। इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए और भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है जिसकी 1480 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से 2020-21 से 2023-24 की चार-वर्षीय कार्यान्वयन अवधि होगी।

**44.** लाल किले से, हमारे प्रधानमंत्री जब "जीरो डिफैकट-जीरो इफैकट" विनिर्माण की बात करते हैं तो उनका आशय गुणवत्ता और मानकों से है। पिछले साल सितंबर में, मैंने उद्योगों से सभी जरूरी, अनिवार्य तकनीकी मानकों और उनके प्रभावी प्रवर्तन के समयबद्ध अंगीकरण की अपील की थी। इस वर्ष के दौरान, सभी मंत्रालय गुणता मानक संबंधी आदेश जारी करेंगे।

**45.** उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए, एक नई स्कीम, "निर्विक" का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें उच्चतर बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि में कटौती और दावों के निपटान हेतु सरलीकृत प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। 5वें वर्ष के समाप्त होते होते, आशा है कि इस स्कीम से लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का निर्यात करने में सहायता मिलेगी।

**46.** केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लगे शुल्कों और करों, जैसे कि विद्युत शुल्क और परिवहन के लिए प्रयोग किए गए ईंधन पर वैट को निर्यातकों को डिजिटल तरीके से लौटाने का प्रस्ताव किया जाता है। इन शुल्कों व करों को अब तक मौजूदा अन्य किसी तंत्र के तहत न तो छूट प्राप्त थी और न लौटाया जाता था। *निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की यह स्कीम इस वर्ष शुरू की जाएगी।*

**47.** प्रधानमंत्री का विजन है कि प्रत्येक जिला एक निर्यात केन्द्र के तौर पर विकसित होना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है और संस्थागत मैकेनिज्म का सृजन किया जा रहा है।



**48.** माल, सेवाओं की अधिप्राप्ति और निर्माण कार्यों के लिए एकल मंच उपलब्ध कराने के लिए देश में एकीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली के सृजन हेतु सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) योजना अग्रसर है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सुनहरा अवसर है। इस प्लेटफार्म पर 3.24 लाख विक्रेता पहले से ही सक्रिय हैं। इस पर 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का प्रस्ताव किया जाता है।

मैं, वर्ष 2020-21 के लिए उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए लगभग 27,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूँ।

“आर्थिक विकास” थीम के अंतर्गत दूसरा फोकस अवसंरचना पर है।

#### अवसंरचना

**49.** माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में बल देकर कहा था कि अगले 5 वर्षों में अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। इसी के अनुकरण में मैंने 31 दिसम्बर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6500 से अधिक परियोजनाएं हैं जिन्हें इनके आकार और विकास के चरण के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है।

इन नई परियोजनाओं में हाऊसिंग, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मुहैया कराना, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, मेट्रो और रेल यातायात, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक की जीवन शैली में सुधार लाने का विजन रखा गया है। हम इन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में जेनरिक और क्षेत्रगत सुधार लाएंगे।

भारत के युवावर्ग के लिए अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में रोजगार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना केन्द्रित कौशल विकास के अवसरों को विशेष बल प्रदान करेगी।

**50(1).** मैं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयारी सुविधा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों से युवा इंजीनियरों, प्रबंधन स्नातकों और अर्थशास्त्रियों की सक्रिय भागीदारी होगी।

**50(2).** सरकार की सभी अवसंरचना एजेंसियों को निदेश देने का भी प्रस्ताव है कि स्टार्ट-अप्स में युवा शक्ति को शामिल करें। ये नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना में मूल्यवर्धित सेवाएं लाने में मददगार होंगे।

**51.** जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी की जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख विनियामकों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएंगी। इसके अंतर्गत सिंगल विंडो वाली ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट सृजित होगी और रोजगार सृजन, कौशल और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

**52.** राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। इसमें 2500 किमी अभिगम नियंत्रण राजमार्गों, 9000 किमी आर्थिक गलियारों, 2000 किमी तटीय और न्यू पत्तन सड़कों और 2000 किमी सामरिक राजमार्गों का विकास शामिल किया जाएगा।

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे और दो अन्य पैकेज वर्ष 2023 तक पूरे हो जाएंगे। चैन्नई-बेंगलूरु एक्सप्रेसवे को भी शुरू किया जाएगा।

**53.** फास्टेग तंत्र हमारे राजमार्गों को और अधिक वाणिज्यिकृत करने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अधिक संसाधन जुटा सके। मैं वर्ष 2024 से पहले 6000 किमी से अधिक के राजमार्गों के कम से कम बारह लॉट्स को मौद्रिकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**54.** अपनी ड्यूटी करते हुए भारतीय रेल राष्ट्र को अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा है।

(क) इस सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के 100 दिनों के भीतर इसने 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधाएं चालू की हैं।

(ख) मानवरहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया है।

(ग) 27000 किमी लंबाई की रेललाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें लागतों को इष्टतम करने की आवश्यकता होगी। रेलवे के पास ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। भारतीय रेल के बारे में मैं अन्य के अलावा इन पांच उपायों पर बल देना चाहूंगी:

- रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेल ट्रैक के साथ-साथ बड़ी सोलर पावर क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

- स्टेशन के पुनर्विकास की चार परियोजनाओं और 150 यात्री गाड़ियों का प्रचालन सरकारी निजी भागीदारी रीति से किया जाएगा। निजी भागीदारी को आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- तेजस के तरह की और गाड़ियां प्रमुख पर्यटक गंतव्यों को जोड़ेंगी।
- मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाई जाएगी।
- 18600 करोड़ रुपये की लागत वाली 148 किमी लंबी बेंगलूरु सबअर्बन ट्रांसपोर्ट परियोजना में मेट्रो मॉडल पर किराया लगेगा। केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत इक्विटी प्रदान करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक का भाग विदेशी सहायता से पूरा किया जाएगा।

**55.** हमारे समुद्री बंदरगाहों को और अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी को निष्पादन में और सुधार लाना है। वैश्विक बेंचमार्कों के अनुरूप एक गर्वनेंस फ्रेमवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

सरकार कम से कम एक बड़ी बंदरगाह को निगमित करने और बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

**56.** अंतर्देशीय जलमार्गों को पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल विकास मार्ग पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 890 किमी दुबरी-सादिया कनेक्टिविटी का कार्य 2022 तक कर लिया जाएगा।

जल मार्गों के विकास कार्य के परिणामस्वरूप नदी के दोनों किनारों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने “अर्थ गंगा” की अवधारणा रखी है। नदी के किनारों पर आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को जारी रखा गया है।

**57.** देश में वैश्विक औसत की तुलना में वायु यातायात तेजी से बढ़ रहा है। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 तक एक सौ और वायुपत्तन तैयार किए जाएंगे। आशा है कि इस अवधि में वायु बेड़े में वायुयानों की संख्या वर्तमान 600 से बढ़कर 1200 तक पहुंच जाएगी।

मैं 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करता हूं।

**58.** हर घर में बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तथापि, वितरण क्षेत्र विशेषकर डिस्कॉन्स वित्तीय दबाव में हैं। मंत्रालय ‘स्मार्ट’ मीटरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। मैं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करता हूं कि अगले 3 वर्षों में बिजली के पारंपरिक मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदल दिया जाए। इसके अलावा, इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार आपूर्तिकर्ता और दरों का चयन करने की आजादी मिलेगी।

डिस्कॉम्स में सुधार लाने के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे।

मैं वर्ष 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखती हूं।

**59.** तेल और गैस के अपस्ट्रीम क्षेत्र में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पोलिसी (ओएएलपी) ने काफी सफलता पाई है जिसके अंतर्गत अन्वेषण के लिए निजी क्षेत्र और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 1,37,000 वर्ग किमी भूमि सौंपी है। सिटी गैस वितरण के अधिकार भी वितरित किए गए हैं।

**60(1).** इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है; और

**60(2).** भारत में गैस के बजारों को अधिक सघन बनाने का प्रस्ताव है, पारदर्शी मूल्य-निर्धारण को सुकर बनाने और लेन-देनों को सरल बनाने के लिए और अधिक सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे।

### नई अर्थव्यवस्था

**61.** नई अर्थव्यवस्था अभिनव परिवर्तनों पर आधारित होती है जो पहले से स्थापित व्यापार मॉडलों का स्थान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (आईओटी), 3-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डाटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विश्व की अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रहे हैं। भारत ने पारंपरिक व्यवसायों के स्थान पर एग्रीगेटर प्लेटफार्म्स के साथ साझी अर्थव्यवस्था जैसे नए प्रतिमान पहले ही अपना लिए हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन में सक्षम होने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का दोहन किया है और वह भी उस पैमाने पर जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।

**62.** अब “डाटा इज द न्यू ऑयल” एक सूक्ति बन गई है और यह सच भी है कि एनालिटिक्स, फिनटेक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) ने हमारी जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया है। इसका लाभ उठाने के लिए मैं:

**62(1).** जल्द ही ऐसी नीति लाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके जरिए निजी क्षेत्र को देश भर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके। इससे हमारी फर्म अपनी मूल्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक चरण में आंकड़ों को बड़ी कुशलता से समाविष्ट करने में सक्षम होंगी।

**62(2).** हमारा विजन है ग्राम पंचायत स्तर पर सभी ‘6 सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजीटल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसलिए, भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों से इस वर्ष 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है।

**63.** हमें ज्ञान-प्रेरित उद्यमों के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा का सृजन और संरक्षण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में अनेक उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं जिनसे स्टार्ट-अप्स लाभान्वित होंगे।

**63(1).** एक ऐसे डिजीटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा जो आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और अभिग्रहण को सुकर बनाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्टता संस्थान में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाएगा जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जटिलता और नवोन्मेष पर कार्य करेगा।

**63(2).** नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

**63(3).** अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बेड्स को संपोषित करते हुए प्रौद्योगिकी क्लस्टरों का स्तर और ऊपर उठाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माणकारी सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

**63(4).** भारत के जेनरिक लैंडस्कप की मैपिंग अगली पीढ़ी की चिकित्सा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए हम एक व्यापक डाटाबेस सृजित करने के लिए दो नई राष्ट्र स्तरीय विज्ञान स्कीमों को प्रारंभ करेंगे।

**63(5)** सरकार पहले चरण के स्टार्टअप्स के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।

**64.** क्वांटम प्रौद्योगिकी व्यापक रूप से विविध एप्लीकेशनों के साथ कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा में नए मोर्चे खोल रही है। आशा है कि इस क्षेत्र में विकसित हो रही सैद्धांतिक संरचनाओं से बड़ी संख्या में वाणिज्यिक एप्लीकेशन उभरकर सामने आएंगे।

क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 8000 करोड़ रुपये का परिचय प्रदान करने का प्रस्ताव है।

### जिम्मेदार समाज

हमारे तीसरे थीम में हम महिला एवं बाल, सामाजिक कल्याण संस्कृति और पर्यटन पर फोकस करेंगे।

#### महिला एवं बाल, सामाजिक कल्याण

**65.** मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों से अधिक है। प्रारंभिक स्तर पर यह अनुपात 94.32 प्रतिशत, जबकि लड़कों के लिए यह 89.28 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर, यह अनुपात 78 प्रतिशत की तुलना में 81.32 प्रतिशत है, उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कों के 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों का अनुपात 59.70 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

**66.** माता और बच्चे का स्वास्थ्य घनिष्ठ रूप से सहसंबद्ध हैं। पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों (0-6वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2017-18 में ‘पोषण अभियान’ शुरू किया था। 10 करोड़ से अधिक परिवारों की पोषणात्मक स्थिति को उपलोड करने के लिए छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए गए हैं। इन बदलावों का पैमाना अभूतपूर्व रहा।

**67.** वर्ष 1929 के शारदा अधिनियम में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की गई। जैसे-जैसे भारत तरक्की कर रहा है, महिलाओं के शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के

अवसर बन रहे हैं। महिला मातृत्व दर में कमी लाना तथा पोषण के स्तरों में सुधार लाना अनिवार्य है। मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैं एक कार्य बल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूँ जो अपनी अनुशंसाएं छह माह की समयावधि में देगी।

मैं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करती हूँ।

**68.** महिलाओं के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए इस बजट से महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।

**69.** हमारी सरकार इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प है कि सीवर सिस्टमों या सेप्टिक टैंकों की सफाई का कोई मैनुअल कार्य नहीं होगा। ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। यह मंत्रालय इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य कर रहा है। अब हम इसे विधायी एवं संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से इसके तार्किक निर्णय पर ले जाएंगे। ऐसी प्रौद्योगिकियों की व्यापक पैमाने पर स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

**70.** अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की दिशा इस सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ।

**71.** अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मैं वर्ष 2020-21 के लिए बजट में लगभग 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान करती हूँ।

**72.** इस सरकार को वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की समस्याओं की चिंता है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए का आबंटन मुहैया कराया जा रहा है।

### संस्कृति एवं पर्यटन

**73.** हमारी सरकार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करती है; इसे शुरू में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा। ऐसे खोजों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता जुटाने और उनका विश्लेषण करने और उच्चस्तरीय संग्रहालयों के माध्यम से उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए संग्रहालय विज्ञान एवं पुरातत्व विज्ञान जैसी विधाओं में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। वर्तमान में, इन दोनों विषयों में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी एक रुकावट है। इससे पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

**74.** स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। वे हैं: राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलाविरा (गुजरात) और अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)।

**75.** हमारे प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय, जो देश में सबसे पुराना है, के पुनरुद्धार की घोषणा की थी।

**75(1).** ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में, मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थित होगा। पूरे देश में चार और संग्रहालयों का नवीकरण और री-क्यूरेण किया जाएगा ताकि आगंतुकों को एक विश्वस्तरीय अनुभूति मिल सके। हमारी सरकार, रांची (झारखंड) में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का समर्थन करेगी।

**75(2).** लोथल, जो अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग का एक नौवहन स्थल है, में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

मैं 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**76.** यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक (विश्व आर्थिक मंच) में भारत का रैंक 2014 के 65वें स्थान से सुधरकर 2019 में 34 हो गया। जनवरी से नवम्बर, 2019 की अवधि का विदेशी विनिमय आय 1.75 लाख करोड़ रुपए से 7.4 प्रतिशत बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपए हो गया।

पर्यटन में वृद्धि का विकास और रोजगार से सीधा संबंध है। राज्यों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें कुछ चिह्नित स्थानों के लिए एक योजना तैयार करेंगी और 2021 के दौरान वित्तीय योजना तैयार करेंगी जिसके तहत 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के लिए 2500 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

### पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

**77.** सितम्बर, 2019 में, प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अपने सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मिलन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया है। यह वैश्विक भागीदारी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग की शुरुआत के बाद, इस प्रकार की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस वैश्विक भागीदारी से सीईएनडीएआई संरचना के एक भाग के रूप में अनेक दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे आपदा उन्मोचन अवसंरचना पर जोर देने से जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना संभव होगा।

**78.** देश के विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत ने एक 'सर्वोत्तम प्रयास' के आधार पर 2015 के पेरिस करार के अंतर्गत, अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान सौंपा। इसका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2021 से होगा। कार्य के रूप में हमारी प्रतिबद्धताएं सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएंगी।

**79.** अभी भी ऐसे जल विद्युत संयंत्र हैं जो पुराने हैं और उनका कार्बन उत्सर्जन स्तर बहुत अधिक है।

ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए, हम प्रस्ताव करते हैं कि यदि उनका कार्बन उत्सर्जन पूर्व निर्धारित मानकों से अधिक हो, तो उन्हें चलाने की उपयोगिता उन्हें बन्द कर देने में ही है। इस प्रकार खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है।

**80.** एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में, स्वच्छ हवा चिंता का विषय है। सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है जो एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रही हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। इस प्रोत्साहन के मानदण्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए, वर्ष 2020-21 के लिए 4400 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है।

(इस कुरल का अर्थ है कि बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा (प्रजा की), ये पांच चीजें किसी राज्य के आभूषण हैं)

### अभिशासन

**81.** माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैंने फूलों के गुलदस्ते के रंग और घटक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। उन्हें आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार भारत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब मैं उन दो हाथों के बारे में बताती हूँ जो उन्हें संभालेंगे। उनमें से एक हाथ अभिशासन निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त, नीति संचालित और सही इरादा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास करना है। प्रत्येक नागरिक, आकांक्षी युवा, कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं, जोखिम उठाने वाले उद्यमियों, सर्वदा आशान्वित और परिश्रमी किसान या बुद्धिमान एवं वृद्ध वरिष्ठ नागरिक पर विश्वास करना। उनमें से कई करदाता हैं। आज अन्य लोग करदाता नहीं हो सके हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष सभी नागरिकों की तरफ से लक्ष्य के रूप में हासिल करने के लिए 'जीवन आसान' को प्रस्तुत किया है। 'जीवन आसान' और 'व्यवसाय करना सरल' दोनों का एक महत्वपूर्ण पहलु कर प्रशासन की निष्पक्षता और कुशलता है। हम इस बजट के माध्यम से विधानों में एक "करदाता संहिता" शामिल करना चाहते हैं। हमारी सरकार करदाताओं को पुनः आश्वस्त करना चाहती है कि हम उपाय करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे नागरिक किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्त हों।

**82.** विधानों में कार्यों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी, जो सिविल प्रकृति का है, तय करने के बारे में बहस चल रही है। अतः, कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जो इसे ठीक कर देगा। उसी प्रकार, जहां उपबंध मौजूद है, वहां अन्य कानूनों की भी जांच की जाएगी और उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

**83.** सरकार का इरादा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। वर्तमान में, अभ्यर्थियों को समान पदों के लिए अलग-अलग समय पर अनेक एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों के समय, प्रयास और खर्च पर भारी बोझ पड़ता है। उन अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रत्येक जिले में, विशेषरूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

**84.** व्यावसायिक एवं अन्य विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए, सरकार ने अनेक अधिकरणों और विशेषज्ञ निकायों का गठन किया है। सर्वश्रेष्ठ मेधावी एवं पेशेवर विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए इन निकायों में सीधी भर्ती सहित नियुक्ति के एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

**85.** एक स्थायी एवं भविष्यसूचक व्यवसाय वातावरण इस सरकार की एक मुख्य विशेषता है। संविदाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, इस बात पर भी एक बड़ी बहस चल रही है। भारत में संविदाओं से संबंधित एक व्यवस्थित ढांचा है। हम उसे सुदृढ़ करने पर विचार करेंगे।

**86.** निरंतर जटिल होती जा रही हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक समय निगरानी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आकड़ों की बहुत ही अधिक विश्वसनीयता होनी चाहिए। आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित प्रस्तावित नई राष्ट्रीय नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इससे आधुनिक आकड़ा संग्रहण, समेकित सूचना पोर्टल और सूचनाओं का समय पर प्रसारण की दिशा में एक कार्य-योजना तैयार होगी।

**87.** मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 में जी20 अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। इस अध्यक्षता के दौरान, भारत महत्वपूर्ण रूप से वैश्विक आर्थिक एवं विकास कार्यक्रम का संचालन करने में समर्थ हो सकेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं इसकी तैयारी आरंभ करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करती हूँ।

**88.** सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत अधिक प्राथमिकता है। सरकार अभिनव एवं विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्यों को आरंभ करने में सहायक होने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से वित्तीय सहायता सुचारु रूप से पहुँचना सुनिश्चित कर रही है। केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन की जेस्टेशन अवधि कम करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार आया है।

**89.** सरकार नव गठित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सहायता देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को 5,958 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

### वित्तीय क्षेत्र

**90.** यदि अभिशासन को आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार भारत वाले गुलदस्ते को पकड़े हुए दो हाथों में से एक हाथ के रूप में उल्लेख किया जाए, तो दूसरा हाथ वित्तीय क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के लिए, एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के हमारे प्रयासों में, वित्तीय ढांचा विकसित होते रहना चाहिए और अधिक से अधिक सुदृढ़ होते रहना चाहिए।

**91.** हमने पिछले कुछ समय पहले 10 बैंकों का एकीकरण करके चार बैंक करने का अनुमोदन किया था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने विनियामक एवं विकास के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूँजी के माध्यम से लगभग 3,50,000 करोड़ रुपये प्रदान किया था। इन बैंकों में अभिशासन संबंधी सुधार किए जाएंगे ताकि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

उनमें से कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए पूँजीगत बाजार में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

**92.** मैं इस गरिमामयी सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ठोस तंत्र विद्यमान है और जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है।

इसके अतिरिक्त, जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा, जो इस समय 1 लाख रुपये है उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

**93.** सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि वृत्तिदक्षता में वृद्धि की जा सके, पूँजी तक पहुंच हो सके और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग के लिए अभिशासन और निगरानी में सुधार लाया जा सके।

**94.** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम, 2002 के अधीन ऋण वसूली हेतु पात्र होने के लिए एनबीएफसी हेतु सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये का आस्ति सीमा किए जाने अथवा मौजूदा 1 करोड़ रुपये से घटाकर ऋण सीमा 50 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

**95.** पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। फिर भी, अपेक्षाकृत अधिक निजी पूँजी की आवश्यकता है। तदनुसार, भारत सरकार के आईडीबीआई बैंक की शेष पूँजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को बेचे जाने का प्रस्ताव है।

**96.** सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पारदर्शिता और अपेक्षावृत्त अधिक वृत्तिदक्षता लाने के लिए और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सरकार उचित उपाय करेगी।

**97.** नौकरी के दौरान आवागमन को आसान बनाने में मदद करने के लिए, हम सार्वभौमिक पेंशन के दायरे को स्वतः नामांकन में लाना चाहते हैं; हम ऐसे तंत्र भी लाना चाहते हैं जो अंतर-प्रचालनीयता में समर्थ बना सके और संचित निधियों के लिए सुरक्षा उपाय मुहैया करा सकें।

पीएफआरडीआई की विनियमनकारी भूमिका के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। भारतीय पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम में ऐसे आवश्यक संशोधन किए जाएंगे जो पीएफआरडीआई से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस न्यास के पृथक्करण को भी सुकर बनाएंगे। यह सरकार से इतर कर्मचारियों द्वारा पेंशन न्यास की स्थापना में भी समर्थ बनाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे नागरिक अपनी वृद्धावस्था के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित होंगे।

**98.** अर्थव्यवस्था के पहिये को चलायमान रखने के लिए एमएसएमई अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये नौकरियों, नवाचार तथा जोखिम लेने वालों का सृजन भी करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इस बजट में भी और अधिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

**98(1).** मैं, कारक विनियमन अधिनियम, 2011 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे एनबीएफसी टीआरडीडीएस के जरिए लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए बीजक वित्त पोषण का विस्तार करने में समर्थ होंगी, जिससे उनकी आर्थिक और वित्तीय धारणीयता में वृद्धि होगी।

**98(2).** कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण एमएसएमई के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस ऋण की गणना अर्ध-इक्विटी के रूप में की जाएगी। और मध्यम तथा लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से इसे पूरी गारंटी प्रदान की जाएगी। तदनुसार, सरकार द्वारा सीजीटीएमएसई की राशि में वृद्धि की जाएगी।

**98(3).** पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत ऋण संरचना से पांच लाख से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। पुनर्संरचना विंडो 31 मार्च, 2020 को समाप्त होनी थी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस विंडो का 31 मार्च, 2021 तक विस्तार करने पर विचार किए जाने का अनुरोध किया है।

**98(4).** एक ऐप-आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद प्रारंभ किया जाएगा। इससे एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतानों और परिणामी नकदी प्रवाह की विसंगति की समस्या का निराकरण होगा।

**99.** मध्यम-आकार की अनेक कंपनियां घरेलू तौर पर सफल हैं किन्तु निर्यात बाजारों में वे सफल नहीं हैं। भेषज, आटो संघटकों और अन्य जैसे चुनिंदा सेक्टरों के लिए हम प्रौद्योगिकी उन्नयनों, अनुसंधान और विकास, व्यवसाय संबंधी कार्यनीति आदि के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ रुपये की स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इन दोनों संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था 50 करोड़ रुपये का अंशदान करेगी। यह 100 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी और तकनीकी सहायता के लिए प्राप्त की जाएगी। बैंकों से 900 करोड़ रुपये का ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

### वित्तीय बाजार

**100.** पिछले वर्ष, बजट भाषण में, मैंने बांड बाजार को गहन बनाने का उल्लेख किया था। आकांक्षी वृद्धि दर हासिल करने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रणाली में पूंजी प्रवाह की आवश्यकता होगी। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से काफी कार्य किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को निम्न उपलब्धियों के बारे में बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है

**100(1).** सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त अनिवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह से खोल दी जाएंगी।

**100(2).** कारपोरेट बांडों में एफपीआई के लिए सीमा, वर्तमान में बकाया स्टॉक का 9 प्रतिशत, बढ़ाकर कारपोरेट बांडों के बकाया स्टॉक की 15 प्रतिशत कर दी जाएगी।

**100(3).** निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और ऋण चूक स्वेप का दायरा बढ़ाने के लिए, हम वित्तीय संकुचनों को कम करने के लिए एक तंत्र तैयार करने हेतु एक विधान तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे सदन के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

**101.** सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ऋण-आधारित एक्सचेंज कारोबारित निधि (ईटीएफ) एक बड़ी सफलता थी। सरकार मूल रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करके एक नई ऋण-ईटीएफ शुरू करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करती है।

यह खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच सुलभ कराने के साथ-साथ पेंशन निधियों और दीर्घावधिक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश प्रदान करेगी।

**102.** एनबीएफसी/एचएफसी की नकदी संबंधी बाधाओं का निराकरण करने के लिए, केन्द्रीय बजट 2019-20 के बाद, सरकार ने एनबीएफसी के लिए एक आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है। नकदी उपलब्ध कराने की इस सहायता को आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाएगा। सरकार इस प्रकार शुरू की गई प्रतिभूतियों की गारंटी देकर सहायता प्रदान करेगी।

### अवसंरचना वित्तपोषण

**103.** जब 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी तब अवसंरचना में निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगी कि

अवसंरचना परियोजना की सहायता के रूप में लगभग 22,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ की सहायक कंपनी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों को इक्विटी सहायता की पूर्ति करेगी। वे इसका उपयोग, यथा-अनुमेय, 1,00,000 करोड़ से अधिक की वित्तपोषण परियोजना के सृजन के लिए करेंगे। इससे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण के एक बड़े स्रोत का सृजन होगा और एक बहुप्रतीक्षित अनिवार्यता पूर्ण होगी।

**104.** आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा सर्वोत्कृष्ट डेटा प्रोसेसिंग का केन्द्र बनने की क्षमता है।

**104(1).** आवास भवन के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक अनुमोदित मुक्त व्यापार जोन है। इसकी पहले से ही 19 बीमा कंपनियां, 40 बैंकिंग कंपनियां हैं। इसने बहुमूल्य धातु परीक्षण प्रयोगशालाओं और परिष्करण सुविधाओं की स्थापना का भी प्रावधान किया है। विनियामक के अनुमोदन से, गिफ्ट सिटी वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में गिफ्ट-आईएफएससी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना करेगा। यह स्वर्ण आयातों और निर्यातों के लिए प्राथमिक अंतरमध्यवर्ती होगा। यह भारत को विश्व भर में अपने स्थान को सुधारने और भारत में रोजगार सृजित करने में समर्थ बनाएगा तथा इससे स्वर्ण का बेहतर मूल्य अन्वेषण हो पाएगा।

**104(2).** हालिया वर्षों में अपतटीय वित्तीय केन्द्रों में भारतीय रुपये की व्यापार मात्रा में भी उछाल आया है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने गिफ्ट सिटी, गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में व्यापार किए जाने वाले रुपी व्युत्पादों को अनुमति देने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

### विनिवेश

**105.** स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करना कंपनी को अनुशासित करता है और वित्तीय बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराता है तथा इसके मूल्य को मुक्त करता है। यह खुदरा निवेशकों को इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान में सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

### राजकोषीय प्रबंधन

**106.** 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी प्रथम रिपोर्ट दे दी है। सहकारी संघवाद की भावना से मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। यह आयोग 2021-22 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट वर्ष के बाद वाले भाग के दौरान प्रस्तुत करेगा।

**106.** मैंने वर्ष 2016-17 और 2017-18 की संग्रहण में से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि शेष राशियों को दो किस्तों में अंतरित करने का निर्णय लिया है। इसके पश्चात, निधि में अंतरण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के जरिए संग्रहण तक ही सीमित होगा।

**107.** केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं को भविष्य की उभरती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के मुताबिक बनाने, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमित सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो, बुनियादी कार्यापलट आवश्यक है।

**108.** हाल ही में संभावित राजकोषीय आंकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बहस होती रही है। मैं इस सदन को आश्चस्त करती हूँ कि अपनाई गई प्रक्रिया एफआरबीएम अधिनियम, के अनुरूप है। यह अब तक अपनाई गई परिपाटियों के भी अनुरूप है।

तथापि, और अधिक स्पष्टता के लिए, मैंने अनुबंधों में केन्द्रीय सरकार के उस ऋण की गणना की है जो बाजार उधार के भाग नहीं हैं और जिनका उपयोग व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। अब तक इन ऋणों के ब्याज का शोधन और अदायगी भारत की संचित निधि से की गई है।

**109.** वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान 26.19 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर हैं और प्राप्तियां 19.32 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए हमने उपलब्ध प्रवृत्तियों के आधार पर जीडीपी की 10 प्रतिशत पर मामूली वृद्धि अनुमानित की है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियां 22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं और विभिन्न स्कीमों और जीवन की गुणवत्ता, सुधार की आवश्यकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए व्यय के स्तर को 30.42 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

वर्ष के दौरान सरकार ने पूंजी व्यय को ऊपर रखते हुए निर्बाध रूप से कार्य किया है। वस्तुतः इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ब्योरा मेरे भाषण की मुद्रित प्रति के अनुबंधों में देखा जा सकता है।



**110.** प्रत्येक बजट में राजकोषीय घाटे के मुद्दे का उचित रूप से निराकरण किया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार ने निवेशों को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कर सुधार किए हैं। तथापि, संभावित कर वृद्धि में समय लगेगा।

हमने स.अ. 2019-20 में 3.8 प्रतिशत और ब.अ. 2020-21 के लिए 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। यह अनुमान सरकार की वृहद आर्थिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहने के अनुरूप है। इसमें दो घटक शामिल हैं:

(क) वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 ब.अ.के लिए 3 प्रतिशत;

(ख) एफआरबीएम एक्ट की धारा 4(2) में अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण अनुमानित राजकोषीय घाटे से अंतर के लिए एक ट्रिगर तंत्र का प्रावधान है। अतः, मैंने सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 दोनों के लिए, एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के अनुरूप 0.5 प्रतिशत का अंतर लिया है।

तदनुसार, संसद के समक्ष मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-कार्यनीति संबंधी विवरण के रूप में वापसी पथ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह राजकोषीय पथ हमें सरकारी निधियों से निवेश की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना राजकोषीय सुदृढ़ता के पथ के लिए प्रतिबद्ध करता है।

तदनुसार, 2019-20 के लिए निवल बाजार उधार 4.99 लाख करोड़ रुपये होगा और वर्ष 2020-21 के लिए यह 5.36 लाख करोड़ रुपये होगा।

**111.** वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उधारों का एक अच्छा हिस्सा सरकार के उस पूंजीगत व्यय के लिए चला जाएगा जो 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था दूसरी 22,000 करोड़ रुपये की राशि कतिपय ऐसी विनिर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनियों को वित्तपोषित करने हेतु इक्विटी के लिए आबंटित की गई है जो इसे कई गुणा बढ़ा लेंगी और अवसंरचना क्षेत्र को और अधिक आवश्यक दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराएंगी। इससे अर्थव्यवस्था की वर्धित गति में भी सुधार होना चाहिए।

अब मैं अपने भाषण के भाग ख में अपने विचार रखूंगी।

#### भाग ख

##### प्रत्यक्ष कर

**112.** अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मूलभूत राजकोषीय उपायों की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था का उच्च वृद्धि के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना सुनिश्चित किया है। यह ऐसा समय है जब देश व्यवसाय के सर्वाधिक आकर्षण गंतव्य बनने के लिए एक दूसरे के साथ ऐसी होड़ में लगे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसलिए यह आश्चर्य होने के लिए कि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी और निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य बना रहे, हमने विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर दर को अभूतपूर्व रूप से कम करके 15% के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसी तरह, मौजूदा कंपनियों के लिए भी उक्त दर को कम करके मात्र 22% कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, हमारी कार्पोरेट कर दरें अब विश्व में न्यूनतम दरों में शामिल हैं। इससे कंपनियां अपने व्यवसायों को फैलाने में और भविष्य में नए निवेश करने में सक्षम होंगी। हालांकि थोड़े समय के लिए, इन उपायों के चलते हमें अत्यधिक राजस्व की हानि होगी, फिर भी मैं निश्चित हूँ कि लंबे समय बाद हमारी अर्थव्यवस्था को इनका प्रचुर लाभ होगा।

सूर्य जल की नन्हीं बूंदों से वाष्प लेता है। यही राजा भी करता है। बदले में ये प्रचुर मात्रा में लौटाते हैं। वे लोगों के कल्याण के लिए ही संग्रह करते हैं।

(कालिदास रचित रघुवंश के सर्ग 1, दोहा 18)

**113.** अभी तक किए गए सुधारात्मक उपायों के क्रम में, इस बजट के कर प्रस्तावों में वृद्धि को उत्प्रेरित करने, कर ढांचे को सरल बनाने, अनुपालन को सहज बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए और अधिक सुधार शुरू किए जाएंगे।

##### 114. व्यक्तिगत आयकर और कराधान का सरलीकरण

- 2019 के अंतरिम बजट में हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यष्टियों को आयकर से छूट दी थी। लेकिन वर्तमान में, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% और 10 लाख रुपए के ऊपर की आय पर 30% कर का भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में आयकर अधिनियम विभिन्न छूटों और कटौतियों से भरा पड़ा है जिससे करदाता द्वारा अनुपालन और कर प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम का प्रशासन बोझिल हो गया है। किसी करदाता के लिए पेशवरों की सहायता के बिना आय कर कानून का अनुपालन करना लगभग असंगत हो गया है।

- व्यष्टि करदाताओं को पर्याप्त राहत देने और आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए, मैं एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव करती हूँ जिसमें उन व्यष्टि करदाताओं के लिए आयकर दरों को पर्याप्त रूप से कम किया जाएगा जो कतिपय कटौतियों और छूटों का त्याग करते हैं।
- नई व्यवस्था में, एक व्यष्टि को 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के बीच आय के लिए 20% की वर्तमान दर के स्थान पर 10% की कम दर पर कर भुगतान करना होगा।
- 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय के लिए वह 20% की वर्तमान दर के स्थान पर 15% की दर पर कर भुगतान करेगा।
- इसी तरह 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपए के बीच की आय के लिए करदाता वर्तमान 30% की दर के स्थान पर 20% की कम दर पर कर भुगतान करेगा।
- 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 30% की मौजूदा दर के स्थान पर 25% की दर पर कर लगेगा। 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% की दर से कर लगता रहेगा।
- जो 5 लाख रुपए तक आय अर्जित करते हैं उन्हें न तो पुरानी व्यवस्था में और न ही नई व्यवस्था में कोई कर देने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित कर ढांचा करदाताओं को पर्याप्त राहत देगा और उनको अधिक राहत मिलेगी जो मध्यम वर्ग से हैं।

कर योग्य आय के स्लैब (रुपए)	मौजूदा कर दरें	नई कर दरें
0-2.5 लाख	छूट	छूट
2.5-5 लाख	5%	5%
5-7.5 लाख	20%	10%
7.5-10 लाख	20%	15%
10-12.5 लाख	30%	20%
12.5-15 लाख	30%	25%
15 लाख से ऊपर	30%	30%

- नई कर व्यवस्था में, किसी करदाता द्वारा दावित छूटों और कटौतियों के आधार पर उसे पर्याप्त कर लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख रुपए अर्जित करता है और किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा है तो उसे पुरानी व्यवस्था में 2,73,000 रुपए देने होते जबकि अब उसे मात्र 1,95,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस प्रकार उसका कर भार नई व्यवस्था में 78,000 रुपए कम हुआ है। वह नई व्यवस्था में तब भी लाभ में रहेगा भले ही वह पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के तहत 1.5 लाख रुपए की कटौती ले रहा हो।
- नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। कोई व्यष्टि जो वर्तमान में अधिनियम के तहत और अधिक कटौतियां और छूटें ले रहा है, उनका लाभ उठाने का विकल्प दे सकता है और पुरानी व्यवस्था में कर का भुगतान करना जारी रख सकता है।
- नई व्यक्तिगत आयकर दरों के लिए प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए का अनुमानित परित्यक्त राजस्व आवश्यक होगा। हमने आयकर विवरणी को समय-पूर्व करने के उपाय भी शुरू किए हैं ताकि नई व्यवस्था का विकल्प देने वाले व्यष्टि को अपनी विवरणी दायर करके और आयकर देने में किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।
- आयकर प्रणाली को सरल बनाने के लिए, मैंने विगत अनेक दशकों में आय कर कानून में समाविष्ट की गई सभी छूटों और कटौतियों की समीक्षा की है। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्तमान में आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकृति की एक सौ से अधिक छूटें और कटौतियां प्रदान की गई हैं। मैंने नई सरलीकृत व्यवस्था में इनमें से लगभग 70 को हटा दिया है। हम कर प्रणाली को और अधिक सरल बनाने और कर दर को कम करने के विचार से आने वाले वर्षों में शेष छूटों और कटौतियों की समीक्षा करेंगे और इन्हें युक्तिसंगत बनाएंगे।

**115. लाभांश वितरण कर**

- फिलहाल, कंपनियों को अपने शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश पर लागू अधिभार और उप कर सहित 15% की दर से लाभांश वितरण कर (डीडीटी) देना होता है और यह कर कंपनी द्वारा अपने लाभों पर देय कर के अतिरिक्त होगा।
- यह भी तर्क दिया गया है कि डीडीटी के उद्ग्रहण की प्रणाली के परिणामस्वरूप निवेशकों के कर भार में वृद्धि होती है, विशेषकर उनके लिए जिनकी लाभांश आय को उनकी आय में शामिल किया जाए तो उन्हें डीडीटी की दर से कम दर पर कर देना होता है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकांश विदेशी निवेशकों को उनके अपने देश में डीडीटी की अनुपलब्धता होने के परिणामस्वरूप उनके लिए इक्विटी पूंजी पर लाभ की दर में कमी आएगी। भारतीय इक्विटी बाजार को और आकर्षक बनाने तथा निवेशकों के बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए मैं लाभांश वितरण कर को हटाने का और लाभांश कराधान की क्लासिकल प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव करती हूँ जिसके तहत कंपनियों को डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभांश पर कर केवल प्राप्तकर्ताओं के हाथों में उनकी लागू दर पर ही लगाया जाएगा।
- आगे, करों के क्रम प्रपाती प्रभाव को दूर करने के लिए, मैं धारक कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी से प्राप्त किए गए लाभांश के लिए कटौती देने का भी प्रस्ताव करती हूँ। डीडीटी को हटाए जाने से 25,000 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक परित्यक्त राजस्व परिणत होगा।
- यह एक और साहसी कदम है जिससे भारत निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनेगा।

**116. विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए रियायती कर दर**

- विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, सितंबर 2019 में नए उपबंध शामिल किए गए थे जिनमें, विनिर्माण क्षेत्र में नई शामिल घरेलू कंपनियों, जो 31 मार्च, 2023 तक विनिर्माण प्रारंभ करेंगी, को 15% की रियायती कार्पोरेट कर दर पेश की गई है।
- विद्युत क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए, मैं विद्युत उत्पादन में लगी नई घरेलू कंपनियों को भी 15% की रियायती कार्पोरेट कर दर देने का प्रस्ताव करती हूँ।

**117. विदेशी निवेशों के लिए कर रियायत**

- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी सरकारों के सॉवरेन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनके द्वारा 31 मार्च, 2024 से पहले और न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ अवसंरचना और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100% कर छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ।
- विदेशी निधियों को कम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए, मैं ली गई उधार धनराशि और जारी किए गए बांडों के संबंध में गैर-निवासियों को ब्याज भुगतान के लिए धारा 194एलसी के तहत रोके रखने की 5% की रियायती दर की अवधि को 30 जून, 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।
- मैं भारतीय कंपनियों और सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा जारी बांडों के संबंध में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और योग्य (अर्हक) विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को ब्याज भुगतान के लिए धारा 194एलडी के तहत 5% की रोके रखने की निम्न दर की अवधि को भी 30 जून 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।
- मैं धारा 194एलडी के अंतर्गत 5 प्रतिशत की विदहोलिंग की रियायती दर म्यूनिसिपल बांडों पर किए गए ब्याज भुगतान पर भी लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- आईएफएससी एक्सचेंज पर बांडों के सूचीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उसके एक्सचेंज पर सूचीबद्ध बांडों पर ब्याज भुगतान की विदहोलिंग दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

**118. स्टार्ट-अप**

स्टार्ट अप हमारी अर्थव्यवस्था के विकास इंजिन के रूप में उभर कर आए हैं। पिछले वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने उनकी सहायता करने और उनके विकास को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं। अपने विकासात्मक वर्षों के दौरान स्टार्ट अप अत्यंत प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आम तौर पर एम्पलायी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) का प्रयोग करते हैं। ईएसओपी

इन कर्मचारियों के लिए प्रतिभूति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस समय, ईएसपीओ निष्पादन के समय पूर्वशर्त के रूप में करयोग्य है। इसके परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों के लिए नकद प्रवाह की समस्या उत्पन्न होती है जो अपने शेयर तत्काल नहीं बेचते और उन्हें लम्बे समय तक रखते हैं। स्टार्ट अप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मैं पांच वर्ष तक अथवा उनके द्वारा कंपनी छोड़े जाने अथवा उनके द्वारा अपने शेयर बेचे जाने तक, जो भी पहले हो, कर भुगतान को आस्थगित रखकर कर्मचारियों पर कराधान के बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ।

- इसके अतिरिक्त, 25 करोड़ रुपये का कुल कारोबार करने वाले पात्र स्टार्ट अप को यदि कुल कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो, तो सात वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए अपने लाभ की 100 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। बड़े स्टार्ट अप को यह लाभ देने के लिए मैं कुल कारोबार की सीमा मौजूदा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा, इस तथ्य को मानते हुए कि आरंभिक वर्षों में, इस कटौती का लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्टअप को पर्याप्त लाभ न हुआ हो, मैं कटौती के दावे की पात्रता अवधि बढ़ाकर मौजूदा 7 वर्ष से 10 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

#### 119. सहकारी संस्थाओं के लिए रियायती कर दर

- सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा देने, निविष्टियों की खरीद तथा उत्पादों के विपणन को आसान बनाकर हमारी अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में इन सहकारी संस्थाओं पर अधिभार और उपकर के साथ 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। बड़ी रियायत के तौर पर तथा सहकारी संस्थाओं और कारपोरेट के बीच समानता लाने के लिए, मैं इन संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर के साथ 22 प्रतिशत कर भुगतान का विकल्प होने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं जिस प्रकार कंपनियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम वैकाल्पिक कर (मैट) से छूट प्राप्त है, उसी प्रकार सहकारी संस्थाओं को वैकाल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट होने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

#### 120. मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई)

इस समय, एक करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालों को लेखापाल द्वारा अपनी बही खातों की लेखा परीक्षा करवाना अपेक्षित है। एमएसएमई क्षेत्र के छोटे खुदरा व्यापारियों, व्यवसायियों, दुकानदारों पर अनुपालन का भार कम करने के लिए, मैं लेखापरीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में पांच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूँ। लेस कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वर्धित सीमा केवल उन व्यवसायियों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेनेदेन में 5 प्रतिशत से कम नकद का प्रयोग करते हैं।

#### 121. सस्ते मकान

- 'सभी के लिए आवास' तथा सस्ते मकानों का लक्ष्य हासिल करने के लिए, मैंने पिछले बजट में सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर प्रदत्त ब्याज हेतु एक लाख पचास हजार रुपये तक अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। यह कटौती 31 मार्च, 2020 या पहले स्वीकृत किए गए आवास ऋणों पर दी गई थी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकाधिक व्यक्ति इसका लाभ उठाएं और सस्ते मकानों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इस अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने के लिए ऋण स्वीकृति की तिथि में एक वर्ष की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करती हूँ।
- इसके अतिरिक्त, देश में सस्ते आवासों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित सस्ते आवास की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान है। सस्ते आवास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, मैं इस टैक्स हॉलिडे का लाभ उठाने के लिए सस्ते आवास की परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि में एक वर्ष की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूँ।

#### 122. स्थावर संपदा लेनदेनों को रियायत

- इस समय, स्थावर संपदा में लेनदेन के संबंध में पूंजी लाभ, व्यवसाय लाभ तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर कर आरोपित करते समय यदि विचाराधीन मूल्य सर्किल दर की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक है, तो इस अंतर को क्रेता और विक्रेता दोनों की आय मानी जाती है। स्थावर संपदा लेनदेन में कठिनाइयों को कम करने तथा इस क्षेत्र को राहत देने के लिए, मैं यह सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**123. धर्मार्थ संस्थाएं**

- समाज में धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए, इन संस्थानों की आय को कराधान से पूर्ण छूट प्राप्त है। इसके अलावा, इन संस्थाओं को किए गए दान की भी दानकर्ता की कर योग्य आय का परिकलन करने में कटौती के रूप में अनुमति है।
- इस समय, करदाता को कटौती का लाभ उठाने के लिए आयकर विवरण में दान लेने वाले का पूर्ण ब्यौरा देना अनिवार्य है।
- दान के लिए कटौती का दावा करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए, दानप्राप्त कर्ता द्वारा प्रस्तुत दानों की सूचना के आधार पर करदाता की विवरणी में दानकर्ता की पूर्व सूचना देने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे करदाता द्वारा किए गए दान के लिए कटौती का दावा करना आसान होगा।
- इसके अलावा, कर छूट का दावा करने के लिए धर्मार्थ संस्थाओं को आयकर विभाग के साथ पूंजीकरण करना होता है। विगत में, पूंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः हस्तचालित होती थी और देशभर में फैली हुई थी।
- नई और मौजूदा धर्मार्थ संस्थाओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए, मैं पूंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णरूप से इलेक्ट्रॉनिक करने का प्रस्ताव करती हूँ जिसके अंतर्गत सभी नई और मौजूदा धर्मार्थ संस्थाओं को एक विशिष्ट पूंजीकरण संख्या (यूआरएन) जारी की जाएगी। इसके अलावा, उन नई धर्मार्थ संस्थाओं जिन्होंने अपनी धर्मार्थ गतिविधियां आरंभ नहीं की हैं, के पूंजीकरण को आसान बनाने के लिए, मैं उन्हें तीन वर्षों के लिए अनन्तिम पूंजीकरण की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ।

**124. फेसलेस अपीलें**

हमारी सरकार रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने के प्रति वचनबद्ध है ताकि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप से अधिकतम अभिशासन प्रदान किया जा सके। निर्धारण प्रक्रिया में अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नई फेसलेस निर्धारण स्कीम पहले ही आरंभ की जा चुकी है। इस समय, विवरण का प्रस्तुतीकरण, विवरणियों की प्रोसेसिंग, धन वापसी तथा निर्धारण जैसे आयकर विभाग के अधिकांश कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक मोड में निष्पादित किए जाते हैं। आयकर विभाग द्वारा आरंभ किए गए सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने तथा मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए, मैं आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की जा सके।

**125. 'विवाद से विश्वास' स्कीम**

- महोदय, विगत में हमारी सरकार ने कर से संबंधित मुकदमेबाजी कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले बजट में, अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए सबका विश्वास स्कीम लाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस समय, विभिन्न अपीलिय मंचों अर्थात् आयुक्त (अपील)आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं। इस वर्ष, मैं प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष कर की सबका विश्वास की तरह एक स्कीम लाने का प्रस्ताव करती हूँ।
- प्रस्तावित 'विवाद से विश्वास' स्कीम के अंतर्गत करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और उसे ब्याज और दंड से पूर्ण माफी मिलेगी बशर्ते वह 31 मार्च 2020 तक भुगतान करता हो। जो 31 मार्च 2020 के पश्चात् इस स्कीम का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह स्कीम 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी।
- जिन करदाताओं के अपील के मामले किसी स्तर पर लंबित हैं, वे इस स्कीम से लाभ उठा सकते हैं।
- मैं आशा करती हूँ कि करदाता मुकदमे की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे।

**126. विलयित बैंकों की हानियां**

- वित्तीय क्षेत्र के समेकन के भाग के रूप में, हमारी सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय की योजनाएं लेकर आई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलित प्रतिष्ठान, समामेलित प्रतिष्ठानों की अंतर्लीन न की गई हानियों और मूल्यहास का लाभ उठा सकें, मैं, आयकर अधिनियम के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ।

#### 127. करदाता चार्टर

- किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव होगा जब करदाताओं के अधिकार की स्पष्ट रूप से गणना की जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और आयकर की सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए करदाता चार्टर को अपनाना अधिदेशित करने के लिए मैं, आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ। चार्टर में निहित विषयों का ब्यौरा जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

#### 128. आधार के द्वारा तुरन्त पैन

- पिछले बजट में, मैंने पैन और आधार के परस्पर बदले जाने की संभावना लायी थी जिसके लिए आवश्यक नियम पहले ही अधिसूचित किए गए। पैन के आबंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए जल्दी ही हम एक प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने की किसी आवश्यकता के बगैर आधार के आधार पर तुरन्त ही ऑनलाइन पैन का आबंटन किया जाएगा।

129. हमारी सरकार 2017 में प्रत्यक्ष कर के ऐतिहासिक सुधार के रूप में जीएसटी लायी है। सितंबर 2019 में हमने कारपोरेट कर के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण के अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। इससे भी अधिक हमने कारपोरेट कर की ऐसी दर की पेशकश की, जो विश्व में संभवतः सबसे कम है। इस मार्ग पर चलते हुए हमने अब व्यैक्तिक आयकर को इसके सबसे कम दर पर रखा है और कंपनी के हाथों में डीडीटी को पूरी तरह हटा दिया है। इसके अतिरिक्त अब प्रत्यक्ष कर सबसे कम, सरल और निर्बाध है। स्टार्ट-अप्स पर प्रत्यक्ष कर में बहुत जल्दी-जल्दी बहुत से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। यहां तक कि अनुपालना आसान बनाने में भी अभूतपूर्व बदलाव किए जा रहे हैं। अंतिम बात यह है कि कर प्रशासन के साथ व्यक्तिगत अन्तरामुख सब से कम है।

#### अप्रत्यक्ष कर

130. जैसाकि मैंने अपने भाषण के भाग क में उल्लेख किया है, जीएसटी में सुधार जारी हैं। 1 अप्रैल, 2020 से सरलीकृत विवरणी का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है। यह विवरणी फाइल करना सरल बनाएगा, इसकी विशेषताओं में शून्य विवरणी के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, विवरणी पूर्व फाइलिंग उन्नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण हैं।

131. वापसी की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और मानव अन्तरामुख के बिना इसे पूर्णतया स्वचलित किया गया है।

132. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस दूसरा नवोन्मेष है जिसमें केन्द्रीयकृत प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचना जुटाई जाएगी। इसको वैकल्पिक आधार पर इसी महीने से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इससे अनुपालना और विवरणी फाइलिंग सुसाध्य होगा।

133. अनुपालना में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। करदाताओं का आधार के अनुसार सत्यापन शुरू किया जा रहा है। इससे डमी या अस्तित्व में न रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता इनवॉइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है। जब क्यूआर-कोड के जरिए खरीद हेतु भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा। इनवॉइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। डीप डाटा एनालिटिक्स और एआईटूल्स का जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट, वापसी और अन्य धोखा धड़ी का सफाया करने और उन लोगों को जो प्रणाली के साथ छल-कपट करने के प्रयास कर रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इनवॉइस और इनपुट कर क्रेडिट मैचिंग किया जा रहा है जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक बैमेल विवरणियां पाई जाती हैं। न्यूनतम सीमाओं की पहचान की जाती है और अनुशीलन किया जाता है। महत्वपूर्ण नीतिस्तर के परिवर्तन भी किए गए हैं। जीएसटी दर संरचना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है जिससे कि इनवर्टेड ड्यूटी संरचना जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

134. सीमाशुल्क के लिए व्यावसाय आसान बनाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। सीमा पर भारत के व्यापार में प्रमात्रात्मक बढ़ोतरी, व्यवसाय करना आसान बनाने के मानदंड का विश्व बैंक द्वारा रैंकिंग इन प्रयासों का साक्ष्य है। इस मानदंड पर भारत का रैंक 2018 में 146वां से सुधरकर 80 पर आ गया और 2019 में और अधिक सुधरकर 68वां हो गया। हमारे घरेलू विनिर्माताओं, विशेषकर एमएसएमई सेक्टर और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक समान कार्य क्षेत्र मुहैया कराने हेतु उपाय भी किए गए हैं।

**135.** यह देखा गया है कि मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के तहत आयात बढ़ रहे हैं। घरेलू उद्योग के लिए एफटीए लाभों के अनुचित दावे खतरा बन गए हैं। ऐसे आयात के लिए कड़ी जांच करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सीमा शुल्क अधिनियम में उपयुक्त उपबंध समाहित किए जा रहे हैं। आगामी माह में, हम मूल उद्गम की आवश्यकताओं संबंधी नियमावली की समीक्षा करेंगे, विशेषकर कतिपय संवेदनशील मदों के लिए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफटीए हमारी नीति की सचेतन दिशा के अनुरूप हैं।

**136.** कर्तव्यों के रक्षोपाय संबंधी उपबंधों को हम सुदृढ़ कर रहे हैं, जिन्हें आयात में अत्यधिक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर आघात पहुंचने पर लागू किया जाता है। संशोधित उपबंध व्यवस्थित रूप से आयात में अत्यधिक वृद्धि को विनियमित करने में समर्थ बनाएंगे। माल के पाटन को नियंत्रित करने और सब्सिडी प्राप्त माल के आयात के लिए उपबंधों को घरेलू उद्योग हेतु एक समान कार्य क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाओं की तर्ज पर किए जा रहे हैं।

**137.** जनहित में, समय-समय पर सीमाशुल्क से छूट दी गई है। तथापि, इनमें से अनेक का उपयोग अब नहीं हो रहा है या वे अप्रचलित हो चुके हैं। समीक्षा करने पर, ऐसी कतिपय छूटों को वापस लिया जा रहा है। शेष सीमा शुल्क छूटों की, उनकी प्रासंगिकता को देखने के लिए सितंबर 2020 तक व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसी समीक्षाओं के लिए मैं क्राउड सोर्स सजेशनस का प्रस्ताव रखती हूं। सीमाशुल्क विधानों और उन्हें बदलते समय तथा व्यावसाय करना आसान बनाने की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के संबंध में सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे।

**138.** एमएसएमई में, श्रम गहन सेक्टर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके विकास के लिए सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले आयात अड़चन हैं। ऐसे मदों के आयात पर नियंत्रण के उपाय करने के लिए ध्यान दिया गया है जिनका उत्पादन बेहतर गुणवत्ता के साथ हमारे एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। इस सेक्टर की आवश्यकता को देखते हुए फुटवियर और फर्नीचर जैसी मदों पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है।

**139.** हमारी मेक इन इंडिया नीति में लाभांश देना शुरू हो गया है। भारत अब विश्व स्तरीय माल बना रहा है और वैसे माल का निर्यात कर रहा है। हमने चिकित्सा उपकरणों में भी काफी प्रगति की है। कुछ वर्ष पहले तक चिकित्सा उपकरणों के लिए आयातों पर निर्भर रहे थे। अब, हम न केवल चिकित्सा उपकरण का विनिर्माण कर रहे हैं अपितु बड़ी मात्रा में उनका निर्यात भी कर रहे हैं। यह सेक्टर और अधिक बढ़ावा देने योग्य है। सरकार सबके लिए स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत ने इसे संभव बनाया है। घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधन उत्पन्न करने के दोहरे उद्देश्य को हासिल करने के लिए, इस बात को देखते हुए कि अब ये माल भारत में काफी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, मैं, चिकित्सा उपकरण के आयातों पर सीमाशुल्क के द्वारा मामूली स्वास्थ्य उपकरण लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इस उपकरण से प्राप्त आय का उपयोग महत्वकांक्षी जिलों में चिकित्सा सेवाओं के लिए अवसंरचना बनाने में किया जाएगा।

**140.** मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके घटकों जैसी मदों के लिए सुनिर्धारित सीमाशुल्क दरों की पूर्व घोषणा की गई है। इससे भारत में घरेलू मूल्यवर्धन क्षमता में धीरे-धीरे वृद्धि सुनिश्चित हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों, और मोबाइल के पार्ट्स पर ऐसी सावधानी पूर्वक बनाई गई चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के भाग के रूप में, सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जा रहा है।

**141.** अन्य परिवर्तनों में, कतिपय निविष्टियों और कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है जबकि कतिपय माल पर इसे बढ़ाया जा रहा है, जिनको देश के भीतर बनाया जा रहा है। पिछले बजट में, न्यूज प्रिंट और हल्के कोटिड कागज पर 10% बुनियादी सीमा शुल्क लगाया गया था। तथापि, तब से, मैंने अनेक प्रसंग प्राप्त किया है कि इस लेवी से उस समय प्रिंट मीडिया पर अतिरिक्त भार पड़ा है जब यह कठिन दौर से गुजर रहा है। इसलिए मैं, न्यूज प्रिंट और हल्के कोटिड कागज के आयात पर बुनियादी सीमाशुल्क घटाकर 10% से 5% करने का प्रस्ताव करती हूं।

**142.** निचले प्रयोक्ताओं के लिए रसायन महत्वपूर्ण फीड स्टॉक हैं। उदाहरण के लिए पीटीए वस्त्र रेशा और सूत के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि है। वस्त्र के क्षेत्र में अपार संभावना को भुनाने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इसकी सहज उपलब्धता वांछनीय है, जो एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजक है। इसलिए, सार्वजनिक हित में पीटीए पर पाटन रोधी शुल्क को समाप्त किया जा रहा है।

**143.** राजस्व उपायों के रूप में, मैं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा और आकस्मिक शुल्क के द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। फिर भी, बीड़ी की शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

**144.** अंततः कर सुधार को जारी रखना सतत चुनौती है और हम उसको पूरे जोश के साथ अनुसरण करने का प्रस्ताव करते हैं।

**145.** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मेरे बजट प्रस्ताव का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध में है।

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव (बजट)

अनुबंध I

## महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट परिव्यय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	नाम	ब.अ. 19-20	सं.अ. 19-20	ब.अ. 20-21
<b>I</b>	<b>महत्वाकांक्षी भारत</b>	<b>4,67,517</b>	<b>4,36,913</b>	<b>4,82,401</b>
क	कृषि एवं संबद्ध, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास	2,76,380	2,49,910	2,83,202
ख	आरोग्यता, जल, स्वच्छता	93,294	89,618	96,885
ग	शिक्षा एवं कौशल विकास	97,843	97,385	1,02,314
<b>II</b>	<b>आर्थिक विकास</b>	<b>2,23,695</b>	<b>2,24,941</b>	<b>2,37,604</b>
क	उद्योग एवं वाणिज्य	27,043	28,608	27,227
ख	ऊर्जा	1,57,437	1,58,207	1,69,637
		39,215	38,127	40,740
<b>III</b>	<b>नई अर्थव्यवस्था</b>	<b>40,534</b>	<b>34,724</b>	<b>42,852</b>
क	सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	19,127	18,979	20,379
ख	संचार (भारत नेट)	8,350	3,000	8,000
ग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13,056	12,745	14,473
<b>IV</b>	<b>जिम्मेदार समाज</b>	<b>59,036</b>	<b>54,831</b>	<b>62,626</b>
क	महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण	50,850	48,210	53,876
ख	संस्कृति एवं पर्यटन	5,232	3,963	5,650
ग	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	2,955	2,658	3,100
<b>V</b>	<b>वित्तीय क्षेत्र</b>	<b>19,002</b>	<b>23,686</b>	<b>40,433</b>
क	बैंकिंग, बीमा, वित्तीय बाजार और अवसंरचना वित्त	19,002	23,686	40,433



## अनुबंध II

## महत्वपूर्ण योजनाओं को आबंटन

(₹ करोड़)

क्र.सं.	नाम	ब.अ. 19-20	सं.अ. 19-20	ब.अ. 20-21
1	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9,200	9,200	9,197
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	60,000	71,002	61,500
3	अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रैला योजना	5,445	5,568	6,242
4	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रैला कार्यक्रम	3,810	4,194	4,191
5	अल्प संख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रैला कार्यक्रम	1,590	1,709	1,820
6	अन्य असुरक्षित समूहों के लिए अम्ब्रैला कार्यक्रम	1,818	1,846	2,210
7	राष्ट्रीय गंगा योजना	750	353	800
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000	14,070	19,500
10	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	25,853	25,328	27,500
11	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	10,001	10,001	11,500
12	स्वच्छ भारत मिशन	12,644	9,638	12,294
13	राष्ट्रीय स्वस्थ मिशन	33,651	34,290	34,115
14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-समग्र शिक्षा	38,547	37,672	39,161
15	पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत	6,556	3,314	6,429
16	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	75,000	54,370	75,000
17	दीन दयाल अंत्योदया योजना राष्ट्रीय अजीविका मिशन-आजीविका	9,774	9,774	10,005
18	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	4,000	4,733	6,020
19	अम्ब्रैला एकीकृत बाल विकास योजना कार्य एवं कौशल विकास	27,584	24,955	28,557
20	स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	11,000	9,912	11,000

## अनुबंध III

## राज्यों और विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	नाम	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
<b>I.</b>	<b>करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण</b>	<b>8,09,133</b>	<b>6,56,046</b>	<b>7,84,181</b>
<b>II.</b>	<b>अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें</b>	<b>54,581</b>	<b>57,344</b>	<b>73,275</b>
1.	एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	10,000	20,000	25,000
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन	392	380	407
3.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	4,500	3,000	4,000
4.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-ऋण	19,723	25,000	25,000
5.	पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	326	324	287
6.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के तहत योजनाएं	2,321	2,321	1,199
7.	मांग के अंतर्गत विशेष सहायता-राज्यों का अंतरण	15,000	4,000	15,000
8.	मांग-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति को विशेष केन्द्रीय सहायता	1,074	1,074	1,172
9.	मांग-जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता	1,245	1,245	1,210
<b>III.</b>	<b>वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>1,20,466</b>	<b>1,23,710</b>	<b>1,49,925</b>
1.	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान-ग्रामीण निकाय	52,558	58,616	69,925
2.	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	23,359	25,843	30,000
3.	एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	10,344	10,938	20,000
4.	अंतरण पश्च राजस्व घाटा अनुदान	34,206	28,314	30,000
<b>IV.</b>	<b>राज्यों को कुल अंतरण [(I) + (II) + (III) को छोड़कर]</b>	<b>3,35,220</b>	<b>3,22,443</b>	<b>3,35,878</b>
1.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	2,92,003	2,83,057	2,95,269
2.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत	42,076	38,227	39,451
3.	व्यय की अन्य श्रेणी के अंतर्गत (राजस्व)	1,033	1,055	1,066
4.	पूंजी अंतरण	109	104	93
<b>V.</b>	<b>दिल्ली और पुडुचेरी की कुल अंतरण</b>	<b>10,028</b>	<b>28,419</b>	<b>47,408</b>
1.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	2,026	1,999	5,603
2.	केन्द्रीय क्षेत्र के स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	89	222	299
3.	व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)	7,613	25,972	41,355
4.	पूंजी अंतरण	300	225	150
	<b>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण</b>	<b>13,29,428</b>	<b>11,87,961</b>	<b>13,90,666</b>

## अनुबंध IV

## प्रमुख मंत्रालय/विभागों को आबंटन

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
1	कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	1,30,485	1,01,904	1,34,400
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	8,079	7,846	8,363
3	परमाणु ऊर्जा	16,926	17,426	18,229
4	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	1,940	1,857	2,122
5	उर्वरक विभाग	80,035	80,035	71,345
6	नागर विमानन मंत्रालय	4,500	3,700	3,798
7	वाणिज्य विभाग	6,219	7,219	6,219
8	औद्योगिक तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	5,675	6,490	6,606
9	डाक विभाग	11,299	12,398	15,525
10	दूरसंचार विभाग	27,338	23,350	66,432
11	उपभोक्ता मामले विभाग	2,272	2,050	2,300
12	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,92,240	1,15,240	1,22,235
13	संस्कृति मंत्रालय	3,042	2,547	3,150
14	रक्षा सेवा (राजस्व)	2,01,902	2,05,902	2,09,319
15	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	1,03,394	1,10,394	1,13,734
16	रक्षा पेंशन	1,12,080	1,17,810	1,33,825
17	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	3,000	2,670	3,049
18	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,902	1,810	2,070
19	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6,654	5,839	6,899
20	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2,955	2,658	3,100
21	विदेश मंत्रालय	17,885	17,372	17,347
22	आर्थिक कार्य विभाग	14,312	15,952	29,308
23	वित्तीय सेवा विभाग	4,690	7,734	11,125
24	राजस्व विभाग	1,02,048	1,22,066	1,36,640
25	ब्याज अदायगियां	6,60,471	6,25,105	7,08,203
26	पेंशन	48,565	50,565	61,169
27	राज्यों को अंतरण	1,55,447	1,55,447	2,00,447
28	मत्स्य पालन विभाग	805	700	825
29	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	2,932	2,790	3,289
30	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,197	1,043	1,233
31	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	62,659	62,659	65,012
32	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,900	1,950	2,100
33	लोक उद्यम विभाग	23	23	23

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
34	गृह मंत्रालय	4,896	19,955	8,002
35	लद्दाख	...	...	5,958
36	जम्मू और कश्मीर को अंतरण	...	...	30,757
37	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	48,032	42,267	50,040
38	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	56,537	56,537	59,845
39.	उच्चतर शिक्षा विभाग	38,317	38,317	39,467
40.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,375	4,065	4,375
41.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8,245	7,518	8,960
42.	पेय जल और स्वच्छता विभाग	20,016	18,360	21,518
43.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	11,184	11,184	12,065
44.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	7,011	7,011	7,572
45.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	4,700	4,700	5,029
46.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5,255	3,892	5,753
47.	पंचायती राज मंत्रालय	871	500	901
48.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	42,901	42,901	42,901
49.	विद्युत मंत्रालय	15,875	15,875	15,875
50.	रेल मंत्रालय	68,019	69,967	72,216
51.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83,016	83,016	91,823
52.	ग्रामीण विकास विभाग	1,17,647	1,22,649	1,20,147
53.	भू-संसाधन विभाग	2,227	1,900	2,251
54.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	5,580	5,481	6,302
55.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2,580	2,381	2,787
56.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4,896	4,883	5,385
57.	पोत परिवहन मंत्रालय	1,903	1,523	1,800
58.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2,989	2,531	3,002
59.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	8,885	8,885	10,104
60.	निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग	1,205	1,100	1,325
61.	अंतरिक्ष विभाग	12,473	13,139	13,479
62.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,231	5,231	5,444
63.	वस्त्र मंत्रालय	4,831	4,831	3,515
64.	पर्यटन मंत्रालय	2,189	1,416	2,500
65.	जनजाति मामले मंत्रालय	6,895	7,340	7,411
66.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	29,165	26,185	30,007
67.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,217	2,777	2,827

## अनुबंध V

अतिरिक्त बजटीय और अन्य संसाधन से संबंधित विवरण (सरकार द्वारा पूर्ण रूप से शोधित बांड, एनएसएसएफ आदि)

भाग-क - सरकार द्वारा पूरी तरह से शोधित बांडों के निर्गमन के जरिए जुटाई गई ईबीआर (₹ करोड़)

मांग सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम तथा योजना का नाम	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
42.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	5,000.00	2,700.00	3,000.00
57.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय			
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	20,000.00	10,000.00	10,000.00
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग			
	उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (राइज)	5,000.00	1,000.00	3,000.00
61.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग			
	(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना	—	1,85.00	
	(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एआईबीपी एवं अन्य परियोजनाएं)	4,882.00	3,033.96	5,000.00
62.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय			
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	5,000.00	5,000.00	0.00
	(ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	6,300.00	2,000.00	12,000.00
70.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
	प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	822.00	500.00	1,000.00
77.	विद्युत मंत्रालय			
	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	9,000.00	8,500.00	5,500.00
85.	ग्रामीण विकास विभाग			
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	—	10,000.00	10,000.00
90.	पोत परिवहन मंत्रालय			
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) परियोजनाएं	1,000.00	—	—
जोड़:		57,004.00	44,583.96	49,500.00

भाग- ख - एनएसएसएफ से ऋणों के जरिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम/निकाय का नाम	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
1.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	—	1,10,000.00	1,36,600.00
	भारतीय खाद्य निगम			
2.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	—	15,000.00	—
	भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)			
3.	उर्वरक विभाग			
	(i) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	—	1,805.00	—
	(ii) धातु एवं खनिज व्यापार निगम	—	1,310.00	—
	जोड़:	—	1,28,115.00	1,36,600.00
	कुल जोड़ (क + ख)	57,004.00	1,72,698.96	1,86,100.00

## टिप्पणियां:

- (i) सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 में दर्शाए गए अनुसार एनएसएसएफ के जरिए वित्तीय सहायता का अनुमान इन वर्षों के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रस्तावित निधियों (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में एनएसएसएफ ऋणों की चुकौती सहित) के लिए कुल आवश्यकता और सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 में किए गए बजटीय प्रावधान के बीच अंतर के आधार पर लगाया गया है।
- (ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूँजी प्रदान करना: सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी विनियामक पूँजी, वर्धित पूँजी और त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) को वांछनीय स्तरों पर बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए उनके पूँजीकरण के लिए 2017-18 में 80,000 करोड़ रुपए और 2018-19 में 1,06,000 करोड़ रुपए की सीमा तक पूँजी प्रदान की गई थी। इस प्रयोजनार्थ, 2019-20 में भी 70,000 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल, एक नियत कूपनधारक भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए पूँजी प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष में, अब तक सरकार की नई पूँजी के रूप में 64,612 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध वरुआई गई है।
- (iii) वार्षिकी परियोजनाओं के संबंध में देयता का विवरण प्राप्ति बजट 2020-21 के भाग - ख में दिया गया है।

## प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

## 1. कर प्रोत्साहन

- 1.1 वैयक्तिक आय-कर में राहत और कराधान का सरलीकरण: राहत पहुँचाने और कराधान व्यवस्था का सरलीकरण करने के उद्देश्य से, व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब यदि विनिर्दिष्ट छूटों/कटौतियों को प्राप्त नहीं करता है तो उन्हें निम्नलिखित अपेक्षाकृत कम दरों पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है:

कुल आय (₹)	दर (%)
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5
5,00,001 से 7,50,000 तक	10
7,50,001 से 10,00,000 तक	15
10,00,001 से 12,50,000 तक	20
12,50,001 से 15,00,000 तक	25
15,00,000 से ऊपर	30

अधिभार और उपकर मौजूदा दरों पर लगने जारी रहेंगे।

- 1.2 सहकारी समितियों के लिए राहत और सरलीकरण: राहत देने और कराधान व्यवस्था के सरलीकरण के उद्देश्य से, सहकारी समितियाँ यदि कतिपय विनिर्दिष्ट कटौतियों/छूटों को प्राप्त नहीं करती हैं, तो उनपर 22% जमा 10% अधिभार जमा 4% उपकर के अनुसार कर लगाने का विकल्प उन्हें दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इन सहकारी समितियों को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट दी जाए।
- 1.3 विदेशी निवेश के लिए कर रियायत: अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी कंपनी सहित सॉवरेन धन निधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ और अवसंरचना सेक्टर अथवा अन्य पात्र अधिसूचित सेक्टरों में 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए निवेश के संबंध में, कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सॉवरेन धन निधि तथा एडीआईए की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी कंपनी के ब्याज, लाभांश और पूंजी लाभ से हुई आय को कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 1.4 लाभांश वितरण कर समाप्त करना: वर्तमान में, लाभांश वितरित करने वाली कंपनी के लाभांश पर कर लगाया जाता है। यह अन्यायकारी पाया गया। शेयरधारकों के लाभांश पर कर लगाने की पारंपरिक प्रणाली पर लौटने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 1.5 आईएफएससी, म्युनिसिपल बांड और विदेशी उधारों के लिए प्रोत्साहन: विदेशों से लिए गए उधारों के लिए वर्तमान में धारा 194उग और 194उघ के अंतर्गत उपलब्ध पांच प्रतिशत की रियायती दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की व्यवस्था 30 जून, 2023 तक और तीन वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2020 तक या उसके बाद किन्तु 01 जुलाई, 2023 से पहले लिए गए नए विदेशी उधारों पर विदेशी उधारों पर विदेशी उधारों को चार प्रतिशत पर रखा जाए, जो किसी भी आईएफएससी में स्थित अभिज्ञात स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीबद्ध हो।
- 1.6 सस्ते आवासन को प्रोत्साहन: सम्प्रति, सस्ता आवास खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक स्वीकृत ऋणों पर अदा किए गए ब्याज के लिए एक लाख पचास हजार रुपये तक की अतिरिक्त कटौती अनुमत है। सस्ते आवास की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृति की तारीख 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है। अतः यह कटौती 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत आवास ऋणों के संबंध में भी उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, देश में सस्ते आवासों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित सस्ते आवास परियोजना के विकासकों द्वारा अर्जित लाभों पर कर अवकाश प्रदान किया गया। सस्ते आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सस्ते आवास परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीख बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 तक अनुमोदित सस्ते आवास परियोजनाओं के विकासक भी कर अवकाश प्राप्त कर सकते हैं।

- 1.7 रियल एस्टेट सेक्टर को रियायत: वर्तमान में, अचल सम्पत्ति के अंतरण के संबंध में जहां प्रतिफल सर्किल दर से कम है, आय का परिकलन के लिए 5% तक राशि सुरक्षित रखनी अनुमत है। आवास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 1.8 स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन: स्टार्ट-अप के कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) प्रदान करते हुए अपेक्षाकृत कम वेतन पर अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नियोजित करने के लिए स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्ट-अप्स द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई इन एसओपी पर कर भुगतान पांच वर्ष अथवा कर्मचारी द्वारा कंपनी छोड़ने अथवा उक्त कर्मचारी द्वारा उन शेयरों को बेचने तक, जो भी पहले हो, स्थगित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।  
बड़े स्टार्ट-अप्स को कर अवकाश का लाभ देने के लिए, कर अवकाश का दावा करने हेतु न्यूनतम कारोबार को ₹25 करोड़ से ₹100 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अलावा, स्टार्ट-अप्स जिन्हें इस अवकाश को प्राप्त करने के लिए आरंभिक वर्षों में पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, उनकी चिंताओं के निराकरण के लिए, 100% कटौती का दावा करने के लिए पात्रता की अवधि मौजूदा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 1.9 अगले लाभ से हानि-पूर्ति या कतिपय आमेलनों में मूल्यह्रास अनुमत करना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि आमेलित सरकारी क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियां अनावशेषित हानियों और आमेलित इकाइयों के मूल्यह्रास का लाभ ले सकें, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 1.10 "व्यापार न्यास" की परिभाषा को व्यापक बनाना: असूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास (इन्वआईटी) अथवा स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) को प्रोत्साहित करने के लिए, असूचीबद्ध आरईआईटी और इन्वआईटी को वही कराधान व्यवस्था देने का प्रस्ताव किया जाता है जो सूचीबद्ध इन्वआईटी और आरईआईटी को दी जाती है।
- 1.11 इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को छूट: तीन वर्ष के भीतर कच्चे तेल की पुनःपूर्ति की शर्त के अधीन इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में अपनी भण्डारण सुविधा में रखे गए कच्चे तेल की पुनःपूर्ति की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत अथवा सृजित आय के संबंध में इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 1.12 विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए रियायती कर दर: विद्युत सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त कार्पोरेट कर की रियायती 15% दर विद्युत उत्पादन में कार्यरत उन नई घरेलू कंपनियों को इस शर्त के अधीन देने का प्रस्ताव किया जाता है कि वे विद्युत उत्पादन 31 मार्च, 2023 तक करना प्रारंभ कर देंगी।
- 2. कर निश्चितता प्रदान करने के उपाय**
- 2.1 सेफ हार्बर नियमों का दायरा बढ़ाना तथा उन्नत कीमत निर्धारण करार: स्थायी स्थापना (पीई) को लाभ सौंपने के मामले में करदाताओं को कर निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से, यह व्यवस्था करते हुए कि पीई को लाभ देने का निर्धारण सेफ हार्बर व्यवस्था (एसएचआर) और उन्नत कीमत निर्धारण करार (एपीए) के दायरे के अंतर्गत भी किया जाएगा, एपीए और एसएचआर का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 2.2 बीमा कंपनियों को कटौती का औचित्यस्थापन: यह प्रस्ताव किया जाता है कि सांविधिक देयताओं की विलंब से अदायगी के लिए बीमा कंपनियों को खर्च करने के अनुमति नहीं दी गई थी, उसकी अनुमति भुगतान करने के वर्ष में देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 2.3 स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दर में कटौती: मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए, तकनीकी सेवाओं (व्यवसायिक सेवाओं से अन्य) के लिए शुल्कों के मामले में टीडीएस के लिए दर मौजूदा दस प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि टीडीएस और कार्य संविदा की दर एकसमान हो जाए।
- 2.4 विवाद से विश्वास स्कीम: प्रत्यक्ष कर संबंधी मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए एक स्कीम लाने का प्रस्ताव है। यह स्कीम 30 जून, 2020 तक खुली रहेगी। करदाता जिनके मामले में किसी भी स्तर पर अपीलें लम्बित हैं; वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्कीम के तहत, करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा और कोई भी ब्याज तथा शास्ति नहीं देनी पड़ेगी, बशर्ते कि वे 01 अप्रैल, 2020 से पहले भुगतान कर दें। विवादित कर से असंबद्ध विवादित शास्ति, ब्याज और शुल्क के लिए, विवाद का निपटान करने के लिए करदाता को केवल 25% राशि अदा करना आवश्यक होगा यदि स्कीम के अंतर्गत, भुगतान 01 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात किया गया है तो करदाता को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

**3. कर आधार को व्यापक बनाना और उसका सघनीकरण**

- 3.1 ई-कॉमर्स संव्यवहारों पर टीडीएस: कराधार को व्यापक और सघन करने के उद्देश्य से, पैन/आधार वाले मामलों में 1% की दर से और पैन/आधार रहित मामलों में 5% की दर से ई-कॉमर्स ऑपरेटर सभी भुगतानों पर अथवा ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को ऋणों पर टीडीएस काटने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए व्यष्टि और एचयूएफ जो ₹5 लाख से कम राशि प्राप्त करता है, द्वारा पैन/आधार प्रस्तुत करने पर उसको छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 3.2 ब्याज पर टीडीएस का दायरा बढ़ाना: कतिपय बड़ी सहकारी सोसायटियां जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में सकल प्राप्तियां ₹पचास करोड़ से अधिक हैं, को अदायगी पर ब्याज पर टीडीएस काटने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 3.3 टीसीएस का दायरा बढ़ाना: भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण स्कीम के अंतर्गत वर्ष में सात लाख रुपये से अधिक राशि विप्रेषित करने पर और विदेशी यात्रा पैकेज की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विक्रेता, जिसका कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक है, द्वारा वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान की बिक्री करने पर भी टीसीएस का प्रस्ताव किया जाता है।
- 3.4 कतिपय निधियों में नियोक्ता द्वारा अंशदान की छूट की सीमा: मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधि और राष्ट्रीय पेंशन निधि में नियोक्ता द्वारा कर छूट प्राप्त अंशदान पर वर्ष में ₹सात लाख और पचास हजार की ऊपरी सीमा कर्मचारियों के खाते में लगाने का प्रस्ताव किया जाता है।

**4. कर प्रशासन की प्रभावकारिता में सुधार**

- 4.1 फेसलेस अपील: निर्धारण प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से नई फेसलेस निर्धारण स्कीम की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली से मानव अंतरापृष्ठ समाप्त कर विभाग द्वारा शुरू किए गए सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की शुरुआत करने के लिए समर्थकारी अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 4.2 विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) का दायरा बढ़ाना: सभी अनिवासियों को पात्र निर्धारिता के रूप में सम्मिलित करते हुए डीआरपी के संदर्भों का दायरा बढ़ाने तथा यह स्पष्ट करने के लिए कि सभी वैभिन्न्य जो निर्धारिता के प्रतिकूल हैं, डीआरपी के दायरे के भीतर होंगे, डीआरपी के संदर्भों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 4.3 करदाता का चार्टर: आयकर विभाग की सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीबीडीटी करदाता के चार्टर को अंगीकार करे और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निदेश जारी करे।
- 4.4 फेसलेस निर्धारण के दायरे में संशोधन: उन मामलों को सम्मिलित करने के लिए, जिनमें निर्धारण एकपक्षीय रूप से पूरा किया जा रहा है, फेसलेस निर्धारण का दायरा संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

**5. अनुपालन की सुगमता**

- 5.1 कर लेखापरीक्षा के लिए सीमा बढ़ाना: लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए, अनिवार्य कर लेखापरीक्षा के लिए न्यूनतम कारोबार की सीमा मौजूदा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव उस मामले में किया जाता है जिनमें नकद प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं हैं और नकद भुगतान कुल भुगतानों के 5% से अधिक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अनुपालन लागत में कटौती करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट कर विवरणी दायर करने की देय तारीख से एक माह पहले दायर हो। तदनुसार, आयकर विवरणियों को दायर करने की उक्त देय तिथि संगत निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर से बदलकर 31 अक्तूबर किया जाना प्रस्तावित है ताकि कर लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने की तारीख में कोई परिवर्तन न हो।
- 5.2 अनिवासी को कतिपय शर्तों पर आयकर विवरण प्रस्तुत करने से छूट देना: अनिवासियों का अनुपालन का भार कम करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि धारा 115क में दिए गए दर पर कर की कटौती की गई हो, तो तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी अथवा शुल्क के रूप में प्राप्त उनकी आय पर आयकर विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी जाए।

**6. आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों का यौक्तिकीकरण**

- 6.1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को प्रदान की जाने वाली कतिपय परिलब्धियों और भत्तों पर दी जाने वाली छूट समाप्त की जाए।



- 6.2 पण्य लेनदेन कर को आरोपित करने के प्रयोजनार्थ 'करयोग्य पण्य लेनदेन' की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 6.3 फेसलेस दंड के लिए स्कीम अधिसूचित करने हेतु केन्द्र सरकार को समर्थ बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 6.4 सर्वेक्षण प्रचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि सर्वेक्षण निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित नहीं है, तो आयकर आयुक्त अथवा प्रधान आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
- 6.5 यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अपीलीय अधिकरण मांग पर तभी रोक लगाएगा जब करदाता ने मांग की राशि के 20 प्रतिशत का भुगतान किया हो अथवा समतुल्य राशि के लिए प्रतिभूति प्रदान की हो।
- 6.6 भारत में निवासी बनने के लिए भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की अवधि 182 दिन से घटाकर 120 दिन किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। तत्पश्चात "निवासी किन्तु साधारण निवासी नहीं" के उपबंध में ढील देने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि पिछले दस वर्षों में से सात वर्षों में अनिवासी रहने वाले निवासी साधारण निवासी हो सके। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि कोई भारतीय नागरिक जो कहीं भी कर अदायगी नहीं करता है, उसे भारतीय निवासी माना जाएगा।
- 6.7 यह उपबंध करने के लिए धारा 194ग के अंतर्गत टीडीएस के प्रयोजनार्थ "कार्य" की परिभाषा में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है कि संविदा विनिर्माण में, निर्धारिती अथवा उसके सहयोगी द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री धारा 194ग के अंतर्गत "कार्य" की सीमा में आएगी।
- 6.8 करदाताओं को जीएसटी में असत्य निविष्टि क्रेडिट का दावा करने के लिए जाली बीजकों सहित असत्य प्रविष्टियां दर्ज करके उनके बही-खातों में धोखाधड़ी करने में हतोत्साहित करने के लिए, इन अपव्यवहारों के लिए दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 6.9 उस उपबंध में संशोधन करने का प्रावधान किया जाता है जिसके तहत भारत को आधारभूत ह्रास और लाभ अंतरण (सामान्यतः एमआईएल के रूप में जाना जाता है) से बचने के लिए कर करार से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन द्वारा अधिदेशित नई प्रस्तावना का पालन करने के लिए अन्य देशों या संघ राज्यों या संघ के साथ दोहरे कराधान परिवर्जन करार (डीटीएए) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि भारत ने पहले ही एमआलआई का समर्थन किया है।
- 6.10 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उल्लेखनीय आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) के अधिनियमन को आस्थगित करने का प्रस्ताव किया जाता है क्योंकि उस समय तक डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित जी-20 ओईसीडी की रिपोर्ट आने की प्रत्याशा है। भारतीय ग्राहकों को लक्ष्य बनाकर विज्ञापन से राजस्व प्राप्त करने के लिए और भारतीय लोगों से लिए गए आकड़ों की बिक्री से राजस्व के लिए स्रोत नियम के लिए उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।
- 6.11 सेबी के नए एफपीआई विनियमनों के अनुरूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अप्रत्यक्ष अंतरण के उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। रायल्टी की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।
- 6.12 धारा 115खकक और धारा 115खकख के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि रियायती कर अवधि का चयन करने वाली किसी भी घरेलू कम्पनी (मौजूदा और नई दोनों) को उक्त धारा के अंतर्गत विशिष्ट रूप से कटौती की अनुमति दिए जाने को छोड़कर, इस अधिनियम के अध्याय VI-क के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने की अनुमति न दिया जा सके।
- 6.13 विदेशी निधि स्थापित करने के शर्तों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि भारत में निधि प्रबंधन क्रियाकलाप स्थापित करना सरल हो सके।
- 6.14 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी पूँजीगत आस्ति, चाहे वह भूमि हो अथवा भवन अथवा दोनों, के मामले में, 1 अप्रैल, 2001 को उस आस्ति का उचित बाजार मूल्य, जहां स्टाम्प शुल्क मूल्य उपलब्ध हो, 1 अप्रैल, 2001 को उस आस्ति के स्टैम्प शुल्क मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- 6.15 न्यासों, संस्थाओं, निधियों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आदि के पंजीकरण की प्रक्रिया और संगठन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान या कम्पनी आदि के मामले में अनुमोदन युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। दान प्राप्तकर्ता द्वारा दान का विवरण फाइल करने के लिए भी उपबंध का प्रस्ताव किया जाता है ताकि दानकर्ता दावा किए गए कटौती का अपना समयपूर्व कर विवरणी भर सके।

- 6.16 फॉर्म 26एएस को उपयुक्त धारा में लाकर उसे भरने से संबंधित उपबंध को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है क्योंकि अब उसमें अनेक प्रकार की सूचनाएं होती हैं।
- 6.17 पृथकृत पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो को धारण करने वाले करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करने के लिए अभिधारण की लागत और धारण की अवधि से संबंधित उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 6.18 उन व्यक्ति को विहित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का प्रस्ताव किया जाता है जो किसी कम्पनी और एक सीमित देयता सहभागी के मामले में आयकर विवरणी सत्यापित कर सके। ऐसे व्यक्ति को विहित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का भी प्रावधान किया जाता है जो एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पेश हो सके।
- 6.19 घरेलू कम्पनियों द्वारा नई रियायती कर शासन का चयन करना सरल बनाने के लिए, धारा 35कघ के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि धारा 35कघ के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए एक विकल्प मुहैया कराया जा सके।
- 6.20 धारा 94ख के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, धारा 94ख के अंतर्गत ब्याज कटौती नियम से भारत में अनिवासी बैंक की किसी शाखा के ब्याज भुगतान को हटाने का प्रस्ताव किया जाता है।

### बजट भाषण का अनुबंध

#### क. सीमा शुल्कों में विधायी परिवर्तन

##### 1. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में प्रमुख संशोधन:

क्रम सं.	संशोधन
क.	अनुपालन में सुधार लाने के लिए
1.	व्यापार करारों के तहत तरजीही प्रशुल्क उपचार को प्रशासित करने के लिए समर्थकारी उपबंध का प्रावधान करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय Vकक (एक नई धारा 28घक) समाविष्ट की जा रही है। प्रस्तावित नई धारा का उद्देश्य आयातक पर विशेष रूप से कतिपय बाध्यताओं का प्रावधान करना और शंका के मामले में निर्यातक देश से समयबद्ध सत्यापन निर्धारित करना है। लंबित सत्यापन तरजीही प्रशुल्क उपचार निलंबित कर दिया जाएगा और अंतर परक शुल्क के समतुल्य प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर ही माल क्लियर किया जाएगा। कतिपय मामलों में, आगे सत्यापन के बिना तरजीही प्रशुल्क उपचार से इनकार किया जा सकता है।
ख.	मुकदमेबाजी कम करने के लिए
1.	पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करने के लिए धारा 28 में स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जा रहा है कि वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन से पहले उक्त धारा के अधीन जारी किया गया कोई भी नोटिस धारा 28 द्वारा अभिशासित किया जाता रहेगा जैसाकि यह उक्त अधिनियम से पहले किया जाता रहा है भले ही इसके विपरीत किसी अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय अधिकरण, न्यायालय या किसी अन्य कानून द्वारा आदेश जारी किया गया है।
ग.	अन्य समर्थकारी उपबंध
1.	धारा 11(2) का खंड (च) केन्द्रीय सरकार को स्वर्ण या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को क्षति की रोकथाम के लिए उनके आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इस खंड के दायरे में "किसी अन्य माल" स्वर्ण और चांदी के अतिरिक्त को शामिल करने के लिए इसका संशोधन किया जा रहा है।
2.	सीमा शुल्क प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक शुल्क क्रेडिट बही के सृजन प्रावधान करने के लिए एक नई धारा (धारा 51ख) समाविष्ट की जा रही है। इससे निर्यातों या ऐसे लाभों के संबंध में इनके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग या अंतरण के लिए शुल्क विप्रेषण के स्थान पर शुल्क क्रेडिट किए जाने का प्रावधान होगा। इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157(2) में उपयुक्त विनियम के निर्गमन हेतु समर्थकारी उपबंध भी अंतःस्थापित किए जा रहे हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28कक के तहत उपबंधित शुल्कों की वसूली के लिए उपबंधों का भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शुल्कों के क्रेडिट को जोड़ने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

**2. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन:**

क्रम सं.	संशोधन
क	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन
1.	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख, जिसमें किसी पण्य के आयातों में अत्यधिक वृद्धि के विपरीत व्यापार संबंधी उपचार के रूप में सुरक्षा उपाय शुल्क के अधिरोपण का उपबंध था, उसे संशोधित किया जा रहा है ताकि प्रशुल्क दर कोटा और अन्य सुरक्षा उपाय संबंधी उपाय जैसे अन्य सुरक्षा उपायों की अनुप्रयोज्यता हेतु उपबंध किए जा सकें जिन्हें केन्द्रीय सरकार आयातों में अत्यधिक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को हानि से संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे।
ख.	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन
1.	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची को निम्न के लिए संशोधित किया जा रहा है: (i) "वालफैन" के लिए नई प्रशुल्क मद 8414 51 50 सृजित करना। इस मद के लिए प्रशुल्क दर 20 प्रतिशत है और वालफैनों पर बीसीडी को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। (ii) "ओपन सेल और टेलीविजन सेट" के लिए नई प्रशुल्क मद 8529 90 30 सृजित करना। इस मद के लिए प्रशुल्क दर 15 प्रतिशत है। तथापि, इन मदों पर 'शून्य' बीसीडी जारी रहेगी। (iii) "सोलर सेलों, जो असेम्बलड नहीं" के लिए प्रशुल्क मदें 85 41 40 11 और "मॉड्यूलों में असेम्बलड या पैनों में बनाए गए" सोलर सेलों के लिए प्रशुल्क मद 8541 40 12 सृजित करना। इन मदों के लिए प्रशुल्क दर 20 प्रतिशत है। तथापि, इन मदों पर 'शून्य' बीसीडी जारी रहेगी।

**3. समतुल्य शुल्क नियमावली और प्रतिपाटन शुल्क नियमावली में संशोधन:**

इन नियमावलियों में सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं के आयातों के मामले में और ऐसी वस्तुओं जिनसे घरेलू उद्योग को हानि होती हो, के पाटन के मामले में जांच-पड़ताल के तरीके और प्रक्रिया का प्रावधान है। इन नियमावलियों में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं:

क्र.सं.	नियमावली	संशोधन
1.	प्रतिपाटन नियमावली	इस नियमावली को सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप प्रतिपाटन शुल्क की सभी प्रकार की प्रवंचनाओं का ध्यान रखने के लिए इसे और अधिक व्यापक बनाकर तथा दायरे का विस्तार करके प्रवंचनारोधी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन नियमों के दायरे में स्पष्टता लाने के लिए इन नियमों में कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।
2.	समतुल्य शुल्क नियमावली	वर्तमान में, समतुल्य शुल्कों की प्रवंचना के मामले में जांच पड़ताल हेतु कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे शुल्क के समर्थकारी अधिरोपण के लिए समतुल्य शुल्क की प्रवंचना के मामले में जांच पड़ताल में समर्थ बनाने के लिए समतुल्य शुल्क नियमावली में एक उपबंध समाविष्ट किया जा रहा है। इन नियमों में स्पष्टता लाने के लिए कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।

**ख. कतिपय आयातित वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क छूट की समीक्षा**

- निरर्थक, पुरानी अप्रचलित अथवा अपनी उपयोगिता खो चुकी प्रविष्टियों को छांटने के लिए सीमा शुल्क छूट की समीक्षा की गई है। ऐसी समीक्षा पर, संगत अधिसूचनाओं के उपयुक्त संशोधन/निरसन द्वारा 80 छूटे वापस ली जा रही हैं। ये छूटें हैं- समीक्षा उन्मुख होने के चलते, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित वस्तुओं पर छूट/रियायती दरें वापस लिया जाना शामिल है, नामतः:

क्र.सं.	वस्तुओं की श्रेणी	विशिष्ट वस्तुएं
1.	कृषि और पशु आधारित उत्पाद	टूनावेट, दूध और कतिपय मिल्क उत्पाद, चीनी, चुकन्दर के बीज, खांड, कतिपय मादक पेय और एकाकी सोया प्रोटीन, सोया फाइबर आदि।

2.	धातु की वस्तुएं	क. लेड की छड़ें, राड और तार ख. जस्ते की ट्यूब, पाइप और ट्यूब ग. टिन की प्लेटें, चादरें और पत्तियां
3.	यंत्र	विनिर्दिष्ट विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, विनिर्दिष्ट मेट्रो परियोजनाओं जैसी कतिपय परियोजनाओं, अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में प्रयोग के लिए आयातित यंत्र; सड़क निर्माण के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट वस्तुएं।
4.	इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त तांबा और उससे निर्मित सामान; प्रिंटर, सीडी राइटर, एमपी 3 या एमपी4 या एमपीईजी4 प्लेयर, प्री-रिकार्डेड कैसेटों, आडियो कैसेटों, रंगीन टेलीविजन ट्यूबों आदि के विनिर्माण हेतु कल-पुर्जे।
5.	विविध	क. पीनट बटर, संरक्षित आलू ख. इंस्टेंट प्रिंट फिल्म, एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्में ग. कुछ निरर्थक और पुरानी सीमा शुल्क छूटें वापस ली जा रही हैं। इसके अलावा, कुछ छूटें प्रासंगिकता के लिए संरक्षित की जा रही हैं।

ग. एमएसएमई के लिए स्तरीय कार्यक्षेत्र के सृजन और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन:

#### 1. घरेलू उत्पादकों के लिए स्तरीय कार्यक्षेत्र

निम्नलिखित वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है:

क्र.सं.	वस्तुओं की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मर्दे	शुल्क दर	
			पहले	अब
1.	घरेलू सामान और उपकरण	पोर्सलेन या चीनी, सेरेमिक, मिट्टी, लौह, इस्पात, तांबे और एल्युमिनियम के टेबलवेयर और रसोई के बर्तन, कांच के बर्तन, पैड लौक्स, झाड़ू, हाथ की छलनी, कंघे, बेकम फ्लास्क, आदि	10%	20%
2.	विद्युत उपकरण	पंखे, फूडग्राइंडर/मिक्सर, सेवर और बाल हटाने वाले उपकरण, पानी के हीटर, बाल/हाथ सुखाने वाले उपकरण, ओवन, कुकर, टोस्टर, काफी/चायदानियां, इंसेक्ट रेपिलेंट, हीटर, आयरन, आदि।	10%	20%
3.	जूते	क. जूते ख. जूतों के पार्ट्स	25% 15%	35% 20%
4.	फर्नीचर का सामान	सीटें, वेडिंग, गद्दों सहित, की वस्तुएं, लैम्प, लाइटिंग, प्रकाशवान चिह्न, और अन्य फर्नीचर के सामान।	20%	25%
5.	लेखन सामग्री	फाइलिंग कैबिनेट, पेपर ट्रे, बाइंडर, क्लिप, स्टेपल्स, साइन-प्लेट्स, नाम पट्टिकाएं, बेस धातु से निर्मित संख्याएं और प्रतीक आदि।	10%	20%
6.	खिलौने	तिपहिया साइकिलें, स्कूटर, स्केल मॉडल, डॉल्स आदि।	20%	60%
7.	यंत्र	क. उच्च वोल्टेज विद्युत पारेषण परियोजनाओं में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट वस्तुएं ख. रेलवे कैरिज पंखे	5% 7.5%	7.5% 10%

		ग. रेफरीजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर	10%	12.5%
		घ. वाणिज्यिक फ्रीजर	7.5%	15%
		ड. बेल्डिंग और प्लाज्मा कटिंग मशीन	7.5%	10%
		च. रोटरी टिलर/वीडर	2.5%	7.5%
8.	अन्य विविध वस्तुएं	क. कांच की मालाएं ख. कृत्रिम फूल ग. घंटियां, गोंग, मूर्तियां, ट्राफियां और इसी प्रकार के सामान, बेस धातु की मूर्तियां, आभूषण, फोटोग्राफ, फ्रेम, शीशे आदि।	10%	20%

**2. विद्युतचालित वाहनों और सेल्युलर मोबाइल फोनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अंतर्गत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन**

क.	विद्युतचालित वाहनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क में परिवर्तन	शुल्क दर	
		पहले	अब
1.	बस और ट्रकों की पूरी तरह से निर्मित यूनिटें (01.04.2020 से)	25%	40%
2.	बस, ट्रक और दोपहिया वाहनों की सेमी नोकड डाउन (एसकेडी) यूनिटें (01.04.2020 से)	15%	25%
3.	यात्री वाहनों और तिपहिया वाहनों की सेमी नोकड डाउन (एसकेडी) यूनिटें (01.04.2020 से)	15%	30%
4.	यात्री वाहनों और तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों, बस और ट्रकों की पूरी तरह से नोकड डाउन (सीकेडी) यूनिटें (01.04.2020 से)	10%	15%
ख.	सेल्युलर मोबाइल फोनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क में परिवर्तन		
1.	मोबाइल फोनों के पीसीबीए (01.04.2020 से)	10%	20%
2.	सेल्युलर मोबाइल फोनों के वाइब्रेटर/रिगर (01.04.2020 से)	शून्य	10%
3.	डिस्प्ले पैनल और टच असेम्बली (01.10.2020 से)	शून्य	10%

**3. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन**

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
		पहले	अब
1.	सिंगल फेज एसी मोटरों, स्टेपर मोटरों, वाइपर मोटरों आदि जैसी मोटरें	7.5%	10%
2.	विशिष्ट चार्जर और पावर अडाप्टर	लागू दर	20%
3.	सेल्युलर मोबाइल फोनों में उपयोग के लिए फिंगरप्रिंट रीडर	शून्य	15%
4.	इयरफोन और हेडफोन	लागू दर	15%

**4. घरेलू विनिर्माताओं द्वारा आयातित कच्ची सामग्री और इनपुट पर सीमा शुल्क में कमी**

क्र.सं.	इनपुट/कच्ची सामग्री की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
			पहले	अब
1.	रसायन, प्लास्टिक और रबड़	220-400 सीएसटी स्टैंडर्ड/मैरीन फ्यूल 0.5 प्रतिशत (एफओ) में आईएसओ 8217:2017 आरएमजी 380 विस्कोसिटी पूरा करने वाला अति निम्न सल्फर फ्यूल ऑयल	10%	शून्य
		कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक	10%	7.5%

क्र.सं.	इनपुट/कच्ची सामग्री की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मर्दे	शुल्क दर	
			पहले	अब
		स्मार्ट कार्डों के विनिर्माण में प्रयुक्त कैलेण्डियर्ड प्लास्टिक सीटें।	10%	5%
		कनेक्टर्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए पोलिस्टर लिक्विड क्रिस्टल पोलिमर	7.5%	शून्य
2.	कीमती धातुएं	निम्न के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम या पैलेडियम: (क) सभी वस्तुएं, नोबल मेटल कंपाउंड और नोबल मेटल सोल्यूशन सहित (ख) सक्रिय पदार्थ के रूप में कीमती धातु या कीमती धातु यौगिकों के साथ कैटेलिस्ट	12.5%	7.5%
		स्पेंट कैटेलिस्ट या ऐस वाली कीमती धातु, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन	12.5%	11.85%
3.	यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान	माइक्रोफोन के विनिर्माण में प्रयोग हेतु माइक्रोफोन के निम्नलिखित कलपुर्जे अर्थात् क) माइक्रोफोन कार्टेज ख) माइक्रोफोन होल्डर ग) माइक्रोफोन ग्रिल घ) माइक्रोफोन बॉडी	10%	शून्य
		माइक्रो-फ्यूज बेस, सब-मिनियेचर फ्यूज बेस, माइक्रो-फ्यूज कवर और माइक्रो-फ्यूज तथा सब-मिनियेचर फ्यूज के विनिर्माण में सब-मिनियेचर फ्यूज कवर।	7.5%	शून्य
4.	खेल का सामान	पिछले वित्त वर्ष में आयातित खेल के सामान के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत तक अनुमत शुल्क मुक्त आयात वस्तुओं की सूची में विल्लो को जोड़ा जा रहा है।	लागू दर	शून्य
5.	न्यूजप्रिंट	क) न्यूजप्रिंट, जब रजिस्ट्रार और न्यूजपेपर, इंडिया के पास पंजीकृत आयातक द्वारा आयात किया जाए। ख) न्यूजपेपर के मुद्रण के लिए प्रयुक्त अनकोटेड पेपर, जब रजिस्ट्रार और न्यूजपेपर, इंडिया के पास पंजीकृत आयातक द्वारा आयात किया जाए। ग) पत्रिकाओं की छपाई के लिए प्रयुक्त हल्का कोटेड पेपर अंतिम उपयोग की शर्त के अध्वधीन	10%	5%

#### 5. सीमा शुल्क में अन्य परिवर्तन

क्र.सं.	सामान की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मर्दे	शुल्क दर	
			पहले	अब
1.	खाद्य प्रसंस्करण	अखरोट, बिना छिले	30%	100%
2.	रसायन, प्लास्टिक और कांच	कोलाइडल कीमती धातुएं, कीमती धातु के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक, कीमती धातुओं का मिश्रण	7.5%	10%
		बुटिल एक्रीलेट	5%	7.5%

क्र.सं.	सामान की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मर्दे	शुल्क दर	
			पहले	अब
		फाउंड्री मोल्ड या कोर के लिए अन्य तैयार बाइंडर; रसायनयुक्त उत्पाद और रसायन या संबद्ध उद्योगों की प्रिपरेशन	10%	15%
3.	आटो और आटो पार्ट्स	कैटेलेटिक कनवर्टर	10%	15%
		कैटेलेटिक कनवर्टर और इसके पुर्जों के निर्माण में प्रयुक्त नोबल मेटल सोल्यूशन और नोबल मेटल यौगिक	5%	लागू दर
		कैटेलेटिक कनवर्टर और इसके पुर्जे	5%	लागू दर
		कैटेलेटिक कनवर्टरों के विनिर्माण के लिए कल पुर्जे और अन्य विशिष्ट सामग्री	5%	7.5%
		वाणिज्यिक वाहनों (विद्युत वाहनों को छोड़कर) की पूरी तरह से निर्मित यूनिटें (सीबीयू) (01.04.2020 से)	30%	40%

**घ. विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपकरणों पर स्वास्थ्य उपकरण लगाया जाना**

चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य उपकरण लगाए जाने का प्रस्ताव है। यह स्वास्थ्य उपकरण एक सीमा शुल्क होगा। स्वास्थ्य उपकरण ऐसे चिकित्सा उपकरणों पर लागू नहीं होगा जिन्हें बीसीडी से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामान/पुर्जों को भी स्वास्थ्य उपकरण से छूट प्राप्त होगी। स्वास्थ्य उपकरण का उपयोग स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

**ड. प्युरीफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड पर प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिसंहरण:**

निम्नलिखित में उत्पन्न होने वाले या आयात किए जाने वाले प्युरीफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिसंहरण;

1. दक्षिण कोरिया और थाइलैण्ड पर अधिसूचना संख्या 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24.7.2019 के तहत अधिरोपित
2. चीन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान पर अधिसूचना संख्या 28/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5.7.2016 के तहत अधिरोपित

**च. सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) में वृद्धि**

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, वित्त अधिनियम, 2001 की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कतिपय विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। तम्बाकू निर्मित उत्पादों (बीड़ी को छोड़कर) एनसीसीडी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. सिगरेटों पर, सिगरेट की लंबाई के आधार पर और फिल्टर/फिल्टर-भिन्न आधार पर 200-735 रुपये प्रति हजार के हिसाब से एनसीसीडी बढ़ाया जा रहा है।
2. पाइप और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिक्सचरों पर, एनसीसीडी 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।
3. पीने वाली तम्बाकू के अन्य रूपों (पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान के लिए मिक्सचरों को छोड़कर) तथा खाने वाली तम्बाकू के रूपों पर, एनसीसीडी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है।
4. बीडियों पर एनसीसीडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

## छ. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों में शामिल परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव:

क्र.सं.	केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में संशोधन
क	व्यापार या उपभोक्ता की सुविधा के लिए
1.	निविष्ट कर क्रेडिट का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ डेबिट नोट निर्गमन की तारीख को अंतर्निहित बीजक निर्गमन की तारीख से अलग करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) संशोधित की जा रही है।
2.	धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किए गए पंजीकरण को निरस्त करने का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) को संशोधित किया जा रहा है।
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 1 का परंतुक उपयुक्त मामलों में पंजीकरण के निरसन को वापस लेने के आवेदन की तारीख बढ़ाने हेतु न्यायाधिकारिक कर प्राधिकरणों को अधिकार प्रदान करने के लिए अंतःस्थापित किया जा रहा है।
4.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 में कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र की निर्गमन की आवश्यकता समाप्त करने; तथा टीडीएस प्रमाणपत्र के निर्गमन में विलंब होने पर विलंब शुल्क के तदनुसूची उपबंध का लोप करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 का संशोधन किया जा रहा है ताकि न्यायाधिकारिक आयुक्त को धारा 66 की उप-धारा (5) और धारा 243 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।
ख.	अनुपालन में सुधार लाने के लिए
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 को संशोधित किया जा रहा है ताकि निम्नलिखित कार्य में लगे कतिपय श्रेणियों में कर योग्य व्यक्तियों को कंपोजीशन स्कीम के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जा सके:- (i) सीजीएसटी अधिनियम के तहत कर अनुद्विग्राहीय सेवाओं की आपूर्ति, अथवा (ii) सेवाओं की अंतर-राज्य बाहरी आपूर्ति, अथवा (iii) किसी ई-कामर्स आपरेटर्स के माध्यम से सेवाओं की बाहरी पूर्ति
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 को कपटपूर्ण आदान कर क्रेडिट पारित करने अथवा प्राप्त करने संबंधी संव्यवहारों के लाभार्थी को वैसी ही शास्ति का उत्तरदायी बनाने के लिए एक नई उपधारा अंतःस्थापित करके संशोधित किया जा रहा है जैसी शास्ति उस व्यक्ति पर उद्विग्राहीय होती है जो ऐसे विनिर्दिष्ट अपराध करता हो।
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 को संशोधित किया जा रहा है ताकि निविष्ट कर क्रेडिट को बिना किसी बीजक या बिल के धोखाधड़ी से प्राप्त करने के अपराध को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जा सके या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराध करता है या अपराध होने का कारण बनता है, या इन अपराधों से होने वाले लेनदेनों के लाभ को अपने पास रखता है, सजा का हकदार बनाया जा सके।
ग.	अन्य परिवर्तन
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (114) में “संघ राज्य क्षेत्र” की परिभाषा संशोधित की जा रही है ताकि जम्मू और मश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 तथा दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 को लागू करने के विचार से संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा का अद्यतन किया जा सके। यूटीजीएसटी अधिनियम में भी परिणामी परिवर्तन किए जा रहे हैं।



क्र.सं.	केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में संशोधन
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 को कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामले में बीजकों के निर्गमन का तरीका निर्धारित करने हेतु समर्थकारी उपबंध का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण हेतु उपबंध लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
4.	संक्रमणात्मक क्रेडिट लेने के लिए तरीका और समय-सीमा निर्धारित करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 को 01.07.2017 से संशोधित किया जा रहा है।
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 172 को संशोधित किया जा रहा है ताकि अन्य दो वर्षों अर्थात् उक्त अधिनियम की शुरुआत से लेकर पांच वर्षों तक के लिए कठिनाइयों को दूर करने संबंधी आदेश के निर्गमन के लिए उपबंध किया जा सके। इसी तरह के परिवर्तन आईजीएसटी अधिनियम, 2017 (धारा 25) यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 धारा (26) और जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (धारा 14) में भी किए जा रहे हैं।
6.	सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची -II में 4(क) और 4(ख) की प्रविष्टियों में भी 01.07.2017 से संशोधन किया जा रहा है ताकि उक्त अधिनियम की अनुसूची-II से बिना किसी प्रतिफल के बनाई गई व्यापारिक आस्तियों के अंतरण से संबंधित आपूर्तियों के लोप का प्रावधान किया जा सके।

जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन राज्यों और विधानमण्डल वाले केन्द्रीय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पारित इसी प्रकार के अधिनियमों में साथ-साथ तदनु रूप संशोधनों के साथ, यथासंभव उस तारीख से प्रभावी होंगे जब उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

**ज. जीएसटी परिषद की संस्तुतियों को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन**

क्र.सं.	माल और सेवा कर दर तथा रिफंड संबंधी उपबंधों में पूर्वव्यापी संशोधन
1.	मत्स्याहार (एचएस2301) पर केन्द्रीय कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से 01.07.2017 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की जा रही है। तथापि, इस अवधि के दौरान मत्स्याहार की आपूर्ति पर प्रदत्त जीएसटी लौटाया नहीं जाएगा।
2.	पुली, व्हील्स और अन्य पार्ट्स (शीर्षक 8483 के अंतर्गत आने वाले और शीर्षकों 8432, 8433 और 8436 के कृषि मशीनरी के भाग के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं पर 01.07.2017 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत की रियायती दर पर एकीकृत कर और 6 प्रतिशत केन्द्रीय कर तथा 6 प्रतिशत संघ राज्य क्षेत्र कर लगाया जाना। तथापि, किसी अन्य दर पर (12 प्रतिशत से अधिक) चुकाया गया जीएसटी लौटाया नहीं जाएगा।
3.	क्षतिपूर्ति उपकर में इनवर्टेड शुल्क संरचना के कारण उत्पन्न तम्बाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर के संचित क्रेडिट की वापसी अधिसूचना संख्या 3/2019-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) तारीख 30.09.2019 द्वारा अनुमत नहीं है। इस अधिसूचना को 01.07.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। तदनुसार, तम्बाकू से संबंधित उत्पादों पर किसी भी अवधि के लिए इनवर्टेड शुल्क संरचना के कारण कोई भी राशि लौटाई नहीं जाएगी।

बजट प्रस्तावों की अधिक जानकारी के लिए, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा अन्य बजट संबंधी दस्तावेज देखें।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(BUDGET DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st February, 2020

**F. No. 2(2)-B(D)/2020.**—The following is published for generated information.—

**Budget 2020-2021**

**Speech of Nirmala Sitharaman Minister of Finance**

**February 1, 2020**

Hon'ble Speaker,

I rise to present the Budget for the year 2020-2021.

**Introduction**

In May 2019, Prime Minister Modi received a massive mandate to form the government again. With renewed vigour, under his leadership, we commit ourselves to serve the people of India, with all humility and dedication.

2. People of India have unequivocally given their *jan-aadesh* for not just political stability and also reposed faith in our economic policies. This is the Budget to boost their incomes and enhance their purchasing power. Only through higher growth we can achieve that and have our youth gainfully and meaningfully employed. Let our businesses be innovative, healthy and solvent with use of technology.

3. For today's youth born at the turn of the century, for every member of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who seeks a better life, for every woman wishing to stand up and get counted, for every individual from the minority sections of our society – this Budget aims to have your aspirations and hopes addressed.

4. We wish to open up vistas for a vibrant and dynamic economy with a gentle breeze of new technology. This vibrant India shall be a caring society which shall attend to its weak, the old and the vulnerable among its citizens.

5. During 2014-19, our government brought in a paradigm shift in governance. This shift was characterised by a twin focus: fundamental structural reform and inclusive growth.

6. Fundamentals of the economy are strong and that has ensured macroeconomic stability. Inflation has been well contained. Banks saw a thorough cleaning up of accumulated loans of the past decade and then they were recapitalized. Companies were provided an exit through the IBC. Several steps on the formalisation of the economy were taken up.

7. Of the structural reforms, the Goods and Services Tax (GST) has been the most historic in our country. Its chief architect is not with us today. I pay homage to the visionary leader late Shri Arun Jaitley ji. At the time of roll out of GST, he had said and I quote:

*"It will be an India where the Centre and States will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. The unanimity of the Constitutional amendment and the consensus of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics for the*

*nation's interest. With the GST, neither the state nor the Centre loses its sovereignty. In contrast, they will pool their sovereignty on decisions on indirect taxes."*

**8.** True to this vision for the historic structural reform, the Goods and Services Tax has been gradually maturing into a tax that has integrated the country economically. It has consolidated numerous taxes and cesses to one tax and facilitated formalization of economy. It has resulted in the efficiency gains in logistic and transport sectors. The turnaround time for trucks has witnessed a substantial reduction to the tune of 20% due to abolition of check posts in GST. The dreaded Inspector-Raj has also vanished.

**9.** It has also led to significant benefits to MSME by way of enhanced threshold and composition limits. The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially. Through several rate reductions, an annual benefit of ₹ one lakh crore has been extended to consumers. It amounts to 10% reduction in overall tax incidence. An average household now saves about 4% on its monthly spends on account of reduced GST rates.

**10.** During this phase of maturing, GST did face certain challenges. This was natural as transition was daunting. GST Council has been proactive in resolving issues during transition. In the last two years we have added more than 60 lakh new taxpayers, a total of about 40 crore returns were filed, 800 crore invoices were uploaded, and 105 crore e-way bills were generated. There has been extensive engagement with stakeholders. A simplified new return system is being introduced from April 1, 2020.

**11.** A former Prime Minister had once voiced a concern that the fruits of the welfare schemes were not reaching the intended citizens – the common and deserving citizen was only receiving 15 paise of every rupee sent for him. Guided by "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas", our government and our Prime Minister added manifold speed and scaled up the implementation of schemes and programmes that directly benefitted the poor and the disadvantaged. I wish to list out only a few as examples: (a) welfare schemes with Direct Benefit Transfer (DBT) embedded in them; (b) sanitation and water as provision of basic needs and as a measure of preventive healthcare; (c) healthcare, through Ayushman Bharat; (d) clean energy through Ujjwala and solar power; (e) financial inclusion, credit support, insurance protection to vulnerable sections and pension scheme; (f) digital penetration with broadband and UPI; (g) Affordable Housing for all through PMAY.

The milestones achieved are unprecedented, globally recognised and benchmarked against international indices.

**12.** This strategy, changed the established order of a few individuals cornering most of the benefits and was appreciated by the people. This had immensely positive outcomes. We have moved on from a growth rate of just over 4% in 1950s to 6% in 1980s and 1990s. However, during 2014-19 we clocked growth of 7.4% on average with inflation, averaging around 4.5%. It is worthwhile to note that inflation was close to 9% in the last two decades of the last millennium and ranged 10.5% during 2009-14. Between 2006-16, India was able to raise 271 million people out of poverty, which we all should be proud of.

**13.** We are now the fifth largest economy of the world. India's foreign direct investment got elevated to the level of US\$ 284 billion during 2014-19 from US\$ 190 billion that came in during the years 2009-14. The Central Government debt that has been the bane of our economy got reduced, in March 2019, to 48.7% of GDP from a level of 52.2% in March 2014.

14. With this backdrop, our government shall work towards taking the country forward so that we can leapfrog to the next level of health, prosperity and well-being. We shall strive to bring Ease of living for every citizen.

15. I am mindful of presenting this budget in the backdrop of two cross-cutting developments:

- a) Proliferation of technologies, specially analytics, machine learning, robotics, bio-informatics and Artificial Intelligence; and
- b) The number of people in the productive age group i.e. 15-65 years in India, being at its highest.

16. This combination is special to contemporary India. Across the world, if there is a shrinking of globalisation, equally, there is a debate on the efficacy of monetary policy too. The efforts we have made in the last five years and the energy, enthusiasm and the innovation of our youth are the ignition required to push forward. The Indian spirit of entrepreneurship which weathered several storms over the centuries inspire and motivate us. We recognise the need to support and further energise this spirit.

17. This budget is woven around three prominent themes:

One: **Aspirational India** in which all sections of the society seek better standards of living, with access to health, education and better jobs.

Two: **Economic development** for all, indicated in the Prime Minister's exhortation of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas". This would entail reforms across swathes of the economy. Simultaneously, it would mean yielding more space for the private sector. Together, they would ensure higher productivity and greater efficiency.

AND

Three: Ours shall be a **Caring Society** that is both humane and compassionate. Antyodaya is an article of faith.

18. The digital revolution which has placed India in a unique leadership position globally will see the next wave. We shall aim:

- To achieve seamless delivery of services through **Digital governance**
- To improve physical quality of life through **National Infrastructure Pipeline**
- Risk mitigation through **Disaster Resilience**
- Social security through **Pension and Insurance penetration**.

Each one of these initiatives and their components would be benchmarked to international standards and the indices would be announced soon.

19. To Summarize my introductory remarks, this Budget Speaker Sir, is dedicated to provide "Ease of Living" to all citizens. As mentioned, a little earlier, the details under the three broad themes – Aspirational India, Economic Development and Caring India are the flowers in the bouquet that is Ease of Living. Holding this bouquet together are two hands – *one*, Corruption free, policy-driven good governance and *two*, clean and sound financial sector.

20. The three themes described earlier form the basis of my subsequent presentation. They are the flowers of the bouquet that underline the overall concept of "**Ease of Living**" and need to uplift Governance, as pronounced by our Prime Minister Shri Narendra Modi.

The chapter on Finances and subsequent Part B on Taxes provide the necessary underpinning to the Budget that lays the guide map for next year and beyond.

Before, I move to elaborate on each of the three themes, I wish to recite a small verse in Kashmiri:

भैन वउन, गुलज़र मलीभाग ऊयव  
 डल मंज़, डेलवन पम्पेश ऊयव।  
 नवणवन-मन हून वसुन पम्भाग ऊयव  
 भैन वउन, भैन वउन  
 भैन वउन, ननू भैन वउन।  
 - पंडित मीननष केल

Saun Watan Gulzar Shalamaar Hyur  
 Dal Manz Pholvun Pamposh Hyuv  
 Navjavan-an-hund, Vushun Khumaar Hyuv  
 Myon Watan, Chyon Watan  
 Saun Watan, Nundbony Watan

(Everything that we do, all of us do, is for this beautiful country)

Poem by Pandit Dinanath Koul

### **Aspirational India**

21. I shall cover programmes and plans related to: (1) Agriculture, Irrigation and Rural development (2) Wellness, Water and Sanitation and (3) Education and Skills

### **Agriculture, Irrigation and Rural Development**

22. Our government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022. We have provided energy sovereignty through KUSUM and input sovereignty through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. We have provided resilience for 6.11 crores farmers insured under PM Fasal Bima Yojana. Focus on cultivation of pulses, expansion of micro-irrigation through Krishi Sinchai Yojana, have raised the self-reliance of the country. Provision of any annual supplement of the income to the farmer, directly is done through PM-KISAN. Connectivity through PMGSY, financial inclusion have helped raise farm incomes.

22 (1). Prosperity to farmers can be ensured by making farming competitive. For this, farm markets need to be liberalised. Distortions in farm and livestock markets need to be removed. Purchase of farm produce, logistics and agri-services need copious investments. Substantial support and hand-holding of farm-based activities such as livestock, apiary, and fisheries need to be provided for. Farmers desire integrated solutions covering storage, financing, processing and marketing.

23. Adopting sustainable cropping patterns and bringing in more technology are integral to our plan. All this and more can be achieved through working with and in cooperation with the States.

The following 16 action points indicate our focus:

**23 (1).** We propose to encourage those State governments who undertake implementation of following model laws already issued by the Central Government:

- a) Model Agricultural Land Leasing Act, 2016,
- b) Model Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2017, and
- c) Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion and Facilitation) Act, 2018.

**23(2).** Water stress related issues are now a serious concern across the country. Our government is proposing comprehensive measures for one hundred water stressed districts.

**23(3).** In the Budget speech of July 2019, I had stated that “annadata” can be “urjadata” too. The PM-KUSUM scheme removed farmers’ dependence on diesel and kerosene and linked pump sets to solar energy. Now, I propose to expand the scheme to provide 20 lakh farmers for setting up stand-alone solar pumps; further we shall also help another 15 lakh farmers solarise their grid-connected pump sets. In addition, a scheme to enable farmers to set up solar power generation capacity on their fallow/barren lands and to sell it to the grid would be operationalized.

**23 (4).** Our government shall encourage balanced use of all kinds of fertilizers including the traditional organic and other innovative fertilizers. This is a necessary step to change the prevailing incentive regime, which encourages excessive use of chemical fertilisers.

புமி திருத்தி உண்

ஆத்திச்சூடி

Bhumi tiruthi Unn

- Wise, Old Tamil Woman Saint poet Aauvaiyar – Sangam Era

"Aaathichoodi" verse 81

The meaning of this saying is that one must “first tend to till one's land and then eat”. One must eat only after work.

**23 (5).** India has an estimated capacity of 162 million MT of agri-warehousing, cold storage, reefer van facilities etc. NABARD will undertake an exercise to map and geo-tag them. In addition, we propose creating warehousing, in line with Warehouse Development and Regulatory Authority (WDRA) norms. Our government will provide Viability Gap Funding for setting up such efficient warehouses at the block/taluk level. This can be achieved, where States can facilitate with land and are on a PPP mode. Food Corporation of India (FCI) and Central Warehousing Corporation (CWC) shall undertake such warehouse building on their land too.

**23 (6).** As a backward linkage, a Village Storage scheme is proposed to be run by the SHGs. This will provide farmers a good holding capacity and reduce their logistics cost. Women, SHGs shall regain their position as “Dhaanya Lakshmi”.

**23 (7).** To build a seamless national cold supply chain for perishables, inclusive of milk, meat and fish, the Indian Railways will set up a “Kisan Rail” – through PPP arrangements. There shall be refrigerated coaches in Express and Freight trains as well.

**23 (8).** Krishi Udaan will be launched by the Ministry of Civil Aviation on international and national routes. This will immensely help improve value realisation especially in North-East and tribal districts.

**23 (9).** Horticulture sector with its current produce of 311 million MT exceeds production of food grains. For better marketing and export, we propose supporting States which, adopting a cluster basis, will focus on “one product one district”.

**23 (10).** Integrated farming systems in rainfed areas shall be expanded. Multi-tier cropping, bee-keeping, solar pumps, solar energy production in non-cropping season will be added. Zero-Budget Natural Farming (mentioned in July 2019 budget) shall also be included. The portal on “jaivik kheti” – online national organic products market will also be strengthened.

**23 (11).** Financing on Negotiable Warehousing Receipts (e-NWR) has crossed more than ₹ 6000 crore. This will be integrated with e-NAM.

**23 (12).** Non-Banking Finance Companies (NBFCs) and cooperatives are active in the agriculture credit space. The NABARD re-finance scheme will be further expanded. Agriculture credit target for the year 2020-21 has been set at ₹ 15 lakh crore. All eligible beneficiaries of PM-KISAN will be covered under the KCC scheme.

**23 (13).** Our government intends to eliminate Foot and Mouth disease, brucellosis in cattle and also *peste des petits ruminants* (PPR) in sheep and goat by 2025. Coverage of artificial insemination shall be increased from the present 30% to 70%. MNREGS would be dovetailed to develop fodder farms. Further, we shall facilitate doubling of milk processing capacity from 53.5 million MT to 108 million MT by 2025.

**23 (14).** Blue Economy: Our government proposes to put in place a framework for development, management and conservation of marine fishery resources.

**23 (15).** Youth in coastal areas benefit through fish processing and marketing. By 2022-23, I propose raising fish production to 200 lakh tonnes. Growing of algae, sea-weed and cage Culture will also be promoted.

Our government will involve youth in fishery extension through 3477 Sagar Mitras and 500 Fish Farmer Producer Organisations. We hope to raise fishery exports to ₹ 1 lakh crore by 2024-25.

**23 (16).** Under Deen Dayal Antyodaya Yojana for alleviation of poverty, 58 lakh SHGs have been mobilised. We shall further expand on SHGs.

**24.** Now, for the fund allocation for the 16 different steps mentioned above, they are being stated under two different categories:

For the sector comprising of Agriculture and allied activities, Irrigation and Rural Development an allocation of about ₹ 2.83 lakh crore has been made for the year 2020-21 . It's divided, inter-alia:

a) **For Agriculture, Irrigation & allied activities** - ₹ 1.60 lakh crore

b) **For Rural development & Panchayati Raj** - ₹ 1.23 lakh crore

### **Wellness, Water and Sanitation**

Under Aspirational India, I shall now speak about Wellness, Water and Sanitation.

**25.** We have a **holistic vision of healthcare** that translates into wellness of the citizen. Mission Indradhanush has been expanded to cover 12 such diseases, including five new vaccines. **FIT India movement** is a vital part of fight against Non-communicable diseases coming out of life style issues. A very focused safe water (Jal Jeevan Mission) and comprehensive sanitation program (Swachh Bharat Mission) have been launched to support the health vision. That would reduce the disease burden on the poor.

26. Presently, under PM Jan Arogya Yojana (PMJAY), there are more than 20,000 empanelled hospitals. We need more in Tier-2 and Tier-3 cities for poorer people under this scheme.

26 (1). It is proposed to set up Viability Gap funding window for setting up hospitals in the PPP mode. In the first phase, those Aspirational Districts will be covered, where presently there are no Ayushman empanelled hospitals. This would also provide large scale employment opportunities to youth. Proceeds from taxes on medical devices would be used to support this vital health infrastructure

26 (2). Using machine learning and AI, in the Ayushman Bharat scheme, health authorities and the medical fraternity can target disease with an appropriately designed Preventive regime.

27. “TB Harega Desh Jeetega” campaign has been launched. I propose to strengthen these efforts realise our commitment to end Tuberculosis by 2025.

28. I propose to expand Jan Aushadhi Kendra Scheme to all districts offering 2000 medicines and 300 surgicals by 2024.

I have provided for the health sector about ₹69,000 crores that is inclusive of ₹ 6400 crores for Prime Minister Jan Arogya Yojana (PMJAY).

29. Our government is committed to ODF Plus in order to sustain ODF behaviour and to ensure that no one is left behind. Now, more needs to be done towards liquid and grey water management. Focus would also be on Solid waste collection, source segregation and processing.

Total allocation for Swachh Bharat Mission is about ₹12,300 crore in 2020-21.

30. Aiming to provide piped water supply to all households, Prime Minister announced from the Red Fort the **Jal Jeevan Mission**. Our government has approved ₹3.60 lakh crore for this Mission. This scheme also places emphasis on augmenting local water sources, recharging existing sources and will promote water harvesting and de-salination. Cities with over a million population will be encouraged to meeting this objective during the current year itself.

During the year 2020-21, the scheme would be provided budget of ₹11,500 crore.

### **Education and Skills**

The third and the final item under **Aspirational India is Education and Skills**.

31. By 2030, India is set to have the largest working-age population in the world. Not only do they need literacy but they need both job and life skills. Dialogues have been held with State Education Ministries, Members of Parliament and other stake-holders about Education policy. Over 2 lakh suggestions were also received. **The New Education Policy will be announced soon.**

32. It is felt that our education system needs greater inflow of finance to attract talented teachers, innovate and build better labs. Therefore steps would be taken to enable sourcing External Commercial Borrowings and FDI so as to able to deliver higher quality education.

33. Students in the general stream (vis-à-vis services or technology stream) need their employability improved. About 150 higher educational institutions will start apprenticeship embedded degree/diploma courses by March 2021.



**34.** The government proposes to start a programme whereby urban local bodies across the country would provide internship opportunities to fresh engineers for a period up to one year.

**35.** In order to provide quality education to students of deprived section of the society as well as those who do not have access to higher education, it is proposed to start degree level full-fledged online education programme. This shall be offered only by institutions who are ranked within top 100 in the National Institutional Ranking framework. Initially, only a few such institutions would be asked to offer such programmes.

**36.** India should be a preferred destination for higher education. Hence, under its “Study in India” programme, Ind-SAT is proposed to be held in Asian and African countries. It shall be used for benchmarking foreign candidates who receive scholarships for studying in Indian higher education centres.

**37.** A National Police University and a National Forensic Science University are being proposed in the domain of policing science, forensic science, cyber-forensics etc.

**38.** There is a shortage of qualified medical doctors, both general practitioners as well as specialists. In order to meet this requirement:

**38 (1).** It is proposed to attach a medical college to an existing district hospital in PPP mode. Those states that fully allow the facilities of the hospital to the medical college and wish to provide land at a concession, would be able to receive Viability Gap Funding. Details of the scheme would be worked out.

**38 (2).** National Board of Examination imparts PG medical qualifications; Diploma and fellow of National Board (DNB/FNB). The Government will, therefore encourage large hospitals with sufficient capacity to offer resident doctors DNB/FNB courses under the National Board of Examinations.

**39.** There exists a huge demand for teachers, nurses, para-medical staff and care-givers abroad. However, their skill sets, many a time, do not match the employer’s standards and therefore need to be improved. I propose that special bridge courses be designed by the Ministries of Health, Skill Development together with professional bodies to bring in equivalence. Language requirements of various countries need also to be included. All these should be achieved through special training packages.

Our Government proposes to provide about ₹ 99,300 crore for education sector in 2020-21 and about ₹ 3,000 crores for skill development.

### **Economic Development**

#### **Industry, Commerce and Investment**

The guilds of Saraswati-Sindhu civilization & the Harappan seals are remarkable. They belong to 3300 BCE. Words from the Indus Script-hieroglyphs have been deciphered. Commerce and trade related words show how India for a millennia is continuing as rich in skills, metallurgy, trade etc. “Takara Kolimi= Tin smithery”, “Sreni” = Guild, “Sethi”= wholesale merchant, “Poddar”= Assayer of metal into treasury.

**40.** Entrepreneurship has always been the strength of India. Even today, young men and women have given up greener pastures elsewhere to contribute to India’s growth. They are risk-taking and come up with disruptive solutions to festering challenges. Equally, established old industries are resetting themselves in a changing global and domestic situation. We recognise the knowledge, skills and risk-taking capabilities of our youth. He is no longer the job seeker. He is creator of jobs. Now we wish to create more opportunities and remove road-blocks from his path.

I propose to set up an Investment Clearance Cell that will provide “end to end” facilitation and support, including pre-investment advisory, information related to land banks and facilitate clearances at Centre and State level. It will work through a portal.

**41.** There is a case for maximising the benefits of three separately developing economic activities: (1) the upcoming economic corridors; (2) revitalisation of manufacturing activities; and (3) Technology and the demands of aspirational classes. We have to benefit from their convergence. Hence, it is proposed to develop **five new smart cities** in collaboration with States in PPP mode. Such sites would be chosen that offer the best choices in terms of aforementioned principles.

**42.** India needs to manufacture Networked products. That will make it a part of global value chains. This in turn gets more investment and generates more employment for our youth.

**42 (1).** Electronics manufacturing industry is very competitive and India has shown its cost advantages. The potential of this industry in job creation is immense. India needs to boost domestic manufacturing and attract large investments in the electronics value chain. Here, I propose a scheme focussed on encouraging manufacture of mobile phones, electronic equipment and semi-conductor packaging. Details would be announced later.

**42(2).** With suitable modifications, this scheme can be adapted for manufacture of medical devices too.

**43.** India imports significant quantity of technical textiles worth US\$ 16 billion every year. To reverse this trend and to position India as a global leader in Technical Textiles, a National Technical Textiles Mission is proposed with a four-year implementation period from 2020-21 to 2023-24 at an estimated outlay of ₹ 1480 crore.

**44.** From the Red Fort, our Prime Minister spoke about quality and standards when he spoke of “Zero Defect-Zero Effect” manufacturing. In September last year, I had called for a time-bound adoption by industry of all necessary, mandatory technical standards and their effective enforcement. All Ministries, during the course of this year, would be issuing quality standard orders.

**45.** To achieve higher export credit disbursement, a new scheme, NIRVIK is being launched, which provides for higher insurance coverage, reduction in premium for small exporters and simplified procedure for claim settlements.

**46.** It is proposed to digitally refund to exporters, duties and taxes levied at the Central, State and local levels, such as electricity duties and VAT on fuel used for transportation, which are not getting exempted or refunded under any other existing mechanism. *This Scheme for Reversion of duties and taxes on exported products will be launched this year.*

**47.** It is the vision of the Prime Minister that each District should develop as an export hub. Efforts of the Centre and State governments are being synergised and institutional mechanisms are being created.

**48.** Government e-Marketplace (GeM) is moving ahead for creating a Unified Procurement System in the country for providing a single platform for procurement of goods, services and works. It offers a great opportunity for Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs). 3.24 lakh vendors are already on this platform. It's proposed to take its turnover to ₹ 3 lakh crores.

I propose to provide about ₹27,300 crore for development and promotion of Industry and Commerce for the year 2020-21.

Under the theme “Economic Development”, the second focus is on Infrastructure.

## **Infrastructure**

**49.** Hon'ble Speaker, Sir, in his Independence Day speech 2019, Prime Minister had highlighted that ₹ **100 lakh crore** would be invested on infrastructure over the next 5 years. As a follow up measure, I had launched the National Infrastructure Pipeline on 31<sup>st</sup> December 2019 of ₹ 103 lakh crore. It consists of more than 6500 projects across sectors and are classified as per their size and stage of development.

These new projects will include housing, safe drinking water, access to clean and affordable energy, healthcare for all, world-class educational institutes, modern railway stations, airports, bus terminals, metro and railway transportation, logistics and warehousing, irrigation projects, etc. The National Infrastructure Pipeline envisions improving the ease of living for each individual citizen in the country. It's also will bring in generic and sectoral reforms in development, operation and maintenance of these infrastructure projects.

A huge employment opportunity exists for India's youth in construction, operation and maintenance of infrastructure. National Skill Development Agency will give special thrust to infrastructure-focused skill development opportunities.

**50 (1).** I propose to set up a project preparation facility for infrastructure projects. This programme would actively involve young engineers, management graduates and economists from our Universities.

**50 (2).** It is also proposed to direct all infrastructure agencies of the government to involve youth-power in start-ups. They will help in rolling out value added services in quality public infrastructure for citizens.

**51.** A National Logistics Policy will be released soon. *Inter alia*; it will clarify the roles of the Union Government, State Governments and key regulators. It will create a single window e-logistics market and focus on generation of employment, skills and making MSMEs competitive.

**52.** Accelerated development of highways will be undertaken. This will include development of 2500 Km access control highways, 9000 Km of economic corridors, 2000 Km of coastal and land port roads and 2000 Km of strategic highways.

Delhi-Mumbai Expressway and two other packages would be completed by 2023 . Chennai-Bengaluru Expressway would also be started.

**53.** FASTag mechanism encourages us towards greater commercialisation of our highways so that NHAI can raise more resources. I propose to monetise at least **twelve lots of highway bundles** of over 6000 Km before 2024.

**54.** In carrying out its duty, the Indian Railways performs a service to the nation.

- a) Within 100 days of assumption of this government, it has commissioned 550 wi-fi facilities in as many stations.
- b) Eliminated unmanned crossings.
- c) Aims to achieve electrification of 27000 Km of tracks.

This will call for optimisation of costs. Railways has small operating surplus. About Indian Railways, there are five measures, among others, that I wish to highlight:

- Setting up a large solar power capacity alongside the rail tracks, on the land owned by the railways. A proposal is under consideration.

- Four station re-development projects and operation of 150 passenger trains would be done through PPP mode. The process of inviting private participation is underway.
- More Tejas type trains will connect iconic tourist destinations.
- High speed train between Mumbai to Ahmedabad would be actively pursued.
- 148 km long Bengaluru Suburban transport project at a cost of ₹ 18600 crore, would have fares on metro model. Central Government would provide 20% of equity and facilitate external assistance up to 60% of the project cost.

**55.** Our sea-ports need to be more efficient. Technology has to be used to improve performance. A governance framework keeping with global benchmarks needs to be put in place.

This government would consider corporatizing at least one major port and subsequently its listing on the stock exchanges.

**56.** Inland Waterways received a boost in the last five years. The Jal Vikas Marg on National Waterway-1 will be completed. Further, the 890 Km Dhubri-Sadiya connectivity will be done by 2022.

Developing waterways has its impact on the eco-system on both the banks of the river. Our Prime Minister has conceptualised “**Arth Ganga**”. Plans are afoot to energise economic activity along river banks.

**57.** Air traffic has been growing rapidly in the country as compared to global average. One hundred more airports would be developed by 2024 to support Udaan scheme. It is expected that the air fleet number shall go up from the present 600 to 1200 during this time.

I propose to provide about ₹ 1.70 lakh crore for transport Infrastructure in 2020-21.

**58.** Taking electricity to every household has been a major achievement. However, the distribution sector, particularly the DISCOMs are under financial stress. The Ministry intends to promote “smart” metering. I urge all the States and Union Territories to replace conventional energy meters by prepaid smart meters in the next 3 years. Also, this would give consumers the freedom to choose the supplier and rate as per their requirements.

Further measure to reform DISCOMs would be taken.

I propose to provide about ₹ 22,000 crore to power and renewable energy sector in 2020-21

**59.** In the upstream sector of oil and gas, the Open Acreage Licensing Policy (OALP) is a success having awarded 1,37,000 sq km for exploration to private sector and to the CPSEs. City gas distribution rights are also awarded.

**60 (1).** Further, it is proposed to expand the national gas grid from the present 16200 km to 27000 km, and

**60 (2).** To deepen gas markets in India, further reforms will be undertaken to facilitate transparent price discovery and ease of transactions.

### **New Economy**

**61.** The new economy is based on innovations that disrupt established business models. Artificial intelligence, Internet-of-Things (IoT), 3D printing, drones, DNA data storage, quantum computing, etc., are re-writing the world economic order. India has already embraced new paradigms such as the sharing economy with aggregator platforms displacing conventional businesses. Government has harnessed new technologies to enable direct benefit transfers and financial inclusion on a scale never imagined before.

**62.** It is now a cliché – “data is the new oil” and it is true that Analytics, Fintech and Internet of Things (IOT) are changing the way we deal with our lives. To take advantage of this, I propose:

**62 (1).** To bring out soon a policy to enable private sector to build Data Centre parks throughout the country. It will enable our firms to skilfully incorporate data in every step of their value chains.

**62 (2).** Our vision is that all “public institutions” at Gram Panchayat level such as Anganwadis, health and wellness centres, government schools, PDS outlets, post offices and police stations will be provided with digital connectivity. So, Fibre to the Home (FTTH) connections through Bharatnet will link 100,000 gram panchayats this year.

It is proposed to provide ₹ 6000 crore to Bharatnet programme in 2020-21.

**63.** We need to expand the base for knowledge-driven enterprises. Intellectual property creation and protection will play an important role. Several measures are proposed in this regard, which will benefit the Start-ups.

**63 (1).** A digital platform would be promoted that would facilitate seamless application and capture of IPRs. Also, in an Institute of Excellence, a Centre would be established that would work on the complexity and innovation in the field of Intellectual Property.

**63 (2).** Knowledge Translation Clusters would be set up across different technology sectors including new and emerging areas.

**63 (3).** For designing, fabrication and validation of proof of concept, and further scaling up Technology Clusters, harbouring such test beds and small scale manufacturing facilities would be established.

**63 (4).** Mapping of India’s genetic landscape is critical for next generation medicine, agriculture and for bio-diversity management. To support this development, we will initiate two new national level Science Schemes, to create a comprehensive database.

**63 (5).** The government proposes to provide early life funding, including a seed fund to support ideation and development of early stage Start-ups.

**64.** Quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cyber security with wide-spread applications. It is expected that lots of commercial applications would emerge from theoretical constructs which are developing in this area.

It is proposed to provide an outlay of ₹ 8000 crore over a period five years for the National Mission on Quantum Technologies and Applications.

#### **Caring Society**

In our third theme we focus on Women & Child, Social Welfare; Culture and Tourism and also on Environment and Climate Change.

#### **Women & Child, Social Welfare**

**65.** I am pleased to inform the House that “Beti Bachao Beti Padhao” has yielded tremendous results. Gross enrolment ratio of girls across all levels of education is now higher than boys. At elementary level, it is 94.32 % as against 89.28% for boys. At Secondary level, it is 81.32 % as compared to 78 %, At higher secondary level girls have achieved a level of 59.70 % as compared to 57.54 % for boys.

**66.** Health of mother and child are closely correlated. Nutrition is the critical component of health. To improve the nutritional status of children (0-6 years), adolescent girls, pregnant women and lactating mothers, our Prime Minister launched a “Poshan Abhiyan” in 2017-18. More than six lakh anganwadi workers are equipped with smart phones to upload

the nutritional status of more than 10 crore households. The scale of these developments is unprecedented.

**67.** Women's age of marriage was increased from fifteen years to eighteen years in 1978, by amending erstwhile Sharda Act of 1929. As India progresses further, opportunities open up for women to pursue higher education and careers. There are imperatives of lowering MMR as well as improvement of nutrition levels. Entire issue about age of a girl entering motherhood needs to be seen in this light. I propose to appoint a task force that will present its recommendations in six months' time.

I propose to provide ₹35600 crore for nutrition-related programmes for the financial year 2020-21.

**68.** In continuing with our government's commitment to the welfare of women, this budget provides for about ₹ 28,600 crore for programs that are specific to women.

**69.** Our government is determined that there shall be no manual cleaning of sewer systems or septic tanks. Suitable technologies for such tasks have been identified by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The Ministry is working with urban local bodies for the adoption of these technologies. We will now take this to its logical conclusion through legislative and institutional changes. Financial support for wider acceptance of such technologies will be provided.

**70** In furthering this government's commitment towards the welfare of Scheduled Castes and Other Backward classes, I propose a budget provision of about ₹ 85,000 crore for 2020-21.

**71.** In furthering development and welfare of Scheduled tribes, I provide in the Budget for the year 2020-21 an amount of about ₹53,700 crore.

**72.** This government is mindful of the concerns of senior citizens and Divyang. Accordingly, an enhanced allocation of about ₹9,500 crore is being provided for 2020-21.

### **Culture & Tourism**

**73.** Our government proposes to establish an Indian Institute of Heritage and Conservation under Ministry of Culture; it shall have the status of a deemed University to start with. Acquisition of knowledge in disciplines such as museology and archaeology are essential for collecting and analysing scientific evidence of such findings and for dissemination through high quality museums. Currently lack of trained man-power is a handicap for both these disciplines. This also affects tourism.

**74.** Five archaeological sites would be developed as iconic sites with on-site Museums. They are: Rakhigarhi (Haryana), Hastinapur (Uttar Pradesh), Shivsagar (Assam), Dholavira (Gujarat) and Adichanallur (Tamil Nadu).

**75.** Our Prime Minister in January 2020 announced re-curation of the Indian Museum in Kolkata, which is the oldest in the country.

**75 (1).** In the historic Old Mint building Kolkata, a museum on Numismatics and Trade will also be located. Four more museums from across the country shall be taken up for renovation and re-curation so that a world class experience can be offered to visitors. Our government shall also support setting up of a Tribal Museum in Ranchi (Jharkhand).

**75 (2).** A maritime museum would be set up at Lothal—the Harrapan age maritime site near Ahmedabad, by Ministry of Shipping.

I propose to provide ₹ 3,150 crore for Ministry of Culture for 2020-21.

**76.** India has moved up from rank 65 in 2014 to 34 in 2019 in the Travel & Tourism Competitive Index (World Economic Forum). Foreign exchange earnings grew 7.4% to ₹1.88 lakh crores for the period January to November 2019 from ₹1.75 lakh crores

Growth of tourism directly relates to growth and employment. States have a critical role to play. I expect the State governments to develop a roadmap for certain identified destinations and formulate financial plans during 2021 against which specified grants will be made available to the States in 2020-21.

For purpose of tourism promotion, I propose to allocate ₹ 2,500 crore for 2020-21.

### **Environment & Climate Change**

**77.** In September 2019, the Prime Minister has launched the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) with its Secretariat in Delhi. This global partnership is the second such international initiative after the launch of International Solar Alliance in 2015. This Global Partnership will help in addressing a number of Sustainable Development Goals (SDGs), as also the aims of Sendai framework. It will enhance climate change adaptation with a focus on disaster resilient infrastructure

**78.** India submitted its Nationally Determined Contribution, under the Paris Agreement in 2015 on a “best effort” basis, keeping in mind the development imperative of the country. Its implementation effectively begins on 1<sup>st</sup> January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors by the Departments/Ministries concerned through the normal budgeting process.

**79.** There are yet, thermal power plants that are old and their carbon emission levels are high.

For such power plants, we propose that utilities running them would be advised to close them, if their emission is above the pre-set norms. The land so vacated can be put to alternative use.

**80.** In large cities having population above one million, clean air is a matter of concern. The government proposes to encourage such States that are formulating and implementing plans for ensuring cleaner air in cities above one million. Parameters for the incentives would be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate change. Allocation for this purpose is ₹4400 crore for 2020-21.

**நல்ல நாடு**

**பிணியின்மை, செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்**  
**அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து.**

**குறள்- 738**

[The meaning of this kural is that Freedom from illness, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, are the ornaments of a kingdom].

### **Governance**

**81.** Hon’ble Speaker, Sir, all the while I have explained the colour and composition of the bouquet of flowers – schemes and programmes. They were grouped under Aspirational India, Economic Development and Caring India. Now I speak about the two hands that will hold them. One such hand is Governance – clean, corruption-free, policy driven and good in intent and most importantly trusting in faith. Trusting every citizen, the aspirational youth, the hard-working women, the risk-taking entrepreneur, the ever hopeful and untiring farmer or the wise and old senior citizen. Many among them are taxpayers. Others may not

be taxpayers today. Our Prime Minister has laid before us Ease of Living as a goal to be achieved on behalf of all citizens. An important aspect of both ease of living and ease of doing business is fairness and efficiency of tax administration. We wish to enshrine in the statutes a “taxpayer charter” through this budget. Our government would like to reassure taxpayers that we remain committed to taking measures so that our citizens are free from harassment of any kind.

**82.** There has been a debate about building into statutes, criminal liability for acts that are civil in nature. Hence, for Companies Act, certain amendments are proposed to be made that will correct this. Similarly, other laws would also be examined, where such provisions exist and attempts would be made to correct them.

**83.** The Government intends to introduce major reforms in recruitment to Non-Gazetted posts in governments and public sector banks. At present, candidates have to appear for multiple examinations conducted by multiple agencies at different points of time, for similar posts. This places enormous burden on time, effort and cost of young people. To mitigate their hardship faced, it is proposed to set up a National Recruitment Agency (NRA) as an independent, professional, specialist organisation for conduct of a computer-based online Common Eligibility Test for recruitment to Non-Gazetted posts. A test-centre in every district, particularly in the Aspirational Districts would be set up.

**84.** For speedy disposal of commercial and other disputes, Government has constituted various Tribunals and specialised bodies. It is proposed to evolve a robust mechanism for appointment including direct recruitment to these bodies to attract best talents and professional experts.

**85.** A stable and predictable business environment is a key objective of this government. There is also a strong argument for ensuring that contracts are honoured. India has a sound framework related to Contracts Act. We shall deliberate upon strengthening it.

**86.** There is a growing need for the Indian Statistical system to meet the challenges of real time monitoring of our increasingly complex economy. Data must have strong credibility. The proposed new National Policy on Official Statistics would use latest technology including AI. It would lay down a road-map towards modernised data collection, integrated information portal and timely dissemination of information.

**87.** I am happy to inform that India will host G 20 presidency in the year 2022- the year of 75<sup>th</sup> anniversary of independence of Indian Nation. During this presidency, India would be able to drive considerably the global economic and development agenda. For this historic occasion, I allocate a sum of ₹ 100 crore to begin the preparations.

**88.** North Eastern region has a very high priority in Government’s Developmental agenda. Government is ensuring smooth access to financial assistance from multilateral and bilateral funding agencies to help introduce innovative and global best practices. Central Government has effectively used an online portal to reduce gestation period of online. This has improved the flow of funds to the northeast region.

**89.** The Government is fully committed to supporting the all-round development of the newly formed Union Territories of J&K and the Union Territory of Ladakh. Accordingly, an amount of ₹30,757 crore has been provided for the Financial Year 2020-21. An amount of ₹5,958 crore has been provided for the Union Territory of Ladakh.



## **Financial Sector**

**90.** If Governance was described as one of the pair of hands holding the bouquet consisting of Aspirational India, Economic Development and Caring India, the other is the Financial Sector. A clean, reliable and robust financial sector is critical to the economy. In our efforts to achieve the USD 5 trillion economy, the financial architecture should keep evolving and move from strength to strength.

**91.** We had earlier approved consolidation of 10 banks into four. In the last few years, Government of India has infused about ₹ 3,50,000 crore by way of capital into Public Sector Banks for regulatory and growth purposes. Governance reforms would be carried out in these banks, so that they become more competitive.

A few among them will be encouraged to approach capital market to raise additional capital.

**92.** I wish to inform this august House that robust mechanism is in place to monitor the health of all Scheduled Commercial Banks and that depositors' money is safe.

Further, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has been permitted to increase Deposit Insurance Coverage for a depositor, which is now ₹one lakh to ₹five lakh per depositor.

**93.** To strengthen the Cooperative Banks, amendments to the Banking Regulation Act are proposed for increasing professionalism, enabling access to capital and improving governance and oversight for sound banking through the RBI.

**94.** The limit for NBFCs to be eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act 2002 is proposed to be reduced from ₹ 500 crore to asset size of ₹ 100 crore or loan size from existing ₹ 1 crore to ₹ 50 lakh.

**95.** In the last few years, the government has taken concrete steps to bring our banking system to be robust. However, there is a need for greater private capital. Accordingly, it is proposed to sell the balance holding of Government of India IDBI Bank to private, retail and institutional investors through the stock exchange.

**96.** There is a need to take further steps to bring in transparency and greater professionalism in Public Sector Banks. The government will take appropriate measures.

**97.** To help easy mobility while in jobs, we wish to infuse into the Universal Pension coverage with auto enrolment; also, we wish to place such mechanisms which can enable inter-operability and provide safeguards for the accumulated corpus.

Regulating role of PFRDAI requires strengthening. Necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority of India Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from PFRDAI. This would also enable establishment of a Pension Trust by the employees other than Government. I am confident that this will motivate citizens to plan for their old age.

**98.** MSMEs are vital to keep the wheels of economy moving. They also create job, innovate and are risk takers. Several measures for the MSMEs have been taken in the past few years. There are more steps proposed in this budget also.

**98(1).** I propose to make necessary amendments to the Factor Regulation Act 2011. This will enable NBFCs to extend invoice financing to the MSMEs through TReDS, thereby enhancing their economic and financial sustainability.

**98(2).** Working capital credit remains a major issue for the MSMEs. It is proposed to introduce a scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of MSMEs. This subordinate debt to be provided by banks would count as quasi-equity and would be fully guaranteed through the Credit Guarantee Trust for Medium and Small Entrepreneurs (CGTMSE). The corpus of the CGTMSE would accordingly be augmented by the government.

**98(3).** More than five lakh MSMEs have benefitted from restructuring of debt permitted by RBI in the last year. The restructuring window was to end on March 31, 2020. Government has asked RBI to consider extending this window till March 31, 2021.

**98(4).** An app-based invoice financing loans product will be launched. This will obviate the problem of delayed payments and consequential cash flows mismatches for the MSMEs.

**99.** Many mid-size companies are successful domestically but not in export markets. For selected sectors such as pharmaceuticals, auto components and others, we propose to extend handholding support – for technology upgradations, R&D, business strategy etc. A scheme of ₹ 1000 crore will be anchored by EXIM Bank together with SIDBI. Both these institutions would contribute ₹ 50 crore each. This ₹ 100 crore would be achieved towards equity and technical assistance. Debt funding of ₹900 crore from banks would be made available.

### **Financial Markets**

**100.** Last year, in the budget speech, I had mentioned about deepening the bond market. To achieve the aspirational growth rate, we would require flow of capital in our financial system. A lot of work has been done on this in consultation with the RBI.

Hon'ble Speaker, Sir, I am pleased to inform this House of the developments:

**100(1).** Certain specified categories of Government securities would be opened fully for non-resident investors, apart from being available to domestic investors as well.

**100(2).** The limit for FPI in corporate bonds, currently at 9% of outstanding stock, will be increased to 15% of the outstanding stock of corporate bonds.

**100(3).** To improve investors' confidence and to expand the scope of credit default swaps, we propose to formulate a legislation, to be placed soon before the House, for laying down a mechanism for netting of financial contracts.

**101.** The Debt-based Exchange Traded Fund (ETF) recently floated by the government was a big success. Government proposes to expand this by floating a new Debt-ETF consisting primarily of government securities.

This will give retail investors access to government securities as much as giving an attractive investment for pension funds and long-term investors.

**102.** To address the liquidity constraints of the NBFCs/HFCs, post the Union budget 2019-20, the government formulated a Partial Credit Guarantee scheme for the NBFCs. To further this support of providing liquidity, a mechanism would be devised. Government will offer support by guaranteeing securities so floated.

### **Infrastructure Financing**

**103.** Government's commitment for investment in infrastructure was reiterated when ₹103 lakh crore National Infrastructure Pipeline projects were announced. I would also like to inform that about ₹ 22,000 crore has already been provided, as support to Infrastructure Pipeline. This would cater for equity support to Infrastructure Finance Companies such as IIFCL and a subsidiary of NIIF. They would leverage it, as permissible, to create financing pipeline of more than ₹1,00,000 crore. This would create a major source of long term debt for infrastructure projects and fulfil a long awaited requirement.

**104.** IFSC, GIFT city has the potential to become a centre of international finance as well as a centre for high end data processing:

**104 (1).** GIFT IFSC has an approved Free Trade zone for housing vaults. It already has 19 insurance entities, 40 banking entities. It has also provided for setting up of precious metals testing laboratories and refining facilities. With the approval of the regulator, GIFT City would set up an International Bullion exchange(s) in GIFT-IFSC as an additional option for trade by global market participants. This will enable India to enhance its position worldwide, create jobs in India and will lead to better price discovery of gold.

**104 (2).** In recent years there has been a surge in trading volumes of Indian rupee in the offshore financial centres. The Government and RBI has taken various measures to permit Rupee derivatives to be traded in the International Financial Services Centre at GIFT city, Gujarat.

### **Disinvestment**

**105.** Listing of companies on stock exchanges discipline a company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in LIC by way of Initial Public Offer (IPO).

### **Fiscal Management**

**106.** XV Finance Commission has given its first report pertaining to Financial Year 2020-21. In the spirit of co-operative federalism, I am pleased to announce that we have, in substantial measure, accepted the recommendations of the Commission. The commission would submit its final report to the President during the latter part of the year, for five years beginning 2021-22.

**106.** It is decided to transfer to the GST Compensation Fund balances due out of collection of the years 2016-17 and 2017-18, in two instalments. Hereinafter, transfers to the fund would be limited only to collection by way of GST compensation cess.

**107.** A fundamental overhaul of Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Schemes is necessary, to align them with emerging social and economic needs of tomorrow, and **to ensure that scarce public resources are spent optimally.**

**108.** Recently there has been a debate over transparency and credibility of the projected fiscal numbers. Let me assure the House that the procedure adopted is compliant with the FRBM Act. This is also consistent with the practices hitherto followed.

However, for greater clarity, I have enumerated those central Government debt that are not part of market borrowing and are used to fund the expenditure at the annexes. Servicing of interest and repayment of these debts as hitherto, are done out of Consolidated fund of India.

**109.** Revised Estimates of Expenditure for the Financial Year 2019-20 are at a level of ₹ 26.99 lakh Crore and the receipts are estimated at ₹19.32 lakh crore.

We have estimated nominal growth of GDP for year 2020-21, on the basis of trends available, at 10%. Accordingly, receipts for the year 2020-21 are estimated at ₹ 22.46 lakh cr and, keeping in mind commitment of the Government towards various schemes and need for improvement in quality of life, level of expenditure has been kept at ₹ 30.42 lakh crore.

During the year Government has unfailingly worked towards keeping up the capital expenditure. Actually, there is substantial enhancement. All the flagship schemes of the government have been fully provided for. Details may be seen at the annexes to the printed copy of my speech.

**110.** Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Recently Government has undertaken very significant tax reforms for boosting investments. However, expected tax buoyancy will take time.

We estimate a fiscal deficit of 3.8% in RE 2019-20 and 3.5% for BE 2020-21. This estimation is consistent with Government's abiding commitment to macroeconomic stability. It comprises of,

- (a) 3.3% for year 2019-20, and 3% for the 2020-21 budget estimate;
- (b) Section 4 (2) of the FRBM Act provides for a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications. Therefore, I have taken a deviation of 0.5%, consistent with Section 4(3) of FRBM Act, both for RE 2019-20 and BE 2020-21.

Accordingly, the return path is being laid before the parliament as a part of Medium Term Fiscal Policy cum Strategy Statement. This fiscal path commits us to the path of fiscal consolidation without compromising the needs of investment out of public funds.

Accordingly, net market borrowings for the year 2019-20 would be ₹ 4.99 lakh crore and for the year 2020-21, it would be ₹5.36 lakh crore.

**111.** A good part of the borrowings for the financial year 2020-21 would go towards Capital expenditure of the Government that has been scaled up by more than 21%. As, I had previously mentioned another about ₹ 22,000 crore have been allocated for equity to fund certain specified infrastructure finance companies, who would leverage it manifold and provide much needed long-term finance to Infrastructure sector. **That should spur growth impulses in the economy.**

I would, now, move to Part B of my speech.

## PART B

### Direct Tax

**112.** Mr Speaker, Sir, our Government has spearheaded radical fiscal measures to ensure that India's economy continues to tread the path of high growth. These are times when countries are competing with each other like never before to become the most attractive destination for doing business. Therefore, to make sure that India stays globally competitive and a favoured destination for investment, we took a bold historic decision of reducing the corporate tax rate for new companies in the manufacturing sector to an unprecedented level of 15%. Similarly, for the existing companies, the rate has also been brought down to just 22%. As a result, our corporate tax rates are now amongst the lowest in the world. This will enable companies to expand their businesses and make fresh investments in the coming future. Though we will have loss of substantial revenue due to these measures in the short-run, I am certain that our economy will reap huge returns on this score in due course.

प्रजानामेवभूत्यर्थसताभ्योबलिमग्रहीत्।

सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्तेहिरसंरविः ॥

Surya, the Sun, collects vapour from little drops of water. So does the King.

They give back copiously. They collect only for people's wellbeing.

[Verse 18, Sarga 1 Raghuvamsa by Kalidasa]

**113.** In continuation of the reform measures already taken so far, the tax proposals in this budget will introduce further reforms to stimulate growth, simplify tax structure, bring ease of compliance, and reduce litigations.

**114. Personal Income Tax and simplification of taxation**

- In the interim Budget of 2019, our government exempted individuals having income up to ₹ 5 Lakh from paying any income tax. Presently, an individual pays 20% on income between ₹ 5 Lakh to ₹ 10 Lakh and 30% on income above ₹ 10 Lakh. Further, currently the Income Tax Act is riddled with various exemptions and deductions which make compliance by the taxpayer and administration of the Income Tax Act by the tax authorities a burdensome process. It is almost impossible for a taxpayer to comply with the Income-tax law without taking help from professionals.
- In order to provide significant relief to the individual taxpayers and to simplify the Income-tax law, I propose to bring a new and simplified personal income tax regime wherein income tax rates will be significantly reduced for the individual taxpayers who forgo certain deductions and exemptions.
- Under the new regime, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between ₹ 5 Lakh to ₹ 7.5 Lakh against the current rate of 20%.
- For income between ₹ 7.5 Lakh to ₹ 10 Lakh he will pay at the reduced rate of 15% against the current rate of 20 %.
- Similarly for the income between ₹ 10 Lakh to ₹ 12.5 Lakh the taxpayer will pay at the reduced rate of 20% against the current rate of 30 %.
- The income between ₹ 12.5 Lakh to ₹ 15 Lakh will be taxed at the reduced rate of 25% against the existing rate of 30 %. Incomes above ₹ 15 lakh will be continued to be taxed at the rate of 30 %.
- Those earning up to ₹ 5 lakhs shall not pay any tax either in the old regime or in the new regime.
- The proposed tax structure will provide significant relief to taxpayers and more so to those in the middle class.

Taxable Income Slab (₹)	Existing Tax Rates	New Tax Rates
0-2.5 Lakh	Exempt	Exempt
2.5-5 Lakh	5%	5%
5-7.5 Lakh	20%	10%
7.5-10 Lakh	20%	15%
10-12.5 Lakh	30%	20%
12.5-15 Lakh	30%	25%
Above 15 Lakh	30%	30%

- In the new tax regime, substantial tax benefit will accrue to a taxpayer depending upon exemptions and deductions claimed by him. For example, a person earning ₹ 15 lakh in a year and not availing any deductions etc. will pay only ₹, 1,95,000 as compared to ₹, 2,73,000 in the old regime. Thus his tax burden shall be reduced by 78,000 in the new regime. He would still be the gainer in the new regime even if he was taking deduction of ₹ 1.5 Lakh

under various sections of Chapter- VI-A of the Income Tax Act under the old regime.

- The new tax regime shall be optional for the taxpayers. An individual who is currently availing more deductions & exemption under the Income Tax Act may choose to avail them and continue to pay tax in the old regime.
- The new personal income tax rates will entail estimated revenue forgone of ₹ 40,000 crore per year. We have also initiated measures to prefill the income tax return so that an individual who opts for the new regime would need no assistance from an expert to file his return and pay income tax.
- *In order to simplify income tax system, I have reviewed all the exemptions and deductions which got incorporated in the income tax legislation over the past several decades. It was surprising to know that currently more than one hundred exemptions and deductions of different nature are provided in the Income-tax Act. I have removed around 70 of them in the new simplified regime. We will review and rationalise the remaining exemptions and deductions in the coming years with a view to further simplifying the tax system and lowering the tax rate.*

#### **115. Dividend Distribution Tax**

- Currently, companies are required to pay Dividend Distribution Tax (DDT) on the dividend paid to its shareholders at the rate of 15% plus applicable surcharge and cess in addition to the tax payable by the company on its profits.
- It has been argued that the system of levying DDT results in increase in tax burden for investors and especially those who are liable to pay tax less than the rate of DDT if the dividend income is included in their income.
- Further, non-availability of credit of DDT to most of the foreign investors in their home country results in reduction of rate of return on equity capital for them. In order to increase the attractiveness of the Indian Equity Market and to provide relief to a large class of investors, I propose to remove the DDT and adopt the classical system of dividend taxation under which the companies would not be required to pay DDT. The dividend shall be taxed only in the hands of the recipients at their applicable rate.
- Further, in order to remove the cascading effect, I also propose to allow deduction for the dividend received by holding company from its subsidiary. The removal of DDT will lead to estimated annual revenue forgone of ₹ 25,000 Crore.
- This is another bold move which will further make India an attractive destination for investment.

#### **116. Concessional tax rate for Electricity generation companies**

- In order to give boost to the manufacturing sector, new provisions were introduced in September 2019 offering a concessional corporate tax rate of 15% to the newly incorporated domestic companies in the manufacturing sector which start manufacturing by 31<sup>st</sup> March, 2023.
- In order to attract investment in power sector, I propose to extend the concessional corporate tax rate of 15% to new domestic companies engaged in the generation of electricity.

**117. Tax concession for foreign investments**

- In order to incentivise the investment by the Sovereign Wealth Fund of foreign governments in the priority sectors, I propose to grant 100% tax exemption to their interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified sectors before 31<sup>st</sup> March, 2024 and with a minimum lock-in period of 3 years.
- In order to make available foreign funds at a lower cost, I propose to extend the period of concessional withholding rate of 5% under section 194LC for interest payment to non-residents in respect of moneys borrowed and bonds issued up to 30<sup>th</sup> June, 2023.
- I also propose to extend the period up to 30<sup>th</sup> June, 2023 for lower rate of withholding of 5% under section 194LD for interest payment to Foreign Portfolio Investors (FPIs) and Qualified Foreign Investors (QFIs) in respect of bonds issued by Indian companies and government securities.
- I further propose to extend the concessional rate of withholding of 5% under section 194LD to the interest payment made on the Municipal Bonds.
- In order to incentivise listing of bonds at IFSC exchange, I propose to further reduce the withholding rate from 5% to 4% on interest payment on the bonds listed on its exchange.

**118. Start-ups**

Start-ups have emerged as engines of growth for our economy. Over the past year, our Government has taken several measures to hand-hold them and support their growth. During their formative years, Start-ups generally use Employee Stock Option Plan (ESOP) to attract and retain highly talented employees. ESOP is a significant component of compensation for these employees. Currently, ESOPs are taxable as perquisites at the time of exercise. This leads to cash-flow problem for the employees who do not sell the shares immediately and continue to hold the same for the long-term. In order to give a boost to the start-up ecosystem, I propose to ease the burden of taxation on the employees by deferring the tax payment by five years or till they leave the company or when they sell their shares, whichever is earliest.

- Further, an eligible Start-up having turnover up to 25 crores is allowed deduction of 100% of its the profits for three consecutive assessment years out of seven years if the total turnover does not exceed 25 crore rupees. In order to extend this benefit to larger start-ups, I propose to increase the turnover limit from existing ₹ 25 crore to ₹ 100 crores. Moreover, considering the fact that in the initial years, a start-up may not have adequate profit to avail this deduction, I propose to extend the period of eligibility for claim of deduction from the existing 7 years to 10 years.

**119. Concessional tax rate for Co-operatives**

- Co-operative societies play an extremely important role in our economy in facilitating access to credit, procurement of inputs and marketing of products to their members. These cooperatives are currently taxed at a rate of 30% with surcharge and cess. As a major concession and in order to bring parity between the co-operative societies and corporates, I propose to provide an option to cooperative societies to be taxed at 22% plus 10% surcharge and 4% cess with no exemption/deductions. Further, I also propose to exempt these co-operative societies from Alternative Minimum Tax (AMT) just like companies under the new tax regime are exempted from the Minimum Alternate Tax (MAT).

**120. Medium, Small and Micro Enterprises (MSME)**

- Currently, businesses having turnover of more than one crore rupees are required to get their books of accounts audited by an accountant. In order to reduce the compliance burden on small retailers, traders, shopkeepers who comprise the MSME sector, I propose to raise by five times the turnover threshold for audit from the existing ₹ 1 crore to ₹ 5 crore. Further, in order to boost less cash economy, I propose that the increased limit shall apply only to those businesses which carry out less than 5% of their business transactions in cash.

**121. Affordable housing**

- For realisation of the goal of 'Housing for All' and affordable housing, in the last budget I had announced an additional deduction of up to one lakh fifty thousand rupees for interest paid on loans taken for purchase of an affordable house. The deduction was allowed on housing loans sanctioned on or before 31st March, 2020. In order to ensure that more persons avail this benefit and to further incentivise the affordable housing, I propose to extend the date of loan sanction for availing this additional deduction by one more year.
- Further, in order to boost the supply of affordable houses in the country, a tax holiday is provided on the profits earned by developers of affordable housing project approved by 31<sup>st</sup> March, 2020. In order to promote the affordable housing projects, I propose to extend the date of approval of affordable housing projects for availing this tax holiday by one more year.

**122. Concession to real estate transactions**

- Currently, while taxing income from capital gains, business profits and other sources in respect of transactions in real estate, if the consideration value is less than circle rate by more than 5 percent, the difference is counted as income both in the hands of the purchaser and seller. In order to minimize hardship in real estate transaction and provide relief to the sector, I propose to increase the limit of 5% to 10%.

**123. Charity institutions**

- Acknowledging the important role played by the charitable institutions in the society, the income of these institutions is fully exempt from taxation. Further, donation made to these institutions is also allowed as deduction in computing the taxable income of the donor.
- Currently, a taxpayer is required to fill the complete details of the donee in the income tax return for availing deduction.
- In order to ease the process of claiming deduction for donation, it is proposed to pre-fill the donee's information in taxpayer's return on the basis of information of donations furnished by the donee. This would result in hassle-free claim of deduction for the donation made by the taxpayer.
- Further, in order to claim the tax exemption, the charity institutions have to be registered with the Income Tax Department. In the past, the process of the registration was completely manual and scattered all over the country.
- In order to simplify the compliance for the new and existing charity institutions, I propose to make the process of registration completely electronic under which a unique registration number (URN) shall be issued to all new and



existing charity institutions. Further, to facilitate the registration of the new charity institution which is yet to start their charitable activities, I propose to allow them provisional registration for three years.

#### 124. **Faceless appeals**

Our government is committed to bringing in transformational changes so that maximum governance is provided with minimum government. In order to impart greater efficiency, transparency and accountability to the assessment process, a new faceless assessment scheme has already been introduced. Currently, most of the functions of the Income Tax Department starting from the filing of return, processing of returns, issuance of refunds and assessment are performed in the electronic mode without any human interface. In order to take the reforms initiated by the Department to the next level and to eliminate human interface, I propose to amend the Income Tax Act so as to enable Faceless appeal on the lines of Faceless assessment.

#### 125. **No Dispute but Trust Scheme – ‘Vivad Se Vishwas’ Scheme**

- Sir, in the past our Government has taken several measures to reduce tax litigations. In the last budget, *SabkaVishwas Scheme* was brought in to reduce litigation in indirect taxes. It resulted in settling over 1,89,000 cases. Currently, there are 4,83,000 direct tax cases pending in various appellate forums i.e. Commissioner (Appeals), ITAT, High Court and Supreme Court. This year, I propose to bring a scheme similar to the indirect tax *SabkaVishwas* for reducing litigations even in the direct taxes.
- Under the proposed ‘*Vivad Se Vishwas*’ scheme, a taxpayer would be required to pay only the amount of the disputed taxes and will get complete waiver of interest and penalty provided he pays by 31<sup>st</sup> March, 2020. Those who avail this scheme after 31<sup>st</sup> March, 2020 will have to pay some additional amount. The scheme will remain open till 30<sup>th</sup> June, 2020.
- Taxpayers in whose cases appeals are pending at any level can benefit from this scheme.
- I hope that taxpayers will make use of this opportunity to get relief from vexatious litigation process.

#### 126. **Losses of merged banks**

- As a part of consolidation of the financial sector, our Government has brought out schemes for merger and amalgamation of public sector banks. In order to ensure that the amalgamated entities are able to take the benefit of unabsorbed losses and depreciation of the amalgamating entities, I propose to make necessary amendments to the provisions of the Income-tax Act.

#### 127. **Taxpayer’s Charter**

- Any tax system requires trust between taxpayers and the administration. This will be possible only when taxpayer’s rights are clearly enumerated. Towards this end, and with the objective of enhancing the efficiency of the delivery system of the Income Tax Department, I propose to amend the provisions of the Income Tax Act to mandate the Central Board of Direct Taxes (CBDT) to adopt a Taxpayers’ Charter. The details of the contents of the charter shall be notified soon.

**128. Instant PAN through Aadhaar**

- In the last Budget, I had introduced the interchangeability of PAN and Aadhaar for which necessary rules were already notified. In order to further ease the process of allotment of PAN, soon we will launch a system under which PAN shall be instantly allotted online on the basis of Aadhaar without any requirement for filling up of detailed application form.

**129.** Our Government brought in the GST as a historic reform of the indirect taxes in 2017. We also took a path-breaking step of simplifying and rationalising corporate tax in September, 2019. More importantly, we offered a rate of corporate tax, which perhaps is the lowest in the world. Continuing on this path, we have now put the personal income tax at its lowest ever rate and totally removed DDT at the company's hands. Further, the direct taxes are now the lowest, simplest, and smoothest. Direct tax on the Start-ups also has seen many reformatory steps in quick succession. Even ease of compliance is seeing unprecedented changes. Last but not the least, personal interface with tax administration is at the minimum ever.

**Indirect Tax**

**130.** As I mentioned earlier in Part A of my speech, reforms are continuing in GST. A simplified return shall be implemented from the 1<sup>st</sup> April, 2020. This is under pilot run. It will make return filing simple with features like SMS based filing for nil return, return pre-filing, improved input tax credit flow and overall simplification.

**131.** Refund process has been simplified and has been made fully automated with no human interface.

**132.** Electronic invoice is another innovation wherein critical information shall be captured electronically in a centralized system. It will be implemented in a phased manner starting from this month itself on optional basis. It will facilitate compliance and return filing.

**133.** Several measures have been taken for improving compliance. Aadhaar based verification of taxpayers is being introduced. This will help in weeding out dummy or non-existent units. Dynamic QR-code is proposed for consumer invoices. GST parameters will be captured when payment for purchases is made through the QR-code. A system of cash reward is envisaged to incentivise customers to seek invoice. Deep data analytics and AI tools are being used for crackdown on GST input tax credit, refund, and other frauds and to identify all those who are trying to game the system. Invoice and input tax credit matching is being done wherein returns having mismatch more than 10 per cent or above a threshold are identified and pursued. Significant policy level changes have also been made. GST rate structure is also being deliberated so as to address issues like inverted duty structure.

**134.** On Customs side, a number of measures have been taken for ease of doing business. India's quantum leap in the Trading Across Border parameter of Ease of Doing Business rankings by the World Bank is a testimony to these efforts. India's rank on this parameter improved from 146 to 80 in 2018 and further to 68 in 2019. Measures have also been taken for providing a level playing field to our domestic manufacturers, particularly the MSME sector and for securing borders.

**135.** It has been observed that imports under Free Trade Agreements (FTAs) are on the rise. Undue claims of FTA benefits have posed threat to domestic industry. Such imports require stringent checks. In this context, suitable provisions are being incorporated in the Customs Act. In the coming months we shall review Rules of Origin requirements, particularly for certain sensitive items, so as ensure that FTAs are aligned to the conscious direction of our policy.

**136.** We are also strengthening provisions relating to safeguard duties which are applied when surge in imports causes serious injury to domestic industry. Amended provisions shall enable regulating such surge in imports in a systematic way. The provisions for checking dumping of goods and imports of subsidized goods are also being strengthened for ensuring a level playing field for domestic industry. These changes are in line with the international best practices.

**137.** Exemptions from customs duty have been given in public interest from time to time. However, a number of these have outlived their utility or have become outdated. On review, certain such exemptions are being withdrawn. Remaining custom duty exemptions shall be comprehensively reviewed by September, 2020 for taking a view on their relevance. I propose to crowd source suggestions for such reviews. Suggestions would also be invited in respect of the Customs laws and procedures for aligning them with the needs of changing times and ease of doing business.

**138.** Labour intensive sectors in MSME are critical for employment generation. Cheap and low-quality imports are an impediment to their growth. Special attention has been taken to put measured restraint on import of those items which are being produced by our MSMEs with better quality. Keeping in view the need of this sector, customs duty is being raised on items like footwear and furniture.

**139.** Our policy of Make in India has started giving dividends. India is now making world class goods and exporting such products. We have made considerable progress in medical equipment too. Till few years back we were dependent on imports for medical equipment. Now, not only we are manufacturing medical equipment but also exporting them in large quantities. This sector deserves further fillip. Government has also been committed to provide health services to all. Ayushman Bharat has made it possible. To achieve the twin objectives of giving impetus to the domestic industry and also to generate resource for health services, I propose to impose a nominal health cess, by way of a duty of customs, on the imports of medical equipment keeping in view that these goods are now being made significantly in India. The proceed from this cess shall be used for creating infrastructure for health services in the aspirational districts.

**140.** Under Make in India initiative, well laid out customs duty rates were pre-announced for items like mobile phones, electric vehicles and their components. This has ensured gradual increase in domestic value addition capacity in India. Customs duty rates are being revised on electric vehicles, and parts of mobiles as part of such carefully conceived Phased Manufacturing Plans.

**141.** In other changes, customs duty is being reduced on certain inputs and raw materials while it is being revised upward on certain goods which are being made domestically. In the previous budget, basic custom duty of 10% was imposed on the news print and lightweight coated paper. However, since then I have received several references that this levy has put additional burden on print media at a time when it is going through a difficult phase. I, therefore, propose to reduce basic customs duty on imports of news print and light-weight coated paper from 10% to 5%.

**142.** Chemicals are crucial feed stocks for downstream users. PTA, for example, is a critical input for textile fibres and yarns. Its easy availability at competitive prices is desirable to unlock immense potential in textile sector which is a significant employment generator. Therefore, in the larger public interest, anti-dumping duty on PTA is being abolished.

**143.** As a revenue measure, I propose to raise excise duty, by way of National Calamity Contingent Duty on Cigarettes and other tobacco products. However, no change is being made in the duty rates of bidis.

**144.** Finally, continuing the tax reform is an ongoing challenge and we propose to pursue them with full vigour.

**145.** Details of my budget proposals relating to direct and indirect taxes are in the Annexure to my speech.

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budgets)

**Annex-I**

**Budget Outlay for Major Sectors**

(₹ crore)

Sl. No.	Sector Name	BE 19-20	RE 19-20	BE 20-21
<b>I</b>	<b>Aspirational India</b>	<b>4,67,517</b>	<b>4,36,913</b>	<b>4,82,401</b>
a	Agriculture & Allied, Irrigation & Rural Development	2,76,380	2,49,910	2,83,202
b	Wellness, Water, Sanitation	93,294	89,618	96,885
c	Education & Skill Development	97,843	97,385	1,02,314
<b>II</b>	<b>Economic Development</b>	<b>2,23,695</b>	<b>2,24,941</b>	<b>2,37,604</b>
a	Industry & Commerce	27,043	28,608	27,227
b	Transport Infrastructure	1,57,437	1,58,207	1,69,637
c	Energy	39,215	38,127	40,740
<b>III</b>	<b>New Economy</b>	<b>40,534</b>	<b>34,724</b>	<b>42,852</b>
a	Information Technology & Space Technology	19,127	18,979	20,379
b	Communication (Bharat Net)	8,350	3,000	8,000
c	Science & Technology	13,056	12,745	14,473
<b>IV</b>	<b>Caring Society</b>	<b>59,036</b>	<b>54,831</b>	<b>62,626</b>
a	Women & Child Development and Social welfare	50,850	48,210	53,876
b	Culture & Tourism	5,232	3,963	5,650
c	Environment & Climate Change	2,955	2,658	3,100
<b>V</b>	<b>Financial Sector</b>	<b>19,002</b>	<b>23,686</b>	<b>40,433</b>
a	Banking, Insurance, Financial Market and Infra Finance	19,002	23,686	40,433

## Annex – II

## Major Scheme Allocation

(₹ crore)

S. No.	Name of the Scheme	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2020-21
1	National Social Assistance Program	9,200	9,200	9,197
2	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program	60,000	71,002	61,500
3	Umbrella Scheme for Development of Schedule Castes	5,445	5,568	6,242
4	Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes	3,810	4,194	4,191
5	Umbrella Programme for Development of Minorities	1,590	1,709	1,820
6	Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups	1,818	1,846	2,210
7	National Ganga Plan	750	353	800
9	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna	19,000	14,070	19,500
10	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)	25,853	25,328	27,500
11	Jal Jeevan Mission (JJM)	10,001	10,001	11,500
12	Swachh Bharat Mission	12,644	9,638	12,294
13	National Health Mission	33,651	34,290	34,115
14	National Education Mission- Samgra Shiksha	38,547	37,672	39,161
15	PMJAY-Ayushman Bharat	6,556	3,314	6,429
16	Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)	75,000	54,370	75,000
17	Deen Dayal Antyodaya Yojana- National Livelihood Mission - Aajeevika	9,774	9,774	10,005
18	Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana	4,000	4,733	6,020
19	Umbrella Integrated Child development Scheme	27,584	24,955	28,557
20	National Programme of Mid Day Meal in Schools	11,000	9,912	11,000

**Annex – III****Transfer of Resources to States and Union Territories with Legislature****(₹ crore)**

	<b>BE 2019-20</b>	<b>RE 2019-20</b>	<b>BE 2020-21</b>
<b>I. Devolution of States share in taxes</b>	<b>8,09,133</b>	<b>6,56,046</b>	<b>7,84,181</b>
<b>II. Some Important Items of Transfer</b>	<b>54,581</b>	<b>57,344</b>	<b>73,275</b>
1. Assistance to States from NDRF	10,000	20,000	25,000
2. Central Pool of Resources for North Eastern Region and Sikkim	392	380	407
3. Externally Added Projects - Grants	4,500	3,000	4,000
4. Externally Aided Projects-Loan	19,723	25,000	25,000
5. Schemes of North East Council	326	324	287
6. Schemes under Provision to Article 275(1) of the Constitution	2,321	2,321	1,199
7. Special Assistance under the demand - Transfers to States	15,000	4,000	15,000
8. Special Central Assistance to Scheduled Castes under Demand- Department of Social Justice and Empowerment	1,074	1,074	1,172
9. Special Central Assistnace to Tribal Area under the Demand - Ministry of Tribal Affairs	1,245	1,245	1,210
<b>III. Finance Commission Grants</b>	<b>1,20,466</b>	<b>1,23,710</b>	<b>1,49,925</b>
1. Grant for local bodies - Rural Bodies	52,558	58,616	69,925
2. Grants for Urban Local Bodies	23,359	25,843	30,000
3. Grants-in-Aid for SDRF	10,344	10,938	20,000
4. Post Devolution Revenue Deficit Grants	34,206	28,314	30,000
<b>IV. Total Transfer to States [Other than (I)+(II)+(III)]</b>	<b>3,35,220</b>	<b>3,22,443</b>	<b>3,35,878</b>
1. Under Centrally Sponsored Schemes (Revenue)	2,92,003	2,83,057	2,95,269
2. Under Central Sector Schemes (Revenue)	42,076	38,227	39,451
3. Under Other Categories of Expenditure (Revenue)	1,033	1,055	1,066
4. Capital Transfers	109	104	93
<b>V. Total Transfer to Delhi and Puducherry</b>	<b>10,028</b>	<b>28,419</b>	<b>47,408</b>
1. Under Centrally Sponsored Schemes (Revenue)	2,026	1,999	5,603
2. Under Central Sector Schemes (Revenue)	89	222	299
3. Under Other Categories of Expenditure (Revenue)	7,613	25,972	41,355
4. Capital Transfers	300	225	150
<b>Total Transfer to States/UTs</b>	<b>13,29,428</b>	<b>11,87,961</b>	<b>13,90,666</b>

**Annex – IV****Allocation for Major Ministries/ Departments****(₹ crore)**

<b>Sl. No.</b>	<b>Ministry/Department</b>	<b>BE 2019-20</b>	<b>RE 2019-20</b>	<b>BE 2020-21</b>
1	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	1,30,485	1,01,904	1,34,400
2	Department of Agricultural Research and Education	8,079	7,846	8,363
3	Atomic Energy	16,926	17,426	18,229
4	Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	1,940	1,857	2,122
5	Department of Fertilisers	80,035	80,035	71,345
6	Ministry of Civil Aviation	4,500	3,700	3,798
7	Department of Commerce	6,219	7,219	6,219
8	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	5,675	6,490	6,606
9	Department of Posts	11,299	12,398	15,525
10	Department of Telecommunications	27,338	23,350	66,432
11	Department of Consumer Affairs	2,272	2,050	2,300
12	Department of Food and Public Distribution	1,92,240	1,15,240	1,22,235
13	Ministry of Culture	3,042	2,547	3,150
14	Defence Services (Revenue)	2,01,902	2,05,902	2,09,319
15	Capital Outlay on Defence Services	1,03,394	1,10,394	1,13,734
16	Defence Pensions	1,12,080	1,17,810	1,33,825
17	Ministry of Development of North Eastern Region	3,000	2,670	3,049
18	Ministry of Earth Sciences	1,902	1,810	2,070
19	Ministry of Electronics and Information Technology	6,654	5,839	6,899
20	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	2,955	2,658	3,100
21	Ministry of External Affairs	17,885	17,372	17,347
22	Department of Economic Affairs	14,312	15,952	29,308
23	Department of Financial Services	4,690	7,734	11,125
24	Department of Revenue	1,02,048	1,22,066	1,36,640
25	Interest Payments	6,60,471	6,25,105	7,08,203
26	Pensions	48,565	50,565	61,169
27	Transfers to States	1,55,447	1,55,447	2,00,447
28	Department of Fisheries	805	700	825
29	Department of Animal Husbandry and Dairying	2,932	2,790	3,289
30	Ministry of Food Processing Industries	1,197	1,043	1,233
31	Department of Health and Family Welfare	62,659	62,659	65,012
32	Department of Health Research	1,900	1,950	2,100

Sl. No.	Ministry/Department	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2020-21
33	Ministry of Home Affairs	4,896	19,955	8,002
34	Ladakh	...	...	5,958
35	Transfers to Jammu and Kashmir	...	...	30,757
36	Ministry of Housing and Urban Affairs	48,032	42,267	50,040
37	Department of School Education and Literacy	56,537	56,537	59,845
38	Department of Higher Education	38,317	38,317	39,467
39	Ministry of Information and Broadcasting	4,375	4,065	4,375
40	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	8,245	7,518	8,960
41	Department of Drinking Water and Sanitation	20,016	18,360	21,518
42	Ministry of Labour and Employment	11,184	11,184	12,065
43	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	7,011	7,011	7,572
44	Ministry of Minority Affairs	4,700	4,700	5,029
45	Ministry of New and Renewable Energy	5,255	3,892	5,753
46	Ministry of Panchayati Raj	871	500	901
47	Ministry of Petroleum and Natural Gas	42,901	42,901	42,901
48	Ministry of Power	15,875	15,875	15,875
49	Ministry of Railways	68,019	69,967	72,216
50	Ministry of Road Transport and Highways	83,016	83,016	91,823
51	Department of Rural Development	1,17,647	1,22,649	1,20,147
52	Department of Land Resources	2,227	1,900	2,251
53	Department of Science and Technology	5,580	5,481	6,302
54	Department of Biotechnology	2,580	2,381	2,787
55	Department of Scientific and Industrial Research	4,896	4,883	5,385
56	Ministry of Shipping	1,903	1,523	1,800
57	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	2,989	2,531	3,002
58	Department of Social Justice and Empowerment	8,885	8,885	10,104
59	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1,205	1,100	1,325
60	Department of Space	12,473	13,139	13,479
61	Ministry of Statistics and Programme Implementation	5,231	5,231	5,444
62	Ministry of Textiles	4,831	4,831	3,515
63	Ministry of Tourism	2,189	1,416	2,500
64	Ministry of Tribal Affairs	6,895	7,340	7,411
65	Ministry of Women and Child Development	29,165	26,185	30,007
66	Ministry of Youth Affairs and Sports	2,217	2,777	2,827



## Annex-V

Statement of Extra Budgetary & Other Resources (Govt. fully serviced bonds, NSSF etc.)				
(₹ crore)				
Part-A – EBRs mobilised through issue of Govt. fully serviced bonds				
Demand No.	Name of the Ministry/Department and Name of the Scheme	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2020-21
42	Department of Health & Family Welfare Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana	5,000.00	2,700.00	3,000.00
57	Ministry of Housing & Urban Affairs Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Urban	20,000.00	10,000.00	10,000.00
59	Department of Higher Education Revitalising Infrastructure and Systems in Higher Education (RISE)	5,000.00	1,000.00	3,000.00
61	Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (i) Polavaram Irrigation Project (ii) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (AIBP & other Projects)	--- 4,882.00	1,850.00 3,033.96	5,000.00
62	Department of Drinking Water & Sanitation (i) Swachh Bharat Mission (Rural) (ii) Jal Jeevan Mission/National Rural Drinking Water Programme	5,000.00 6,300.00	5,000.00 2,000.00	12,000.00
70	Ministry of New & Renewable Energy Pradhan Mantri-Kisan Urja Sanrakshan Evam Utthan Mahabhiyan (PM-KUSUM)	822.00	500.00	1,000.00
77	Ministry of Power Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana/SAUBHAGYA	9,000.00	8,500.00	5,500.00
85	Department of Rural Development Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Rural	---	10,000.00	10,000.00
90	Ministry of Shipping Inland Waterways Authority of India (IWAI) Projects	1,000.00	---	---
Total		57,004.00	44,583.96	49,500.00

## Part-B – Financial support extended through loans from NSSF

Sl. No.	Name of the Ministry/Department/ Name of the Entity	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2020-21
1	Department of Food & Public Distribution Food Corporation of India	---	1,10,000.00	1,36,600.00
2.	Ministry of Housing & Urban Affairs Building Materials & Technology Promotion Council(BMTPC)	---	15,000.00	---
3.	Department of Fertilizers (i) Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (ii) Metals & Minerals Trading Corporation	---	1,805.00 1,310.00	---
	Total	---	1,28,115.00	1,36,600.00
	Grand Total (A+B)	57,004.00	1,72,698.96	1,86,100.00

## Notes:

(i) Estimates of financial support through NSSF as indicated in RE 2019-20 & BE 2020-21 is arrived on the basis of gap between total requirement for funds (including repayment of NSSF loan in FY 2019-20 & FY 2020-21), proposed by Department of Food & Public Distribution during these years and budgetary provision made in RE 2019-20 & BE 2020-21.

(ii) **Capital Infusion in Public Sector Banks:** Capital to the extent of ₹80,000 crore in 2017-18 and ₹ 1,06,000 crore in 2018-19 was infused for Recapitalization of Public Sector Banks to enable them to maintain their Regulatory Capital, Growth Capital and Prompt Corrective Action (PCA) at desirable levels. For this purpose, a provision of ₹ 70,000 crore has also been made available in the 2019-20. Currently, the capital infusion is made through issuance of GoI special Securities carrying a fixed coupon. In the current Financial Year, so far ₹ 64,612 crore has been infused as Government's fresh capital.

(iii) Statement of liability on annuity projects is given in Part-B of the Receipt Budget 2020-21.

**Annex to Part B of Budget Speech****Direct Tax Proposals:****1. Tax Incentives**

1.1 Relief in personal income-tax and simplification of taxation: In order to provide relief and simplify the taxation regime, it is proposed to provide an option to individual and Hindu undivided family to be taxed at following lower rates if they do not avail specified exemption/deductions:

<b>Total Income (Rs)</b>	<b>Rate (%)</b>
Upto 2,50,000	Nil
From 2,50,001 to 5,00,000	5
From 5,00,001 to 7,50,000	10
From 7,50,001 to 10,00,000	15
From 10,00,001 to 12,50,000	20
From 12,50,001 to 15,00,000	25
Above 15,00,000	30

Surcharge and cess shall be continued to be levied at the existing rates.

1.2 Relief and simplification for co-operative societies: In order to provide relief and simplify the taxation regime, it is proposed to provide an option to cooperative societies to be taxed at 22% plus 10% surcharge plus 4% cess, if they do not avail certain specified deduction/exemption. Further, it is also proposed to exempt these cooperative societies from Alternative Minimum Tax (AMT).

1.3 Tax concession for foreign investments: In order to promote investment of sovereign wealth fund, including the wholly owned subsidiary of Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), it is proposed to grant tax exemption to interest, dividend and capital gains income of Sovereign Wealth Fund and wholly owned subsidiary of the ADIA subject to fulfilment of certain conditions, in respect of investment made in the infrastructure sector or other deserving notified sectors before 31<sup>st</sup> March, 2024 and with a minimum lock-in period of 3 years.

1.4 Removal of Dividend Distribution Tax: At present dividend is taxed in the hands of company distributing such dividend. This is found to be iniquitous. It is proposed to shift to classical system of taxing dividend in the hands of shareholders.

1.5 Incentives for IFSC, municipal bonds and offshore borrowing: The concessional rate of Tax Deductible at Source (TDS) at five per cent currently available under section 194LC and 194LD for borrowing from overseas is proposed to be extended for three years to 30<sup>th</sup> June 2023. Further, specified municipal bonds would also be eligible for such concession on overseas borrowing. It is also proposed to provide that the withholding tax rate shall be four per cent on fresh overseas borrowing on or after the 1st day of April, 2020 but before the 1st day of July, 2023 which is listed only on a recognised stock exchange located in any IFSC.

1.6 Incentives to Affordable Housing: Currently, an additional deduction up to one lakh fifty thousand rupees is allowed for interest paid on loans sanctioned up to 31<sup>st</sup> March, 2020 for purchase of an affordable house. In order to incentivise the purchase of affordable housing, it is proposed to extend the date of sanction of loan to 31<sup>st</sup> March, 2021. Hence, this deduction will also be available in respect of housing loans sanctioned by 31<sup>st</sup> March, 2021.

Further, in order to boost the supply of affordable houses in the country, a tax holiday is provided on the profits earned by developers of affordable housing project approved by 31<sup>st</sup> March, 2020. In order to promote the affordable housing projects, it is proposed to extend the date of approval of affordable housing projects for availing this tax holiday by one more year. Accordingly, developers of affordable housing projects approved by 31<sup>st</sup> March, 2021 can also avail of the tax holiday.

1.7 Concession to Real Estate sector: Currently, safe harbour of 5% is allowed for computation of income in respect of transaction of immovable property where the consideration is less than the circle rate. In order to boost housing sector, it is proposed to increase this safe harbour to 10%.

1.8 Incentives to start-up: In order to encourage the start-ups to employ highly talented employees at a relatively low salary by granting them Employee Stock Option Plan (ESOPs), it is proposed to defer the tax payment on these ESOPs granted by start-up to their employees by five years or till the employee leaves the company or when the said employee sells those shares, whichever is earliest.

Further, in order to extend benefit of tax holiday to larger start-ups, it is proposed to increase the turnover threshold for claiming tax holiday from existing Rs. 25 crore to Rs. 100 crores. Further, in order to address the concerns of start-ups which may not have adequate profit in initial years for availing this holiday, it is proposed to extend the period of eligibility for claim of 100% deduction from the existing 7 years to 10 years.

1.9 Allowing carry forward of losses or depreciation in certain amalgamations: It is proposed to provide that the amalgamated public sector banks and insurance companies shall be eligible to take the benefit of unabsorbed losses and depreciation of the amalgamating entities.

1.10 Widening the definition of “business trust”: In order to encourage unlisted Infrastructure Investment Trust (InvIT) or a Real Estate Investment Trust (REIT), it is proposed to extend the same taxation regime as available to listed InvITs and listed REIT to unlisted REIT and InvIT.

1.11 Exemption to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited: It is proposed to provide exemption to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) in respect of income accruing or arising as a result of an arrangement for replenishment of crude oil stored in its storage facility in pursuance to directions of the Central Government in this behalf subject to the condition of replenishment of crude oil within three years.

1.12 Concessional tax rate for electricity generation companies: In order to attract investment in the power sector, it is proposed to extend the concessional corporate tax rate of 15% provided by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 to new domestic companies that are engaged in the generation of electricity subject to the condition that they start generating electricity by 31<sup>st</sup> March, 2023.

## **2. Measures to provide tax certainty**

2.1 Widening the scope of Safe Harbour Rules and Advance Pricing Agreement: In order to provide tax certainty to taxpayers in the matter of attribution of profit to permanent establishment (PE), it is proposed to widen the scope of Advanced Pricing Agreement (APA) and Safe Harbour Regime (SHR), by providing that determination of attribution of profit to PE shall also be in the scope of SHR and APA.

2.2 Rationalisation of deduction to insurance companies: It is proposed to provide that expenses disallowed in the hands of insurance companies for late payment of statutory dues shall be allowed in the year of payment.

2.3 Reduction in rate of Tax Deduction at Source (TDS): In order to reduce litigation, it is proposed to reduce rate for TDS in case of fees for technical services (other than professional services) to two per cent from existing ten per cent in order to align the same with the rate of TDS on works contract.

2.4 Vivad se Vishwas Scheme: It is proposed to bring out a scheme for reducing the direct tax litigation. Taxpayers in whose case appeals are pending at any level can take the benefit from this scheme. Under the scheme, taxpayer would be required to pay only the amount of the disputed taxes and there will be complete waiver of interest and penalty provided they make payment by 31<sup>st</sup> March, 2020. For disputed penalty, interest and fee not connected with the disputed tax, the taxpayer would be required to pay only 25% of the same for settling the dispute. A tax payer shall be required to pay 110% of the disputed tax (the excess 10% shall be limited to the amount of related penalty and interest, if any) and 30% of penalty, interest and fee in case of payment after 31<sup>st</sup> March, 2020.

### **3. WIDENING AND DEEPENING OF TAX BASE**

3.1 TDS on E-commerce transactions: In order to widen and deepen the tax net, it is proposed to provide that e-commerce operator shall deduct TDS on all payments or credits to e-commerce participants at the rate of 1% in PAN/Aadhaar cases and 5% in non-PAN/Aadhaar cases. In order to provide relief to small businessman, it is proposed to provide exemption to an individual and HUF who receives less than Rs. 5 lakh and furnishes PAN/Aadhaar.

3.2 Enlarging the scope of TDS on interest: It is proposed to extend the TDS on interest paid by certain large co-operative societies whose gross receipts exceeds fifty crore rupees during the last financial year.

3.3 Widening the scope of TCS: It is proposed to provide for tax collection at source (TCS) on remittance under Liberalised Remittance Scheme of Reserve Bank of India exceeding seven lakh rupees in a year and on sale of overseas tour package. Further, TCS is also proposed on sale of goods in excess of fifty lakh rupee in a year by a seller whose turnover is more than 10 crore rupees.

3.4 Limit on exemption of Employer's contribution to certain funds: It is proposed to put an upper cap of seven lakh and fifty thousand rupees in a year on tax exempt employer's contribution in recognized provident fund, superannuation fund and NPS in the accounts of an employee.

### **4. IMPROVING EFFECTIVENESS OF TAX ADMINISTRATION**

4.1 Faceless appeal: In order to impart greater efficiency, transparency and accountability to the assessment process, a new faceless assessment scheme has already been introduced. In order to ensure that the reforms initiated by the Income Tax Department to eliminate human interface from the system reach the next level, it is proposed to provide enabling power for launching of Faceless appeal on the lines of Faceless assessment.

4.2 Widening the scope of Dispute Resolution Panel (DRP): It is proposed to widen the scope of references to DRP by including all non-residents as eligible assessee and to clarify that all variation which are prejudicial to the assessee shall be within the scope of DRP.

4.3 Taxpayer's Charter: With the objective of enhancing the efficiency of the delivery system of the Income Tax Department, it is proposed to provide that the CBDT shall adopt a Taxpayer's Charter and issue necessary direction for the implementation of the Charter.

4.4 Modification in the scope of faceless assessment: It is proposed to widen the scope of faceless assessment scheme to cover those cases in which assessment is being completed *ex-parte*.

## **5. EASE OF COMPLIANCE**

5.1 Raising of limit for tax audit: In order to help small and medium enterprises, it is proposed to raise the turnover threshold for compulsory tax audit from existing Rs. 1 crore to Rs. 5 crore in a case where cash receipt is not more than 5% of total receipt and cash payment is not more than 5% of total payment. Further, in order to reduce the compliance cost, it is also proposed to provide that tax audit report to be filed a month before the due date of filing income-tax return. Accordingly, the said due date for filing of income-tax returns is proposed to be changed from 30<sup>th</sup> September to 31<sup>st</sup> October of the relevant assessment year so that there is no change in the date of finalisation of tax audit.

5.2 Exempting non-resident from filing of Income-tax return on certain conditions: In order to reduce compliance burden of non-residents, it is proposed to exempt them from filing income-tax return on their income of the nature of royalty or fee for technical services, if tax has been deducted at the rate given in section 115A.

## **6. RATIONALISATION OF PROVISIONS OF THE INCOME-TAX ACT, 1961**

6.1 It is proposed to withdraw the exemption on certain perquisites and allowances provided to Chairman and members of Union Public Service Commission and to Chief Election Commissioner and Election Commissioners.

6.2 It is proposed to rationalise the definition of 'taxable commodities transactions' for the purposes of levy of Commodity Transaction Tax.

6.3 It is proposed to enable the Central Government for notifying scheme for levying penalty in a faceless manner.

6.4 To increase transparency in survey operation, it is proposed to provide that if the survey is not based on information provided by prescribed authority, then approval of Commissioner or Principal Commissioner of Income-tax is required.

6.5 It is proposed to provide that Income Tax Appellate Tribunal can grant stay of demand only if the taxpayer has either paid twenty per cent of amount of demand or have provided security for an equal amount.

6.6 It is proposed to reduce the time of stay in India from 182 days to 120 days for an Indian citizen or person of Indian origin to become resident in India. Consequently, it is proposed to relax the provision of "resident but not ordinarily resident" so that a resident who has been non-resident in seven out of ten previous years would be resident but not ordinarily resident. It is also proposed to provide that an Indian citizen who is not liable to tax anywhere would be deemed to be resident in India.

6.7 It is proposed to amend the definition of "work" for the purpose of TDS under section 194C to provide that in a contract manufacturing, the raw material provided by the assessee or its associate shall fall within the purview of the 'work' under section 194C.

6.8 To discourage taxpayers to manipulate their books of accounts by recording false entries including fake invoices to claim wrong input credit in GST, it is proposed to provide for penalty for these malpractices.

6.9 It is proposed to amend the provision allowing India to enter into Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) with other countries or territories or association, to align with the new preamble mandated by Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (commonly referred to as MLI), as India has already ratified MLI.

6.10 It is proposed to defer the enactment of Significant Economic Presence (SEP) to Financial Year 2021-22 as G-20 OECD report on digital economy is expected by that time. It is also proposed to provide for source rule for revenue from advertisement targeted to India customers and revenue from sale of Indian sourced data.

6.11 It is proposed to align exemption from the provision of indirect transfer to Foreign Portfolio Investors in line with new SEBI FPI regulations. It is also proposed to rationalise the definition of royalty.

6.12 It is proposed to rationalise the provisions of section 115BAA and section 115BAB to provide that any domestic company (both existing as well as new) opting for concessional tax regime will not be allowed to claim any deduction under Chapter VI-A of the Act except deductions specifically allowed under said sections.

6.13 The conditions for setting up of offshore fund are proposed to be rationalised so as to facilitate setting up of fund management activity in India.

6.14 It is proposed to clarify that in case of a capital asset, being land or building or both, the fair market value of such an asset on 1st day of April, 2001 shall not exceed the stamp duty value of such asset as on 1st day of April, 2001, where such stamp duty value is available.

6.15 It is proposed to rationalise the process of registration in the case of trusts, institutions, funds, university, hospital etc. and approval in the case of association, university, college, institution or company etc. It is also proposed to provide filing of statement of donation by donee so that the deduction claimed by the donor in its tax return can be pre-filled.

6.16 It is proposed to rationalise the provision regarding uploading of Form 26AS so as to include all the prescribed information.

6.17 It is proposed to rationalise the provisions relating to cost of acquisition and period of holding with respect to segregated portfolios to provide clarity to taxpayers holding such portfolios.

6.18 It is proposed to authorise Board to prescribe person who can verify the return of income in the cases of a company and a limited liability partnership. It is also proposed to authorise Board to prescribe person who can appear as an authorised representatives. This will help companies under Insolvency proceedings and in liquidation. It is also proposed to align the due date of Partner and Firm.

6.19 In order to facilitate opting for new concessional tax regime by the domestic companies, it is proposed to rationalise the provisions of section 35AD so as to provide an option for claiming deduction under section 35AD.

6.20 In order to rationalise the provisions of section 94B, it is proposed to exclude payment of interest to a branch of non-resident bank in India from interest deductibility rule under section 94B.

**Annex to Part B of Budget Speech****Indirect Tax Proposals:****A. Legislative Changes in Customs:****1. Major Amendments in the Customs Act, 1962:**

<b>S. No.</b>	<b>Amendment</b>
<b>A</b>	<b>For improving compliance</b>
1.	A new Chapter VAA (a new section 28DA) is being incorporated in the Customs Act to provide enabling provision for administering the preferential tariff treatment regime under Trade Agreements. The proposed new section seeks to specifically provide for certain obligations on importer and prescribe for time bound verification from exporting country in case of doubt. Pending verification preferential tariff treatment shall be suspended and goods shall be cleared only on furnishing security equal to differential duty. In certain cases, the preferential tariff treatment may be denied without further verification.
<b>B</b>	<b>For reducing litigation</b>
1.	An explanation is being inserted in section 28 to explicitly clarify that any notice issued under the said section, prior to the enactment of the Finance Act, 2018, shall continue to be governed by the section 28 as it existed before the said enactment, notwithstanding order of any Appellate Tribunal, Court or any other law to the contrary.
<b>C</b>	<b>Other enabling provisions</b>
1.	Clause (f) of the section 11(2) empowers the Central Government, for prevention of injury to the economy of the country by the uncontrolled import or export of gold or silver, to prohibit their import or export. This clause is being amended to include “any other goods” (in addition to gold and silver) in its ambit.
2.	A new section (section 51B) is being incorporated to provide for creation of an Electronic Duty Credit Ledger in the customs system. This will enable duty credit in lieu of duty remission to be given in respect of exports or other such benefit in electronic form for its usage, transfer etc. In this regard, enabling provisions for issuance of suitable regulations are also being inserted in section 157(2) of the Customs Act, 1962.  The provisions for recovery of duties provided under section 28AAA of Customs Act, 1962 are also being expanded to include such electronic credit of duties.

**2. Amendments to the Customs Tariff Act, 1975:**

<b>S. No.</b>	<b>Amendment</b>
<b>A</b>	<b>Amendment in the Customs Tariff Act, 1975</b>
1.	Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, which provided for imposition of safeguard duty as a trade remedy against surge in imports of a commodity, is being amended to make provisions for application of other safeguard measures such as Tariff Rate Quota and other safeguard measure as the Central Government may deem necessary to protect the domestic industry from injury due to significant surge in imports.
<b>B</b>	<b>Amendment in the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975</b>
1.	First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 is being amended to: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Create new tariff item 8414 51 50 for “Wall fans”. The tariff rate for this item is 20% and BCD on wall fans is being increased from 7.5% to 20%</li> <li>(ii) Create new tariff item 8529 90 30 for “Open Cell of television set”. The tariff rate for this item is 15%. However, these items will continue at ‘Nil’ BCD.</li> <li>(iii) Create tariff items 8541 40 11 for “Solar Cells, not assembled” and tariff item 8541 40 12 for “Solar Cells assembled in modules or made up into panels”. The tariff rate for these items is 20%. However, these items will continue at ‘Nil’ BCD.</li> </ul>

**3. Amendment in Countervailing Duty Rules and Anti-Dumping Duty Rules:**

These rules provide for manner and procedure for investigation into cases of imports of subsidized goods and cases of dumping of goods, respectively, that cause injury to domestic industry. Following amendments are being made in these rules:

<b>S. No.</b>	<b>Rules</b>	<b>Amendment</b>
1	Anti-Dumping Rules	Changes are being made in the Rules to strengthen the anti-circumvention measures by making them more comprehensive and wider in scope to take care of all types of circumventions of antidumping duty in line with best international practice. Certain other changes are being made in these Rules for bringing clarity in the scope of these rules.
2	Countervailing Duty Rules	At present, there is no provision for investigation in case of circumvention of countervailing duties. A provision is being incorporated in the Countervailing Duty Rules to enable investigation into case of circumvention of countervailing duty for enabling imposition of such duty. Certain other changes are being made for bringing clarity in the Rules.



**B. Review of Customs duty exemption for certain imported goods:**

1. Customs exemption have been reviewed to weed out such entries that are redundant, outdated or have outlived their utility. On such review, 80 exemptions are being withdrawn by making suitable amendment/rescission of relevant notifications. The exemptions being pruned on review, inter-alia, include withdrawal of exemption/concessional rates on the following goods, namely:

S. No.	Category of goods	Specific items
1.	<b>Agro and animal based products</b>	Tuna bait, skimmed milk and certain milk products, sugar beet seeds, raw sugar, certain alcoholic beverages, whey and isolated soya protein, soya fibre, etc.
2.	<b>Items of Metal</b>	a. Lead bars, rods and wire b. Zinc tubes, pipes and tubes c. Tin plates, sheets and strips
3.	<b>Machinery</b>	Machinery imported for use in certain projects such as specified electricity generation projects, specified Metro projects, certain other specified purposes; Specified goods required for construction of roads
4.	<b>Electronic items</b>	Copper and articles thereof used in manufacturing of specified electronic items; Parts for manufacture of printers, CD Writers, MP3 or MP4 or MPEG 4 players, pre-recorded cassettes, audio cassettes, colour television tubes, etc.
5.	<b>Miscellaneous</b>	a. Peanut butter, preserved potatoes b. Instant print film, exposed cinematographic films c. A few redundant and outdated customs duty exemptions are being withdrawn. Further, a few exemptions are being re-aligned for consistency.

**C. Changes in Customs duty for creating a level playing field for MSME and promoting MAKE IN INDIA:****1. Level playing field for domestic producers:**

Customs duty is being increased on the following goods:

S. No.	Category of goods	Specific items	Rate of Duty	
			From	To
1.	<b>Household goods and appliances</b>	Tableware and kitchenware of porcelain or china, ceramic, clay, iron, steel, copper and aluminium, glassware, padlocks, brooms, hand-sieves, combs, vacuum flasks, etc.	10%	20%

2.	<b>Electrical Appliances</b>	Fans, food grinders/mixers, shavers and hair removing appliances, water heaters, hair/hand drying apparatus, ovens, cookers, toasters, coffee/tea makers, insect repellents, heaters, irons, etc.	10%	20%
3.	<b>Footwear</b>	a. Footwear b. Parts of footwear	25% 15%	35% 20%
4.	<b>Furniture goods</b>	Seats, articles of bedding including mattresses, lamps, lighting, illuminated signs, and other articles of furniture	20%	25%
5.	<b>Stationery items</b>	Filing cabinets, paper trays, binders, clips, staples, sign-plates, name plates, numbers and symbols etc. made from base metal	10%	20%
6.	<b>Toys</b>	Tricycles, scooters, scale models, dolls, etc.	20%	60%
7.	<b>Machinery</b>	a. Specified goods used in high voltage power transmission project	5%	7.5%
		b. Railway carriage fans	7.5%	10%
		c. Compressors of refrigerators and air conditioners	10%	12.5%
		d. Commercial freezers	7.5%	15%
		e. Welding and plasma cutting machine	7.5%	10%
		f. Rotary tillers/weeder	2.5%	7.5%
8.	<b>Other miscellaneous items</b>	a. Glass beads b. Artificial flowers c. Bells, gongs, statuettes, trophies and like, statuettes, ornaments, photograph, frames, mirrors etc. of base metal.	10%	20%

**2. Changes in Customs duty to promote MAKE IN INDIA under Phased Manufacturing Programme (PMP) for Electric Vehicles and Cellular Mobile Phones:**

a.	Changes in customs duty under Phased Manufacturing Programme for Electric Vehicles	Rate of Duty	
		From	To
1.	Completely Built Units of Bus and Trucks (with effect from 01.04.2020)	25%	40%
2.	Semi Knocked Down (SKD) units of bus, trucks and two wheelers (with effect from 01.04.2020)	15%	25%
3.	Semi Knocked Down (SKD) units of passenger vehicles and three wheelers (with effect from 01.04.2020)	15%	30%
4.	Completely Knocked Down (CKD) units of passenger vehicles, three wheelers, two wheelers, bus and trucks (with effect from 01.04.2020)	10%	15%
b.	<b>Changes in customs duty under Phased Manufacturing Programme for Cellular Mobile Phones</b>		
	1. PCBA of Mobile phones (with effect from 01.04.2020)	10%	20%
	2. Vibrator/Ringer of Mobile phones (with effect from 01.04.2020)	Nil	10%
	3. Display Panel and Touch Assembly (with effect from 01.10.2020)	Nil	10%

**3. Changes in Customs duty to promote MAKE IN INDIA in Electronics sector:**

S. No.	Specific Items	Rate of Duty	
		From	To
1.	Motors like Single Phase AC motors, Stepper motors, Wiper Motors etc.	7.5%	10%
2.	Specified chargers and power adapters	Applicable Rate	20%
3.	Fingerprint readers for use in cellular mobile phones	Nil	15%
4.	Earphones and headphones	Applicable Rate	15%

**4. Reduction in Customs duty on raw materials and inputs imported by Domestic Manufacturers:**

S. No.	Category of Inputs/ Raw materials	Specific Items	Rate of duty	
			From	To
1.	<b>Fuels, Chemicals and Plastics</b>	Very low sulphur fuel oil meeting ISO 8217:2017 RMG380 Viscosity in 220-400 CST standards/Marine Fuel 0.5% (FO)	10%	Nil
		Calcined Petroleum Coke	10%	7.5%
		Calendared plastic sheets used in manufacturing of smart cards	10%	5%
		Polyester Liquid Crystal Polymers for use in manufacture of connectors	7.5%	Nil
2.	<b>Precious Metals</b>	Platinum or Palladium used in manufacture of: a) Colloidal precious metals, inorganic or organic compounds of precious metal, amalgams of precious metals b) Catalyst with precious metal or precious metal compounds as the active substance	12.5%	7.5%
		Spent Catalyst or Ash containing precious metal, subject to specified conditions	12.5%	11.85 %
3.	<b>Machinery and Electronic Goods</b>	Following parts of Microphone for use in manufacture of Microphone namely, a) microphone cartridge b) microphone holder c) microphone grill d) microphone body	10%	Nil
		Micro-fuse base, sub-miniature fuse base, Micro-fuse Cover and sub-miniature fuse cover for use in manufacture of micro fuse and sub-miniature fuse.	7.5%	Nil
4.	<b>Sports Goods</b>	Willow is being included in the list of items allowed duty free import up to 3% of FOB value of sports goods exported in the preceding financial year	Applicable Rate	Nil
5.	<b>Newsprint</b>	a) Newsprint, when imported by importer registered with Registrar of Newspapers, India. b) Uncoated paper used for printing newspaper, when imported by importer registered with Registrar of Newspapers, India. c) Lightweight coated paper used for printing magazines subject to actual user condition.	10%	5%

**5. Other changes in Customs duty:**

S. No.	Category of Goods	Specific Items	Rate of Duty	
			From	To
1.	<b>Food processing</b>	Walnuts, shelled	30%	100%
2.	<b>Chemicals and Plastics</b>	Colloidal precious metals, inorganic or organic compounds of precious metal, amalgams of precious metals	7.5%	10%
		Butyl Acrylate	5%	7.5%
		Other prepared binders for foundry moulds or cores; Chemical products and preparations of the chemical or allied industries	10%	17.5%
3.	<b>Auto and auto parts</b>	Catalytic converter	10%	15%
		Noble metal solutions and noble metal compounds used in manufacture of catalytic converter and its parts	5%	10%
		Platinum or Palladium used in manufacturing of catalytic converter and its parts	5%	Applicable Rate
		Parts and other specified inputs for manufacture of catalytic converters.	5%	7.5%
		Completely Built Units (CBUs) of commercial vehicles (other than electric vehicles) (with effect from 01.04.2020)	30%	40%

**D Imposition of Health cess on specified medical equipment:**

Health Cess at the rate of 5% is proposed to be imposed on the import of medical devices. This Health Cess shall be a duty of Customs. Health Cess shall not apply to medical devices which are exempt from BCD. Further, inputs/parts used in the manufacture of medical devices shall also be exempt from Health Cess. The proceeds of Health Cess shall be used for financing the health infrastructure and services.

**E. Revocation of Anti-Dumping Duty on Purified Terephthalic Acid:**

Revocation of Anti-dumping duty on import of Purified Terephthalic Acid originating in or exported from: -

1. South Korea and Thailand imposed vide notification No. 28/2019-Customs (ADD) dated 24.7.2019
2. China, Iran, Indonesia, Malaysia and Taiwan imposed vide notification No. 28/2016-Customs (ADD) dated 5.7.2016

**F. Increase in National Calamity Contingent Duty (NCCD) on Cigarettes and tobacco products:**

National Calamity Contingent Duty is levied as a duty of excise on certain manufactured goods specified under the Seventh Schedule of Finance Act, 2001. NCCD is being proposed to be increased on tobacco products (except bidi) as detailed below:

1. On cigarettes, NCCD is being increased ranging from Rs. 200 – 735 per thousand, depending upon length of cigarette and on filter/non-filter basis.
2. On smoking mixtures for pipes and cigarettes, NCCD is being increased from 45% to 60%.
3. On other forms of smoking tobacco (other than smoking mixtures for pipes and cigarettes) and forms of chewing tobacco, NCCD is being increased from 10% to 25%.
4. NCCD on Bidis remains unchanged.

**G. Proposals involving change in provisions of Central Goods and Services Tax Act, 2017:**

S. No.	Amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 / Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 / Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017
<b>A</b>	<b>For facilitating trade or consumer</b>
1	Sub-section (4) of the section 16 of the CGST Act is being amended to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of the underlying invoice for purposes of availing input tax credit.
2	Clause (c) of sub-section (1) of section 29 of the CGST Act is being amended to provide for cancellation of registration which has been obtained voluntarily under sub-section (3) of section 25.
3	A proviso to sub-section (1) of section 30 of the CGST Act is being inserted to empower the jurisdictional tax authorities to extend the date for application of revocation of cancellation of registration in deserving cases.
4	Section 51 of the CGST Act is being amended to remove the requirement of issuance of TDS certificate by the deductor; and to omit the corresponding provision of late fees for delay in issuance of TDS certificate.
5	Section 168 of the CGST Act is being amended to make provisions for enabling the jurisdictional commissioner to exercise powers under sub-section (5) of section 66 and second proviso to sub-section (1) of section 143.

<b>B</b>	<b>For improving compliance</b>
1.	Section 10 of the CGST Act is being amended, so as to exclude from the ambit of the Composition scheme certain categories of taxable persons, engaged in making- (i) supply of services not leviable to tax under the CGST Act, or (ii) inter-State outward supply of services, or (iii) outward supply of services through an e-Commerce operator.
2.	Section 122 of the CGST Act is being amended by inserting a new sub-section to make the beneficiary of the transactions of passing on or availing fraudulent Input Tax Credit liable for penalty similar to the penalty leviable on the person who commits such specified offences.
3.	Section 132 of the CGST Act is being amended to make the offence of fraudulent availment of input tax credit without an invoice or bill a cognizable and non-bailable offence; and to make any person who commits, or causes the commission and retains the benefit of transactions arising out of specified offences liable for punishment.
<b>C</b>	<b>Other changes</b>
1.	The definition of “Union territory” in clause (114) of section 2 of the CGST Act is being amended to update the definition of Union territory in view of the bringing into force of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 and the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories), Act, 2019. Consequential changes are also being made in UTGST Act, 2017.
2.	Section 31 of the CGST Act is being amended to provide enabling provision to prescribe the manner of issuance of invoices in case of supply of taxable services.
3.	Section 109 of the CGST Act is being amended to bring the provision for Appellate Tribunal under the CGST Act in the Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh.
4.	Section 140 of the CGST Act is being amended with effect from 01.07.17, to prescribe the manner and time limit for taking transitional credit.
5.	Section 172 of the CGST Act is being amended to make provision for enabling issuance of removal of difficulties order for another 2 years, i.e. till five years from the date of commencement of the said Act. Similar changes are also being made in the IGST Act, 2017 (section 25), the UTGST Act, 2017 (section 26) and the GST (Compensation to States) Act, 2017 (section 14).

6.	Entries at 4(a) & 4(b) in Schedule II of the CGST Act is being amended with effect from 01.07.2017 to make provision for omission of supplies relating to transfer of business assets made without any consideration from Schedule II of the said Act.
----	--

The proposed changes in GST laws will come into effect from the date when the same will be notified, as far as possible, concurrently with the corresponding amendments to the similar Acts passed by the States & Union territories with legislature.

**H. Retrospective amendments to give effect to the recommendations of the GST Council:**

S. No.	Retrospective amendment in the Goods and Service Tax rate and refund provisions
1	Exemption from Central Tax, Union Territory Tax and Integrated Tax is being given on fishmeal [HS 2301], for the period 01.07.2017 to 30.09.2019. However, GST paid on supply of fishmeal during the period shall not be refunded.
2	Concessional 12% rate of Integrated Tax and 6% Central Tax and 6% Union Territory Tax during the period 01.07.2017 to 31.12.2018, on pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery of headings 8432, 8433, and 8436. However, GST paid at any other rate (higher than 12%) shall not be refunded.
3	The refund of accumulated credit of compensation cess on tobacco products arising out of inverted duty structure in Compensation Cess has been disallowed with effect from 1.10.2019 vide notification No. 3/2019-Compensation Cess (Rate) dated 30.9.2019. This notification is being given retrospective effect from 1.7.2017 onwards. Accordingly, no refund on account of inverted duty structure shall be admissible on tobacco products for any period.

**For further details of the budget proposals, the Explanatory Memorandum and other relevant budget documents may be referred to.**